असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

29 जून, 2022

सप्तदश विधान सभा **२९ जून, २०२२ ई०**

षष्ठम् सत्र **बुधवार, तिथि ०८ आषाढ़, १९४४(शक)**

(कार्यवाही प्रारंभ होने का समय-11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। अब प्रश्नोत्तर काल होगा । अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0-29(श्री ललित कुमार यादव,क्षेत्र सं0-82, दरभंगा ग्रामीण)

(अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न सं0-30(श्री अरूण शंकर प्रसाद,क्षेत्र सं0-33, खजौली

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में किये गये बेस लाइन सर्वे के आधार पर लक्षित 122.15 लाख परिवारों को व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय आइ0एच0एच0एल0 की सुलभता प्रदान की गयी है । साथ ही, भूमिहीन परिवारों विशेषत: अनुसूचित जाति/जनजाति, चलंत एवं अस्थायी आबादी को शौचालय की सुलभता प्रदान करने हेतु 9408 सामुदायिक स्वच्छता परिसर सी0एस0सी0 का निर्माण कराया गया है । नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 रिपोर्ट के संदर्भ में अवगत कराना है कि स्वच्छता आच्छादन की वास्तविक स्थिति के आकलन हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर आंतरिक स्वच्छता सर्वेक्षण कराये गये हैं । सर्वेक्षण से प्राप्त सूचना के आलोक में एवं जनसंख्या वृद्धि तथा नये परिवारों की संख्या में कालांतर में वृद्धि के दृष्टिगत लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण 2021-22 से 2024-25 के तहत किसी कारणवश छूटे हुए परिवार तथा नये परिवारों को व्यक्तिगत शौचालयों की सुलभता हेतु प्रावधान किये गये हैं । जिसके अन्तर्गत शत-प्रतिशत स्वच्छता आच्छादन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना का निर्माण कर व्यवहार परिवर्तन केंद्रित उत्प्रेरण के माध्यम से लाभुकों को शौचालय के निर्माण हेतु प्रेरित किया जायेगा । ज्ञातव्य है कि व्यवहार परिवर्तन एवं इसका स्थायित्व एक सतत् प्रक्रिया है ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : उत्तर संलग्न है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिहार में लोहिया स्वच्छता अभियान चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट स्वच्छता अभियान है, लेकिन आज बिहार देश में सबसे

पिछले पायदान पर है । नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे-5 रिपोर्ट के आधार पर दर्शाता है कि 38 परसेंट बिहार में लोगों के घर आज भी शौचालय विहीन है । इसका क्या कारण है कि बिहार देश का अग्रणी राज्य कई मामले में है बावजूद इसके हमलोग शौचालय के मामले में सबसे फिसड्डी हो गये हैं, कहीं न कहीं पदाधिकारियों की लापरवाही है और पदाधिकारी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जिसकी वजह से गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण नहीं हो रहा है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आगे कौन सा उपाय करके इसकी भरपाई आप करनेवाले हैं ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद जी का जो सवाल है वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है । यह स्वच्छता से जुड़ा हुआ सवाल है । माननीय सदस्य जो प्रश्न उठा रहे हैं कि बिहार में सबसे नीचे पायदान पर स्वच्छता के क्षेत्र में काम हुआ है । महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि ये जो बेस लाइन सर्वे हुआ था-बेस लाइन सर्वे हुआ था 2012-13 में और बेस लाइन सर्वे के आधार पर 1 करोड़ 22 लाख 15 हजार परिवार व्यक्तिगत शौचालय से लाभान्वित सूची में शामिल हुए थे । उसमें जो शौचालय का निर्माण हमलोगों ने कराया है 2012-13 में आच्छादित परिवार की संख्या 39 प्रतिशत पायी गयी और शौचालय विहीन जो परिवार थे यानी हमलोगों ने 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा घरों में शौचालय का निर्माण करा दिया और 1 करोड़ 62 लाख परिवार का हमलोगों ने सर्वे कराया उसके हिसाब से यह किया गया है । आच्छादित परिवारों की संख्या 40 लाख पायी गयी है जिसे विलोपित कर 1 करोड़ 22 लाख 15 हजार परिवार को लोहिया स्वच्छता अभियान के प्रथम चरण अन्तर्गत व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से व्यक्तिगत शौचालय की सुलभता प्रदान की गयी है और जो परिवार शौचालय से अभी वंचित हैं उनके लिए भी राज्य में लगभग 9 हजार से ज्यादा सामुदायिक शौचालय का हमने निर्माण कराया है । अभी आवश्यकता और है जिनके पास घर के अलावे शौचालय की जमीन नहीं है उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, जमीन उपलब्ध करा रहे हैं और जमीन उपलब्ध कराकर उनके लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा रहे हैं । इस प्रकार से जो कमी है उसको हमलोग दूर करेंगे । महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है अगर इनके इलाके में या इनके जानकारी में कहीं पर सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है तो माननीय सदस्य बतायेंगे तो उनके अनुसार हम वहां पर भी कार्रवाई करेंगे । इस प्रकार से हम जो छूटे हुए परिवार हैं उनको जोड़ने की दिशा में भी हम काम शुरू किये हुए हैं और जहां-जहां जिनके घरों में शौचालय नहीं है उनको भी सूचीबद्ध करके उनके घरों में भी शौचालय निर्माण करायेंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे इलाके की बात कर रहे हैं और मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ । इस मामले में कहीं न कहीं पूरे बिहार का नाक

कट रहा है । महोदय, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 एन0एफ0एच0एस0 2019 और 2021 के बीच 28 राज्यों और 8 केन्द्रशासित प्रदेशों के देश के 707 जिलों के लगभग 6.37 लाख सैंपल घरों में आयोजित किया गया था और बिहार में 35834 घरों में यह सर्वे किया गया जिसमें 42483 महिलाएं और 48097 पुरूष इसमें शामिल हुआ और उस सर्वे का रिपोर्ट है कि बिहार में केवल 68 फीसदी घरों में शौचालय है और 38 फीसदी घर में शौचालय नहीं है । देश के सबसे निचले पायदान पर हमलोग हैं, हमसे थोड़ा ज्यादा झारखण्ड का है 70 फीसदी वहां 30 परसेंट घरों में शौचालय नहीं है । हमलोग इस स्थिति में कैसे आ गये हैं ? कितना शौचालय में भ्रष्टाचार हो रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक क्या है ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : क्या माननीय मंत्री जी कोई कमिटी गठित करके और विशेष जॉच करायेंगे कि कैसे हम कम गये जबकि उन्होंने बताया है कि 122.15 लाख परिवारों को व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से हमने दिया तो आखिर वह गया कहां ? या तो डुप्लीकेसी हो गयी या एक ही शौचालय पर दस लोग अपना पैसा निकाल लिये या पदाधिकारियों की इस काम में रूचि नहीं है ।

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ? पूरक संक्षिप्त में पूछिए ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : इन सारे मामले में इन्होंने कोई समीक्षात्मक बैठक की है कि ये आखिर क्यों- ये हेल्थ सर्वे आने के बाद माननीय मंत्री जी द्वारा विभाग के अधिकारियों के साथ कोई समीक्षा किया गया कि क्यों पीछे हैं ?

श्री श्रवण कुमार,मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है विभाग के द्वारा और 40 लाख परिवार बिहार में ऐसे हैं जो डबल लेने के चक्कर में थे उनको रोका गया तो अगर समीक्षा नहीं करते तो 40 लाख परिवार कैसे रूकते, उनको रोका गया है और जहां तक शौचालय निर्माण का सवाल है कि जो छूटे हुए परिवार हैं उनके बारे में हमने कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग ज्यादातर छूटे हुए हैं चूंकि उनके पास जमीन नहीं है तो उनके लिए सरकार जमीन भी बंदोबस्त कर रही है और हमने कहा कि 9 हजार से ज्यादा सामुदायिक शौचालय का निर्माण हमने कराया है और भी जहां आवश्यकता है वहां पर हम करायेंगे और बिना शौचालय का कोई नहीं रहे उसके लिए पूरी सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है । मैं दूसरी बात आपसे कहना चाहता हूँ जैसे परिवार में बंटवारा हो गया तो कल तक उसके पास शौचालय था और आज नहीं है तो उसका भी हम सर्वे करा रहे हैं और उस आधार पर बिना शौचालय का कोई नहीं रहे । अब तो स्वच्छता का दूसरा काम भी शुरू हो गया है महोदय तो मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य जिस बात के लिए चिंतित हैं उनकी चिंता जल्द ही हमलोग दूर कर देंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अब मैं केवल एक बात जानना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष : लास्ट है आपका पूरक ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अंतिम है, तीसरा पूरक है मैं जान रहा हूँ । मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि 38 परसेंट जो लोग बच गये हैं उनको कितने दिनों में शौचालय से आच्छादित कर देंगे । इसकी कोई समय सीमा होनी चाहिए और कब-कब इन्होंने समीक्षा बैठक किया है उसकी अगर कोई तिथि माननीय मंत्री महोदय के पास है तो बता दें कि इसके लिए इन्होंने कब-कब समीक्षा बैठक की है ?

टर्न-2/पुलकित/29.06.2022

अध्यक्ष : मंत्री जी बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : महोदय, अभी डेट तो हम एक्जेक्ट नहीं बता सकते हैं, लेकिन पिछले ही महीने में हमने पूरे बिहार के उप विकास आयुक्त के साथ सचिवालय में बैठक की थी और हमने निर्देशित किया था कि बिना शौचालय के कोई नहीं रहे । 77.8 प्रतिशत लोग शौचालय से आच्छादित है और हम यह महसूस करते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में ज्यादा शौचालयों की कमी हैं । लेकिन हमने 9000 शौचालय बनाये हैं और भी हमलोग शौचालयों को तेजी से बनाने का काम करेंगे और माननीय सदस्य की जो चिंता है उसको जल्द से जल्द हमलोग दूर करेंगे ।

अध्यक्ष : रत्नेश सादा जी क्या है ?

श्री रत्नेश सादा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भाई अरूण शंकर जी को कहना चाहूंगा इन्होंने कहा कि बिहार की नाक कट रही है । सरकार में तो शामिल ये भी हैं । इनसे...

अध्यक्ष : अब ये विषय नहीं है । आपका पूरक है तो पूछिये, नहीं तो बैठिये । माननीय मंत्री जी से पूरक है तो पूछिये ?

श्री रत्नेश सादा : महोदय, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि 12,000/- रुपये में शौचालय नहीं बनता है ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री रत्नेश सादा : इसमें सरकार, माननीय मंत्री पैसा बढ़ायें ताकि गरीब-गुरबा का शौचालय निर्माण हो सके ।

अध्यक्ष : ठीक है । आपका क्या है विनय जी ? बोलिये ।

श्री विनय बिहारी : अध्यक्ष महोदय, हमारे लौरिया प्रखण्ड में एक पंचायत है धोबनी । उसमें 1800 शौचालयों का पैसा गया और सिर्फ 300 शौचालय ही बने हैं । जब जांच के लिए कहा गया तो जांच में एक टेक्निकल प्रॉब्लम है । प्रॉब्लम यह है कि पदनाम पर केस हो, पदनाम के आधार पर होता है तो कोई भी ऑफिसर काम करता है । मान लीजिये, अभी कोई बी0डी0ओ0 हैं और उस बी0डी0ओ0 की बदली हो गई तो उसकी जगह पर जब कोई दूसरा बी0डी0ओ0 आयेगा तो वही बी0डी0ओ0 जहां बदली हुई वहां से कोर्ट में आता है इसलिए आग्रह है कि हमारे धोबनी पंचायत जो लौरिया प्रखण्ड की है, उसकी जांच हो ताकि पता चले । मैंने इसके विषय में जिलाधिकारी को भी दिया हुआ है और क्या हुआ है एक बार...

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है और भी माननीय सदस्यों के प्रश्न हैं ।

श्री विनय बिहारी : एक बार शौचालय पर हरे रंग से पेंट किया गया तो उसका पैसा गया । फिर पीले रंग से....

अध्यक्ष : आपका पूरक क्या है ?

श्री विनय बिहारी : मैं चाहता हूं कि जांच हो ।

अध्यक्ष : आप जांच कराना चाहते हैं ? माननीय मंत्री जी संज्ञान में ले लीजिये...

श्री विनय बिहारी : और जांच नहीं होगी तो बात का पता नहीं चलेगा ।

अध्यक्ष : और जांच से अवगत करायेंगे ।

श्री विनय बिहारी : जांच ऑफिसर के नाम पर न हो ।

अध्यक्ष : इस संबंध में आप लिखकर के दीजिये, मंत्री जी संज्ञान में लेकर जांच करवा देंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम तो लगातार जांच कराते रहते हैं । अगर जांच नहीं कराते तो इन 40 लाख का डबल पेंमेंट हो जाता । इसको घपला और घोटाला लोग नहीं कहते । 40 लाख जो पैसा लेने के चक्कर में लोग थे, उसकी जांच की गयी तभी तो रोका गया और भी माननीय सदस्यों से ऐसी कोई सूचना प्राप्त होगी तो उसकी जांच करायेंगे और जांच कराकर कार्रवाई भी करेंगे ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय....

अध्यक्ष : अब हो गया । एक ही प्रश्न पर नहीं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा विषय है ।

अध्यक्ष : श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, मेरा छोटा सा विषय है । आपका आदेश होगा तो हम पूछ लेते ।

अध्यक्ष : बहुत विस्तार से मंत्री जी ने जवाब दिया है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : महोदय, एकदम छोटा सा है । आपका संरक्षण मिले तो हम पूछ लें ।

अध्यक्ष : पूछिये ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से हम जानना चाहते हैं कि शौचालय विहीन जो परिवार बचे हुए हैं, वैसे परिवार का सर्वेक्षण कराने का विचार माननीय मंत्री जी रखते हैं तो कब तक ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : माननीय सदस्य का जो प्रश्न है उसका जवाब तो हम पहले दे चुके हैं कि सर्वेक्षण का काम तो हमारा चल रहा है और अगर माननीय सदस्य के संज्ञान में कोई ऐसे व्यक्ति छूट रहे हैं तो वह लिखकर दे देंगे या हमको फोन से बता देंगे तो वह परिवार नहीं छूटेगा । सब के घरों में शौचालय का निर्माण कराना है, कोई वंचित नहीं रहेगा । हमने कहा कि अगर कोई शौचालय परिवार में सामूहिक में था और वह आज अलग हो गया । आज अलग हो गया तो तुरंत तो शौचालय नहीं बनेगा, उसकी जांच करायेंगे, सर्वे हो रहा है उसमें जोड़ेंगे और जोड़कर के उनके घरों में शौचालय निर्माण करायेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 31 (श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0- 09, सिकटा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 32 (श्री ऋषि कुमार, क्षेत्र सं0- 220, ओबरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 33 (श्री पवन कुमार जायसवाल, क्षेत्र सं0- 21, ढाका)

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- स्वीकारात्मक ।

2- आंशिक स्वीकारात्मक । बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 25 में ग्राम पंचायतों में, धारा-50 में पंचायत समिति में एवं धारा-77 में जिला परिषद् में स्थायी समिति के गठन का प्रावधान किया गया है । विभागीय पत्रांक-3545 दिनांक 04.06.2019, पत्रांक-4557 दिनांक 18.07.2019 एवं पत्रांक-1799 दिनांक 07.03.2022 के द्वारा क्रमशः ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद् में स्थायी समितियों को प्रभावकारी बनाने हेतु सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को विस्तृत दिशा निर्देश संसूचित है । पंचायती राज विभाग के

तीनों निकायों में स्थायी समितियों की गठन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण कर ली गयी हैं ।

3- वस्तुस्थिति उपर्युक्त खंडों में स्पष्ट कर दी गयी है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जो जवाब है उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि पंचायती राज का चुनाव हुए इतने दिन हो गये हैं । मेरा प्रश्न है कि जिस प्रकार विधान सभा में स्टैंडिंग कमेटी है उसी प्रकार पंचायतों में भी ग्राम पंचायत में पंचायत समिति, जिला परिषद् में स्थायी समिति का गठन होना है और निर्वाचन के माध्यम से होना है । मेरा प्रश्न यह है कि अभी तक मात्र एक जिला परिषद् में, 13 पंचायत समिति में और कुछ पंचायतों में ही गठन हो पाया है। माननीय मंत्री जी का जवाब है कि लगभग पूरा कर लिया गया है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह होगा कि इस मामले में मैंने जो जानकारी दी है वह विभाग से जानकारी प्राप्त करके दी है । जिन पंचायतों ने पंचायत समितियों ने या जिला परिषद्ों ने गठन नहीं किया और इसमें अध्यक्ष, पंचायत समिति का कोई रोल नहीं है । ये गठन कराने की जिम्मेवारी उप विकास आयुक्त की है, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की है, कार्यपालक पदाधिकारी और पंचायत सचिव की है । इन पर कोई दायित्व निर्धारण करने का विचार मंत्री जी रखते हैं तो कब तक । कब तक राज्य में यह गठन हो पायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : महोदय, विभाग के द्वारा जो जवाब उपलब्ध कराया गया है उसके आधार पर 25 जिला परिषद में समिति का गठन किया गया है और 335 जगहों पर पंचायत समिति में गठन किया गया और 4,315 जगहों पर ग्राम पंचायत में किया गया । इसके लिए दो पत्र विभाग के द्वारा पहले भी जारी किये गये थे । डायरेक्टर के माध्यम से दिनांक- 07.03.2022 को और 28.02.2022 को कि आप कमेटी का गठन करके विभाग को इसकी जानकारी दें लेकिन माननीय सदस्य ने जो जानकारी दी है, उससे हम जरूर आश्वस्त करते हैं आपके माध्यम से कि हम यह निर्देश देंगे कि पन्द्रह दिनों में जो भी समिति का गठन निर्वाचन के तहत नहीं करेंगे, उनकी राशि को भी हम रोकने का काम करेंगे, काम आगे नहीं होगा ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्री जी से यह प्रश्न है....

अध्यक्ष : कितना सकारात्मक जवाब मंत्री जी ने दिया है ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा जवाब माननीय मंत्री जी का है उसी से मेरा पूरक है कि जिन जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों ने निर्वाचन के माध्यम से स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव नहीं किया । क्या

उनके गठन को रद्द करने का माननीय मंत्री जी विचार रखते हैं क्योंकि होना तो निर्वाचन से है और वहां तो चयन हुआ है ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

श्री सम्राट चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यदि संज्ञान में आयेगा कि कहीं चुनाव की प्रक्रिया नहीं की गयी है और वहां पर रिपोर्ट हमलोगों को गलत भेजी गई है तो जरूर कार्रवाई करेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव ।

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 34 (श्री कुमार कृष्ण मोहन उर्फ सुदय यादव, क्षेत्र सं0- 216, जहानाबाद)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 35 (श्री ललित कुमार यादव, क्षेत्र सं0- 82, दरभंगा ग्रामीण)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अल्पसूचित प्रश्न सं0- 36 (श्री भाई वीरेन्द्र, क्षेत्र सं0- 187, मनेर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, लोकतंत्र के जिस पवित्र मंदिर में हम बैठे हैं वह केवल राजनीति, प्रतिस्पर्धा का मंच नहीं है बल्कि 12 करोड़ जनमानस की इच्छाओं, भावनाओं और संभावनाओं का केन्द्र भी है । यह केवल विमर्श और विधान के निर्माण की जगह नहीं है बल्कि उज्ज्वल भविष्य के संधान की पीठ भी है । यह आचरण, मर्यादा और कर्त्तव्य निष्ठा को निर्धारित करने वाला न्यास भी है । शायद इसलिए हमारी हर छोटी-बड़ी गतिविधियों पर देश और दुनिया की बारीकी नजर होती है । हम जनमानस के असंतोष, हताशा और कुंठा के कारक के रूप में आलोचना और भर्त्सना के शिकार होते हैं तो वही राज्य-समाज में जो कुछ बेहतर होता है, उस बेहतरी का सेहरा भी हमारे सिर पर बांधा जाता है इसलिए हम विधायक कहे जाते हैं यानी विधि के अनुरूप समाचरण करने वाले, इसी भाव को व्यावहारिक रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए हमने उत्कृष्ट विधायक के चयन के प्रस्ताव पर सदन में चर्चा के लिए अपनी सहमति दी थी ।

माननीय सदस्यगण, आज प्रकृति की भी इच्छा है कि सभी माननीय सदस्य सदन के अंदर विमर्श करें, प्रश्न में भागीदारी करें । यहां बैठे हम सभी लोग एक क्षेत्र विशेष की जनता के प्रतिनिधि हैं । हमारे अलग-अलग मत हैं, विभिन्न

विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दलों से हमारी निष्ठायें जुड़ी हैं लेकिन इस सब से कहीं बढ़कर हमारी पहचान इस महान सदन के अंग के रूप में है ।

(क्रमशः)

टर्न–3/अभिनीत/29.06.2022

–क्रमशः–

अध्यक्ष : जब भी इस गौरवशाली मंदिर की पवित्रता और शुचिता पर प्रश्न उठता है तो हम सभी की व्यक्तिगत और सामूहिक प्रतिष्ठा पर आंच आती है । अतः हम सभी को गंभीरता से यह विचार करना होगा कि बिहार विधान सभा के इस महान सदन से जुड़ने भर से हमें जो प्रतिष्ठा और पहचान मिलती है उसके बदले में हम यहां की विरासत में क्या योगदान कर रहे हैं । हमारे विचार से हम सभी में यह भाव और बोध हमेशा सजग रहे । हमें एक निश्चित मापदंड, सुस्थापित पद्धति और प्रक्रिया अपनाते हुए पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रणाली के आधार पर अपने बीच से हर वर्ष एक सर्वश्रेष्ठ जनप्रतिनिधि को सम्मानित करते हुए जन सामान्य के बीच अपनी विधायिका को प्रतिष्ठित करना है । ये उत्कृष्ट विधायक किसी भी क्षेत्र, पार्टी या वर्ग से हों उनका सम्मान हो । ये हमारी सामूहिक प्रतिष्ठा के वाहक के रूप में जनमानस में जाने जायं । इससे न केवल जनता का विश्वास इस महान सदन के प्रति बढ़ेगा बल्कि राजकाज और राजनीति के प्रति उनकी उम्मीद और अभिरूचि जगेगी । शासन–प्रशासन में होने वाले विचलन पर रोक लगेगी । भयमुक्त और भ्रष्टाचार के विरूद्ध एक सकारात्मक माहौल बनेगा । इस प्रकार की निरंकुशता और अराजकता से मुक्त होने की जनाकांक्षाओं को बल मिलेगा । एक आग्रह और करेंगे कि कोई भी माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हुए सीधे कह देते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है यह ठीक नहीं है । पूरी प्रामाणिकता के साथ, गंभीरता के साथ आप इस शब्द का उपयोग करें तब इस शब्द पर सदन की गंभीरता बन जायेगी । हर प्रश्न पर अगर हम यह कह देंगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, यह कतई उचित नहीं है ।

माननीय सदस्यगण, आप सभी से यह आग्रह है कि नीति, निर्णय और नैतिकता के केंद्र बिन्दु इस महान सदन को हम अपनी तात्कालिक उपलब्धियों का साधन न बनने दें । विरोध और भर्त्सना के अखाड़े में न तब्दील होने दें । हमें यह याद रखना होगा कि इस सदन के भीतर हमारी हर छोटी–बड़ी गतिविधियां इतिहास और संदर्भ का विषय बनती हैं । यदि हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण चाहते हैं तो इस गौरवशाली सदन के इतिहास में किसी भी

प्रकार के अप्रिय अध्याय को जोड़ने के प्रयास से बचना होगा । हमें यह सोचकर आगे बढ़ना होगा कि हम सदन में विमर्श के लिए भागीदारी करें । अपने विषय को सदन में रखें, सदन के बाहर हमारे विषय प्रेस मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच एक नकारात्मक भाव दे सकता है लेकिन सदन में जो विमर्श होगा वही सकारात्मक भाव जनता के हित में और राष्ट्र के हित में होगा । आज बेतिया स्कूल के बच्चे भी सदन की कार्यवाही को देख रहे हैं । बहुत अच्छा कार्यक्रम इनलोगों ने किया था । अंत में मैं कहना चाहूंगा-

''वक्त ने माना हमारे बीच रख दीं दूरियां,
कोशिशें ये हों दिलों में रिश्ता जिंदा रहे ।
प्यार से सुलझाइये, हल गुत्थियां हो जायेंगी,
जब तलक हम हैं ये फलसफा जिंदा रहे ।
मेरी कविता, मेरे दोहे, गीत मेरे और गजल,
मैं रहूं या न रहूं मेरा कहा जिंदा रहे ।''

यही आपसे उम्मीद और आग्रह है । अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य श्री आबिदुर रहमान ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 232 (श्री आबिदुर रहमान, क्षेत्र सं0-49, अररिया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या- 233 (श्री आबिदुर रहमान, क्षेत्र सं0-49, अररिया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल । उत्तर संलग्न है पूरक पूछिए ।

शत-प्रतिशत प्रश्नों के जवाब आज भी आये हैं । मैं सरकार की सजगता को बधाई देता हूं और विधायकों की गंभीरता भी इसमें दिखाई पड़नी चाहिये । सभी सदस्य सदन में आकर, बहुत ही मेहनत से प्रश्नों के जवाब हमारे विधायिका और कार्यपालिका में बैठे लोग लाते हैं । सभी विधायकों से आग्रह है जो बाहर बैठे हैं, सदन के बाहर हैं इस प्रश्नोत्तर काल में भागीदारी करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 234 (श्री ललित नारायण मंडल, क्षेत्र सं0-157, सुल्तानगंज)

श्री संजय कुमार झा, मंत्री (लिखित उत्तर): 1- स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि भागलपुर जिला के सुल्तानगंज प्रखंड के अशियाचक पंचायत में मंझली गांव अवस्थित है ।

2- वस्तुस्थिति यह है कि गंगा नदी के बैक वाटर से सुरक्षा हेतु मंझली गांव के पश्चिम में स्थित रिंग बांध का निर्माण मनरेगा के तहत कराया गया है । इस रिंग बांध की ऊंचाई कम होने के कारण बरसात के दिनों में जब गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है तब बाढ़ का पानी मंझली गांव में प्रवेश कर जाता है ।

साथ ही, मंझली गांव के पश्चिम का भाग चौर का इलाका है । चौर के पूरब में अवस्थित क्षेत्र यथा सुल्तानगंज, मंझली, सुल्तानगंज तारापुर रोड इत्यादि को जलप्लावित होने से बचाने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा 3.5 किलोमीटर की लंबाई में मंझली बांध का निर्माण कराया गया है ।

बरसात के मौसम में प्रश्नगत क्षेत्रों में खेती नहीं होती है परंतु बरसात के पश्चात् इन इलाकों में खेती होती है ।

3- कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, भागलपुर के द्वारा पत्रांक- 435, दिनांक- 23.06.2022 से मंझली गांव के पश्चिम स्थित रिंग बांध (जमींदार बांध) का मजबूतीकरण कराये जाने के संबंध में जिलाधिकारी, भागलपुर से अनुरोध किया गया है ।

श्री ललित नारायण मंडल : सर, इसमें एक प्रश्न अलग से पूछना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिए ।

श्री ललित नारायण मंडल : पूरक पूछना चाहते हैं कि उत्तर में लिखा गया है कि बरसात के दिनों में खेती उधर नहीं होती है जबकि धान की खेती होती है और धान की खेती ओवर फ्लो होकर जो पानी आता है उससे बर्बाद हो जाती है । यह बहुत पुराना बांध है, जब हम बहुत छोटे थे उस वक्त यह बांध बना था सर । महोदय, इससे बहुत हानि होती है और इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, इसलिए आग्रह है कि इसको तेजी से कराया जाय ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : महोदय, मैंने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया है और जो इनका प्रश्न मंझली गांव के लिए है, तो हमने कहा है कि उस बांध का मजबूतीकरण...

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय,

अध्यक्ष : पहले आप ही बोल लीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अभी जल संसाधन मंत्रीजी माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे उसके पहले आपने आसन से कुछ संसदीय प्रणाली को मजबूत करने के लिए या विधायकों के उत्कृष्ट आचरण के संबंध में जो बातें कही हैं । हमने उचित समझा कि सरकार की तरफ से भी जो आपके विचार हैं हम उसके साथ सरकार के विचार को भी जोड़ते हैं कि संसदीय जनतंत्र में जबतक यह सदन और आसन के साथ-साथ सभी माननीय सदस्य उन मूल्यों को संवर्द्धित और

संरक्षित करने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमारे जनतांत्रिक मूल्यों का क्षरण होगा और यह भविष्य में भी जनतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत नहीं होगा । इसलिए हमलोग भी चाहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि संसदीय जनतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर ही इस सदन की खूबसूरती बढ़ाते हैं ।

अध्यक्ष : आप विपक्ष को आमंत्रित कर लें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आप जो बात कह रहे हैं मैं वहीं पहुंच रहा था कि जबतक हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य नहीं होते हैं, सच पूछें तो सरकार या सत्ता पक्ष को भी एक अधूरेपन का एहसास होता है । हम नहीं चाहते हैं कि संसदीय प्रणाली के सशक्त ढंग से कार्य करने की जो प्रणाली निर्धारित की गयी है, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से लेकर संविधान के विशेषज्ञों ने इस सदन को संचालित करने में सत्ता पक्ष हों या विपक्ष हों उनके प्रभावकारी भूमिका का निर्धारण किया है वह किसी भी मामले में कमतर हो यह सरकार भी नहीं चाहती है । महोदय, इसी सदन में एक आदर्श वाक्त लिखा है कि विपक्ष के लोग भी सरकार के अंग होते हैं, विपक्ष के दल भी सरकार के अंग होते हैं और अगर सदन में आज विपक्ष नहीं है तो सरकार अधूरी है और हमलोगों को भी अच्छा नहीं लगता है । इसलिए आपने जो आसन से सभी माननीय सदस्य, जो विपक्षी दलों के हैं, जो अभी सदन में नहीं हैं, हम आपके उस आग्रह के साथ सरकार और सत्ता पक्ष के आग्रह को भी जोड़ते हुए उन सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करते हैं कि जो बाहर हैं वे सदन में आ जायं । सदन की प्रक्रिया निर्धारित है, आप हों, चाहे हम माननीय सदस्य हों, सरकार हो, विपक्ष हो, आसन हो सब नियम से बंधे हैं और एक-एक को नियम का पालन करना चाहिए । जबतक सभी मिलकर नियम का पालन नहीं करेंगे न सदन की खूबसूरती बढ़ेगी, न सदन की मर्यादा बढ़ सकती है । इसलिए आसन की बातों के साथ सरकार की भावना को जोड़ते हुये हमलोग भी जो हमारे माननीय सदस्य विपक्षी दलों के हैं उनसे आग्रह करते हैं कि सदन में आयें और जो चीज सदन की नियमावली से प्रतिबंधित हैं उन बातों पर जोर देकर सदन से अनुपस्थित रहकर सरकार को एक खालीपन का, अधूरेपन का एहसास करायें यह उचित प्रतीत नहीं होता है, इसलिए हम आग्रह करते हैं आपके साथ कि वे सदन में आ जायं ।

टर्न-4/हेमन्त/29.06.2022

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने माननीय विधायकों के उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट विधायिका के संबंध में जो एक नयी कल्पना बिहार विधान सभा

के सामने रखने का प्रयास किया है और महोदय, वह कोई एक दिन की चीज नहीं है । पांच वर्षों का जो कार्यकाल होता है उसमें माननीय विधायकों का सदन के प्रति और सदन की जो कार्यावली है उसके अनुसार अपने को निर्वहन करना और बिहार विधान मंडल कहीं-न-कहीं पूरे बिहार के आम लोगों को प्रतिबिंबित करता है और सरकार और माननीय विधायकों का दायित्व भी है और हमारी प्रतिबद्धता भी बिहार के आम लोगों के प्रति है और विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष का एक आईने के रूप में हम सब उसे देखते हैं । जिससे जो कमियां हैं, जो बातें सदन के माध्यम से लायी जाती हैं, तो उन कमियों को भी हम सब खोजते हैं और उसे रेगुलेट करने का हम सबों का प्रयास रहता है । आपने जो आज सदन के आसन से अपनी बातें कही हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी ने भी विस्तार से इसकी चर्चा की है और मुझे लगता है कि सारा सदन आपकी भावना के साथ है और आपके माध्यम से पूरा सदन आग्रह कर रहा है कि विपक्ष के जो हमारे साथी हैं वह सदन की जो कार्यावली है, जो प्रावधान, जो परंपरा रही है या जो नियमावली रही है उसके अनुसार हम सब उसके प्रति प्रतिबद्ध रहें । यह अनुरोध करते हुए हमारा भी आग्रह है कि विपक्ष के जो हमारे साथी हैं वह सदन में आयें और सदन में जो विमर्श है या जो बहस है उसमें हिस्सा लेकर, बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार का गौरव कैसे बढ़े इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करें। धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहा करते थे कि बिहार में जनसमस्याओं के समाधान एवं इससे संबंधित नीति निर्माण के संदर्भ में यह सदन सार्थक विमर्श के लिए सबसे बड़ी संस्था है । सदन में अपनी बात नियमानुसार रखने एवं सकारात्मक सुझाव देने में सभी समस्याओं का समाधान संभव है, जो संसदीय कार्य मंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि बिहार की करोड़ों जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले विरोधी दल के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह होगा कि जनहित में सभी को सदन में आकर अपनी बात बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियमों के तहत अपनी बात रखनी चाहिए और सबको बिहार के विकास में अपनी सकारात्मक तथा रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए । प्रकृति का भी इशारा है कि आपका बाहर रहना ये अनुमति नहीं दे रहा है । आप सदन में आयें हमारा फिर से आग्रह है ।

माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा था कि जो प्रश्न माननीय सदस्य ललित नारायण मंडल जी ने किया है, जो मझली गांव है, हमने तो स्पष्ट जवाब

भी दे दिया है और हम उसको मजबूत कर देंगे । हम लोगों ने डी0एम0, भागलपुर को भी लिखा है और हम लोग उसको परश्यू करके, शायद इनका भी वही गांव है। कल तो मैंने माननीय विधायक से बात भी की थी और हम लोग इसको मजबूत करवा देंगे ।

श्री ललित नारायण मंडल : बरसात के दिनों में प्रश्नगत क्षेत्रों में खेती नहीं होती है । जबकि खेती होती है और आप जानते हैं कि किसान मानता नहीं है मतलब खेती करेगा ही, लेकिन बहुत क्षति हो जाती है । इसलिए वह जल्दी हो जाय । कृपया इसकी कृपा करें ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने जवाब में दिया है । मैंने ऑलरेडी पत्र का भी रेफरेंस दिया है, जो दिनांक- 23.06.2022 को हमने पत्र लिखा है भागलपुर डिविजन को और हम लोग इसको जल्दी ही करवा देंगे और वह हमसे मिले भी थे, जल्दी ही हम लोग इसको करवा देंगे ।

श्री ललित नारायण मंडल : धन्यवाद सर ।

तारांकित प्रश्न सं0-235 (श्री अमर कुमार पासवान, क्षेत्र सं0-91, बोचहां(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-236 (श्री विश्व नाथ राम, क्षेत्र सं0-202, राजपुर(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-237 (श्री अमर कुमार पासवान, क्षेत्र सं0-91, बोचहां(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-238 (श्री नीतीश मिश्रा, क्षेत्र सं0-38, झंझारपुर)

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री(लिखित उत्तर) : खंड-क स्वीकारात्मक ।

खंड-ख स्वीकारात्मक ।

मधुबनी जिलान्तर्गत झंझारपुर प्रखंड के चनौरागंज पंचायत में बड़की तालाब में 12 फीट से अधिक तथा लखनौर प्रखंड के कछुआ पंचायत में जानो मानो तालाब में भी 14 फीट पानी है ।

अतः उक्त तालाबों के उड़ाही/जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ इतना आग्रह करना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के पीछे जो उद्देश्य था और इसी संदर्भ में तत्कालीन जिलाधिकारी, मधुबनी ने दिनांक- 18.12.2020 को ही कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल,

मधुबनी को निर्देश भी दिया था कि जिन दो तालाबों का जिक्र हमने किया है । मुख्यत: सहरसा के सतर कटईया प्रखंड में मत्स्य गंधा के नाम से लघु सिंचाई विभाग ने बहुत ही अद्‌भुत कार्य किया है और उसी तर्ज पर हम इन दो तालाबों, जो झंझारपुर और लखनौर में जानो मानो और बडकी पोखर है, उसके सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव जिलाधिकारी ने भी भेजा था । लेकिन डेढ़ वर्ष बीत जाने के बाद भी, यह वास्तविकता है कि पानी है उसमें, लेकिन मेरा उद्‌देश्य था कि मत्स्य गंधा की तर्ज पर इन दो तालाबों को विभाग विकसित करने पर विचार करे और जिलाधिकारी ने जो भी अपना निर्देश दिया है...

अध्यक्ष : पूरक हो गया ? माननीय मंत्री, लघु जल संसाधन विभाग ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मत्स्य गंधा झील के बारे में बात की है, इसके बारे में मैं जानकारी देना चाहता हूं कि वहां सहरसा की जो झील है उसमें 70 प्रतिशत भाग सूखा रहता है और 30 प्रतिशत भाग वेटलैंड है और वहां पानी डेढ़ फीट के आसपास में है । इस कारण से वह काम हो सका और माननीय सदस्य ने प्रश्न में जिस जगह के बारे में चर्चा की है जानो मानो तालाब के बारे में, वहां 12 फीट पानी रहता है और मात्र 30 प्रतिशत भाग है जो सूखा है और 70 प्रतिशत भाग वेटलैंड है और वहां की मिट्‌टी दोमट मिट्‌टी है, वहां काम करना मुश्किल होगा । फिर भी मैं माननीय सदस्य को सदन के माध्यम से आश्वस्त कर देना चाहता हूं तकनीकी दल मैं जल्द विभाग के स्तर से भेजूंगा । अगर संभावना पायी गयी, फिजिबिलिटी होगी कि काम किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर विभाग काम कराने के लिए इच्छुक है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मंत्री जी को । मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि तालाब का जीर्णोद्धार एक विषय है, मैंने उसके सौंदर्यीकरण और उसको विकसित करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि सहरसा में लगभग 6 करोड़ से भी अधिक राशि से सिर्फ जल संधारण एक विषय है, लेकिन उसके आसपास की भूमि को पेवर्स ब्लॉक लगाकर बहुत ही सुंदर और आदर्श बनाया गया है, तो माननीय मंत्री जी से मैं पुन: आग्रह करूंगा कि उस तर्ज पर, पानी है यह बहुत बड़ी बात है कि पानी वहां 12 फीट, 14 फीट है जो माननीय मंत्री जी ने भी अपने उत्तर में दिया है । यह एक बहुत बड़े क्षेत्रफल में है और गंगा दशहरा में वहां पर अत्यधिक भीड़ भी होती है, तो मैं पुन: माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस सौंदर्यीकरण को भी ध्यान में रखकर वह कार्य योजना बनाना चाहेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0–239 (श्री नरेन्द्र कुमार नीरज, क्षेत्र सं0–153, गोपालपुर)

श्री जयंत राज, मंत्री(लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष राज्य योजनान्तर्गत Construction of RCC Bridge Over Kalbaliya Dhar Near Kamlakund Tola के नाम से स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है, जिसमें पुल संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पहुंच पथ का कार्य प्रगति पर है । पुल के एक तरफ पहुंच पथ में मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं दूसरी तरफ (मालपुर की ओर) निजी जमीन रहने के कारण इसके सीमांकन हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा अंचलाधिकारी, गोपालपुर से प्रतिवेदन की मांगी की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है पूरक पूछिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत गोपालपुर प्रखंड..

अध्यक्ष : आप प्रश्न पढ़ रहे हैं ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : सर, पूरक तो लिखकर लाये ही नहीं हैं ।

अध्यक्ष : मन में जो पूरक इस प्रश्न पर उठता है तो पूछिये । जवाब आपने पढ़ा है ?

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : नहीं सर, जवाब तो नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : आपके पी0ए0 ने प्रशिक्षण लिया था ?

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : अच्छा हम बोल देते हैं ।

अध्यक्ष : आप अभी बैठ जाइये । पहले उत्तर सुन लीजिए तब पूछियेगा । माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिए । आप उत्तर ध्यान से सुनिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पुल शीर्ष राज्य योजनान्तर्गत Construction of RCC Bridge Over Kalbaliya Dhar Near Kamlakund Tola के नाम से स्वीकृत एवं निर्माणाधीन है, जिसमें पुल संरचना का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं पहुंच पथ का कार्य प्रगति पर है । पुल के एक तरफ पहुंच पथ में मिट्टी भराई का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं दूसरी तरफ (मालपुर की ओर) निजी जमीन रहने के कारण इसके सीमांकन हेतु कार्यपालक अभियंता द्वारा अंचलाधिकारी, गोपालपुर से प्रतिवेदन की मांगी की गई है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव हो सकेगा ।

टर्न-5/धिरेन्द्र/29.06.2022

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : महोदय, स्थिति बहुत ही गंभीर है । पच्चीसों हजार पब्लिक को जब बाढ़, बरसात का टाईम आता है तो बड़ी कठिनाई होती है और कभी-कभी नाव पलट जाती है, दुर्घटनाएं होती हैं । वह पुल अति-आवश्यक है । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वह कब तक बनायेंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, विषय की गंभीरता को लेकर बताइये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, पुल तो बन चुका है । वहां पर एक तरफ का एप्रोच नहीं बना है चूंकि निजी जमीन पड़ रहा है । उसको हमलोग सतत लीज पर ले लेंगे और माननीय सदस्य से भी अनुरोध होगा कि वहां पर थोड़ा-सा सहयोग करें । हमलोग सतत लीज पर उसको ले लेंगे और बना देंगे ।

अध्यक्ष : वे पूछ रहे हैं कब तक ?

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां के अंचलाधिकारी को जमीन का सीमांकन करने के लिए पत्र के माध्यम से निदेश दिया गया है, सीमांकन हो जायेगा तो हमलोग सतत लीज पर उस जमीन को ले लेंगे और उसका पैसा दे देंगे । उसके बाद हमलोग उसे बनवा देंगे ।

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : महोदय, हम समय-सीमा पूछ रहे हैं ?

अध्यक्ष : समय-सीमा बता दीजिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, हमारे विभाग से सतत लीज पर जमीन लेने की प्रक्रिया थोड़ा अलग हो जायेगा ।

अध्यक्ष : आप उसकी प्रगति से विधायक जी को अवगत करा दीजियेगा ।

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, उसकी प्रगति से हमलोग माननीय सदस्य को अवगत भी करा देंगे और माननीय विधायक से अनुरोध होगा....

श्री नरेन्द्र कुमार नीरज : महोदय, हम मंत्री जी से मिल लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है, आप मंत्री जी से मिल लीजियेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-240 (श्री शकील अहमद खाँ, क्षेत्र संख्या-64, कदवा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-241 (श्री प्रणव कुमार, क्षेत्र संख्या-165, मुंगेर)

श्री नितिन नवीन, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-80 के मुंगेर-भागलपुर-मिर्जाचौकी फोरलेन सड़क निर्माण हेतु किसानों का अधिकृत जमीन का भू-अर्जन का कार्य NH Act, 1956 के तहत किया जा रहा है । जिसका दर निर्धारण RFCTLAR Act, 2013 के तहत सक्षम

पदाधिकारी-सह-जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, मुंगेर और भागलपुर के द्वारा किया गया है एवं मुआवजा वितरण किया जा रहा है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिला में जमीन का मूल्य निर्धारण करने हेतु जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक मूल्य निर्धारण कमेटी होती है लेकिन कमेटी ने जो एम0वी0आर0 में मूल्य निर्धारण किया है उससे बहुत कम, न्यूनतम राशि दिया जा रहा है और इतना दोषपूर्ण है कि जहां घर बना हुआ है नियम में है कि घर से 200 मीटर तक....

अध्यक्ष : आप डायरेक्ट पूरक पूछिये ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो एम0वी0आर0 सीट है उसके अनुसार उन्हें कब मुआवजा मिलेगा ?

अध्यक्ष : कब मिलेगा ? बताइये ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, एम0वी0आर0 सीट का जो निर्धारण होता है, जब भूमि अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू होता है तब उस समय से एम0वी0आर0 सीट तैयार होता है और उस समय की कमेटी ने जो वहां का सर्किल रेट रहा होगा और रेवेन्यू के हिसाब से जो जमीन की बिक्री होती है उसका एवरेज निकाल कर, उस समय के जिलाधिकारी ने उसको तय किया है और एम0वी0आर0 सीट के आधार पर ही RFCTLAR Act, 2013 के तहत मुआवजा दिया जाता है तो अभी उसी के तहत सारी चीजें ली गई हैं । अभी जो इसमें मुआवजा का दर निर्धारित है वह भूमि अधिग्रहण के समय में ही तय होता है जब एम0वी0आर0 सीट बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि जो मूल्य निर्धारण किया गया है, वर्तमान में जो रेट है उससे काफी कम निर्धारण किया गया है और यहां तक कि घर का दाम लगाया गया है, उस घर का कृषि भूमि में दिया गया है जबकि नियम है कि घर से 200 मीटर आगे तक आवासीय भूमि में देना चाहिए ।

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरे विषय को, माननीय सदस्य ने जो बताया है कि किसी को अगर इस प्रकार की असुविधा है कि कृषि योग्य भूमि थी और उसको आवासीय नहीं मिल रहा है तो हम उसको दिखवा लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या-242 (श्री अमरजीत कुशवाहा, क्षेत्र संख्या-106, जीरादेई)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-243 (श्री मोहम्मद अनजार नईमी, क्षेत्र संख्या-52, बहादुरगंज)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–244 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र संख्या–48, फारबिसगंज)

अध्यक्ष : उत्तर संलग्न है, पूरक पूछिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर हमें नहीं प्राप्त हुआ है ।

अध्यक्ष : आपका पी0ए0 उत्तर क्यों नहीं निकालता है । जब शत प्रतिशत प्रश्नों का जवाब सरकार दे रही है तो आप लोगों को भी इसे गंभीरता से लेना होगा और अगर आपके पी0ए0 सक्षम नहीं हैं तो आप सभा सचिवालय में भेजिये, उनको हम प्रशिक्षण देंगे ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो रोड है सीमांचल कंस्ट्रक्शन द्वारा....

अध्यक्ष : बैठिये, आप उत्तर सुने नहीं तो कैसे प्रश्न कर रहे हैं । माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, उत्तर पढ़ दीजिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्नाधीन पथ है वह पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–3 के अंतर्गत स्वीकृत है और माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूँ कि पी0एम0जी0एस0वाई0 फेज–3 के अंतर्गत दिनांक–24.06.2022 के द्वारा इसकी स्वीकृति भी मिल गई है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, दिनांक–24.06.2022 के द्वारा स्वीकृति जो प्राप्त हुई है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि इसका वर्क ऑडर कब तक मिलने वाला है ?

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी स्वीकृति तो मिल चुकी है, अब निविदा की प्रक्रिया जल्द हो जायेगी और उसके बाद सड़क बनना शुरू हो जायेगा ।

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है ।

अध्यक्ष : आप मंत्री जी से मिल लीजिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, सीमावर्ती क्षेत्र है और इस रोड से एस0एस0बी0 का आना–जाना लगा रहता है और नो मैन्स लैंड है उसके चलते वहां की गतिविधि को, सीमावर्ती क्षेत्र को देखना एस0एस0बी0 का काम है । प्रमुख रोड होने की वजह से यह वर्ष 2017 से लेकर अभी तक इसका निर्माण कार्य नहीं हुआ । हमने सदन में दस–दस बार इस मामले को उठाया है लेकिन आज तक इस पर काम नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : स्वीकृति तो मिल गई है । आप बैठ जाइये ।

तारांकित प्रश्न संख्या–245 (श्री विजय शंकर दूबे, क्षेत्र संख्या–112, महाराजगंज)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–246 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र संख्या–48, फारबिसगंज)

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर पढ़वा दिया जाय ।

अध्यक्ष : दो–दो प्रश्न है और आप जवाब नहीं निकालते हैं । आप कहीं बाहर से आए हैं क्या ? माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1– स्वीकारात्मक है ।

2– स्वीकारात्मक है ।

3– वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्न चार पथों से संबंधित है कौजबे मटियारी से हंसकोसा, यह पथ बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत स्वीकृति के उपरांत निविदा के प्रकाशन की प्रक्रिया में है । निविदा के निष्पादन के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा । हंसकोसा से धमदाहा चौक, यह पथ शीर्ष पी0एम0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत निर्मित टी04 से सहवाजापुर पथ का पथांश है जो पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि में अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । तीसरा, धमदाहा चौक से पीपरा पुल तक, यह पथ आरेखण में अवस्थित बसावटों को छूटे हुए बसावट के तहत संपर्कता प्रदान करने हेतु विभागीय ऐप के माध्यम से सर्वे कार्य करा लिया गया है जिसका सर्वे आई0डी0–29845 है । समीक्षोपरांत निधि की उपलब्धता के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा । पीपरा पुल से बॉर्डर रोड, इस पथ की मरम्मति हेतु प्राक्कलन बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है । स्वीकृति के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई किया जाना संभव होगा ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछना चाहता हूँ कि ये सारे रोड की कनेक्टीविटी सीमावर्ती क्षेत्र के बॉर्डर रोड से है और ये सभी रोड, मैंने दोनों रोड का ही प्रश्न किया था । दोनों रोड सीमा सड़क से जुड़ा हुआ है और नेपाल का बॉर्डर है । गलत लोगों की एक्टीविटी रहती है, यह रोड नहीं बनने के चलते उस क्षेत्र के हजारों लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है । एक रोड असरी से कुसमाहा के लिए हम वर्ष 2017 से बोल रहे हैं....

अध्यक्ष : पूरक पूछिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस रोड का निविदा करा कर कब तक इसका वर्क ऑर्डर दिया जायेगा ?

अध्यक्ष : आपको माननीय मंत्री जी विस्तार से तो बताये हैं ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया है कि पहला जो रोड है वह कौजबे से मटियारी हंसकोसा यह स्वीकृति की प्रक्रिया में है ।

अध्यक्ष : ये पूछ रहे हैं कि कब तक ?

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, यह स्वीकृति की प्रक्रिया में है । पहला हमलोग एक महीने के अंदर करा देंगे । दूसरा अनुरक्षण अवधि में है, जिस पर अनुरक्षण कार्य कराया जा रहा है । तीसरा का विभागीय ऐप से सर्वे कर लिया गया है, इसमें जब हमलोगों को ब्रिक्स बैंक से लोन मिल जायेगा तो उस समय इसे प्राथमिकता में लेकर बनायेंगे और चौथा, बिहार ग्रामीण अनुरक्षण नीति, 2018 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है इसको भी हमलोग एक महीने के अंदर बनवा देंगे, पीपरा पुल से बॉर्डर तक का जो पथ है ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, नेपाल से कनेक्टीविटी का संबंध है ।

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये, हो गया । आप भी मंत्री जी से मिल लीजियेगा । मंत्री जी से मिलते-जुलते रहिये ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, वर्ष 2017 से लेकर अभी तक मिल ही रहे हैं और हमारा एक भी काम नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष : मंत्री जी, थोड़ा गंभीरता से लीजिये ।

श्री जयंत राज, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम माननीय सदस्य से मिल लेंगे और जो स्थिति है वह उनको बता देंगे ।

अध्यक्ष : सीमावर्ती क्षेत्र का मामला है, गंभीर है ।

श्री जयंत राज, मंत्री : महोदय, जल्द-से-जल्द इसको करा देंगे ।

टर्न-6/संगीता/28.06.2022

तारांकित प्रश्न संख्या-245 (श्री विजय शंकर दूबे, क्षेत्र संख्या-112, महाराजगंज)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-246 (श्री विद्या सागर केशरी, क्षेत्र संख्या-48 फारबिसगंज)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-247 (श्री विनय कुमार, क्षेत्र संख्या-225, गुरूआ)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-248 (श्री विजय कुमार, क्षेत्र संख्या-169, शेखपुरा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-249 (श्री राजेश कुमार, क्षेत्र संख्या-222, कुटुम्बा(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-250 (डॉ0 सत्येन्द्र यादव, क्षेत्र संख्या-114, मांझी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–251 (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र संख्या–135, मोरवा)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–252 (श्री जनक सिंह, क्षेत्र संख्या–116, तरैया)

श्री जयंत राज, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1– स्वीकारात्मक है ।

2– स्वीकारात्मक है ।

3– वस्तुस्थिति यह है प्रश्नाधीन पथ एम0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत डोयला मुख्यमंत्री सड़क कुवर महतो के मकान से शती स्थान ईश्वर नट डोयला बाजार रहमान मिया सोने लाल मांझी के घर तक के नाम से निर्मित है । वर्तमान में यह पथ पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । इस पथ की कुल लम्बाई 2.50 मि0मी0 है, जिसमें निजी जमीन विवाद होने के कारण इस पथांश के 240 मीटर लम्बाई में निर्माण नहीं हो पाया था । पथ के निर्माण हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत सर्वे कर निजी भूमि के मूल्य को समाहित करते हुए प्राक्कलन तैयार की जा रही है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : श्री जनक सिंह, पूरक पूछिए । उत्तर नहीं देखे हैं तो पढ़वा दें ?

श्री जनक सिंह : नहीं, नहीं अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध है और मैं साधुवाद देता हूं माननीय मंत्री जी को चूंकि उन्होंने इस कार्य को कहा है कि पूरा कर लेंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या–253 (श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, क्षेत्र संख्या–17,पिपरा)

श्री जयंत राज, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1– स्वीकारात्मक है ।

2– वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 2.00 कि0मी0 है । पथ की मरम्मति हेतु नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है । निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जा सकेगा ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : महोदय, मंत्री जी का जवाब आया है कि प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है और निधि उपलब्धता के आधार पर निर्माण कराया जाएगा । हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि कब तक राशि उपलब्ध कराकर इस कार्य को निर्माण करा दिया जायेगा ? एक समय निधारित कर दें...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि 2018 के अनुरक्षण नीति के अंतर्गत इस पथ को लिया गया है, इसको हमलोग एक महीने के अंदर टेंडर निकलवाने की प्रक्रिया पूरा कर देंगे ।

श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव : मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : श्री अचमित ऋषिदेव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-254 (श्री अचमित ऋषिदेव, क्षेत्र संख्या-47, रानीगंज (अ0जा0))

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री (लिखित उत्तर) : अररिया जिलान्तर्गत रानीगंज प्रखंड में कुल-04 नलकूप अवस्थित हैं ।

वर्तमान में लघु जल संसाधन विभाग द्वारा नया राजकीय नलकूप लगाने की कोई योजना नहीं है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए विधायक जी । नहीं उत्तर देखें हैं क्या ?

श्री अचमित ऋषिदेव : महोदय, हम भी मंत्री जी से मिल लेंगे ।

अध्यक्ष : माननीय विधायक जी, उत्तर मिला है कि नहीं ?

श्री अचमित ऋषिदेव : उत्तर तो नहीं मिला है लेकिन मंत्री जी से मिलकर काम करवा लेंगे हम ।

अध्यक्ष : ये तो बड़ा अच्छा तालमेल है, सदस्यों के और मंत्री के बीच का ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : हमलोग तो चाहते हैं कि जो माननीय सदस्यों की भावना है या जो माननीय मंत्री जी जितनी उदारता से सदस्यों के अनुरोध का सामंजन करते हैं कि आने वाले समय में मंत्री और सदस्य अगर आपस में मिलते-जुलते रहें, बात करते रहें तो हम समझते हैं प्रश्न आने की नौबत ही नहीं आएगी ।

अध्यक्ष : लेकिन एक चीज विधायक जी, कोयल की आवाज से लोग मुग्ध हो जाते हैं और तोता नकल करता है तो कैद हो जाता है ।

श्रीमती गायत्री देवी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-255 (श्रीमती गायत्री देवी, क्षेत्र संख्या-25, परिहार)

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर मिला हुआ है । मंत्री जी अपने उत्तर में कहे हैं कि इस सड़क को अतिरिक्त सुलभ संपर्कता में लिया गया है । मैं मंत्री जी से पूछती हूं कि कैबिनेट से अतिरिक्त सुलभ संपर्कता योजना की मंजूरी कब मिली है, यह बता दीजिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, कैबिनेट से इसका आलेख बन गया है, कैबिनेट में अभी जा रहा है और जल्द ही हमें उम्मीद है कि सुलभ संपर्कता का मिल गया है और माननीय सदस्या को मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि इसको हमलोग चूंकि बहुत लंबा सड़क है, इसको हमलोग अस्थायी रूप से चालू हालत करने के लिए हमलोग काम भी शुरू कर दिए हैं महोदय ।

श्रीमती गायत्री देवी : उत्तर में तो गलत दिया हुआ है तब, कैबिनेट से इसका मंजूरी...

अध्यक्ष : आप बैठ जाइये मंत्री जी, हां बोलिए ।

श्रीमती गायत्री देवी : इसका कैबिनेट से इसमें उत्तर में दिया हुआ है कि मंजूरी मिल गया हुआ है, और हमलोगों का उत्तर में मिला हुआ है इसका मंजूरी कैबिनेट से हो चुका है और इसका तो उत्तर गलत देने वाला दे दे गलत और अध्यक्ष महोदय, दूसरा है वहां बाढ़ और बरसात के कारण 3 साल से यह सड़क पूरा का पूरा खत्म हो चुका है और बनाने का भी समय नहीं है और इसमें कैबिनेट से उत्तर हमलोगों को मिला हुआ है देखे हैं ।

अध्यक्ष : एक मिनट माननीय सदस्या, बैठ जायें आप । आप उत्तर पहले पढ़ दीजिए माननीय मंत्री जी, इनके प्रश्न का उत्तर पढ़कर सुना दीजिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : 1- स्वीकारात्मक है ।

2- स्वीकारात्मक है ।

3- वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ की लम्बाई 22.00 कि0मी0 है । सम्पूर्ण आरेखन पंचवर्षीय अनुरक्षण अवधि से बाहर है । इस पथ का सर्वेक्षण अतिरिक्त सुलभ सम्पर्कता अन्तर्गत किया गया है । तदनुसार निधि की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर निर्माण कार्य कराया जाना संभव हो सकेगा ।

अध्यक्ष : समझ लिए न ?

श्रीमती गायत्री देवी : मतलब सबसे पहले तो 23 किलोमीटर है, इसमें दे दिया गया है 22 किलोमीटर।

अध्यक्ष : आप भी एक बार मंत्री जी, एक बार मिल करके समझ लीजिए ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सड़क की लम्बाई है वह विभाग के पास 22 किलोमीटर का रिकॉर्ड है तो 22 किलोमीटर का किया गया है...

श्रीमती गायत्री देवी : और वहां का अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : ठीक है, एक बार मिल के समझ लीजिए, आप तो अगल-बगल ही बैठते हैं ।

श्रीमती गायत्री देवी : वहां का अध्यक्ष महोदय, मतलब हमलोगों का तो अभी तो बाढ़ आ गई है क्षेत्र में इसमें कोई दो मत नहीं है, बारिश इतना हो रहा है और 50 हजार की आबादी है..

अध्यक्ष : चलिए, एक बार मिल लीजिएगा, मंत्री जी गंभीरता से विधायिका जी का देख लीजिए ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह ।

तारांकित प्रश्न संख्या–256 (श्रीमती स्वर्णा सिंह, क्षेत्र संख्या–79,गौड़ाबौराम)

श्री जयंत राज, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ पी0एम0जी0एस0वाई0–III अन्तर्गत चयनित टी012 कदवाड़ा से रामखेतरिया पथ का पथांश है । पथ का प्राक्कलन तैयार कर राज्य तकनीकी एजेंसी STA, Muzaffrpur से अनुमोदन प्राप्त कर NRIDA, नई दिल्ली भारत सरकार को स्वीकृति हेतु समर्पित है । तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है, पूरक पूछिए ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : अध्यक्ष महोदय, ये सड़क मैं मंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि यह सड़क पी0एम0जी0एस0वाई0– III के अंतर्गत स्वीकृति के लिए गई हुई है तो मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहती हूं, पूछना चाहती हूं कि यह कब तक स्वीकृत होगी और अगर स्वीकृति में टाईम लगता है, समय लगता है तो अगर इनके विभाग से कुछ हो सकता है क्योंकि ये सड़क का बहुत ही खराब हालत है अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : ठीक है ।

श्रीमती स्वर्णा सिंह : बहुत जर्जर हालत है तो इसमें अगर इनके विभाग से कुछ हो सकता है तो इसमें कुछ किया जाय ।

अध्यक्ष : ठीक है । मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, ये सुझाव दिए हैं ग्रहण कर लीजिए ।

तारांकित प्रश्न संख्या–257 (श्री अनिरूद्ध कुमार, क्षेत्र संख्या–180, बख्तियारपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–258 (श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, क्षेत्र संख्या–95, काँटी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या–259 (श्री नरेन्द्र नारायण यादव, क्षेत्र संख्या–70,आलमनगर)

श्री जयंत राज, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1– स्वीकारात्मक है ।

2– स्वीकारात्मक है ।

3– स्वीकारात्मक है ।

4– वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन पथ बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 अंतर्गत बाड़ाटेनी चौक से दुबही सुबही तक पथ के नाम से निर्माणाधीन है । एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 06.06.2021 है । कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण संबंधित संवेदक के निबंधन को डिबार करने की प्रक्रियाधीन है । संवेदक द्वारा जुलाई 2022 तक कार्य पूर्ण करने संबंधी

शपथ पत्र प्राप्त कर लिया गया है । तद्नुसार निर्माण कार्य जुलाई, 2022 तक पूर्ण कर दिया जायेगा ।

श्री नरेन्द्र नारायण यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सड़क है एन0एच0-106, बाड़ाटेनी से लश्करी दुबही सुबही होते हुए एस0एच0-58 को जोड़ती है, और लगातार संवेदक ने समय की मांग की है शपथ पत्र दिया है, बरसात का बक्त आ गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या एक सप्ताह के अंदर इस क्षतिग्रस्त पथ को चलने लायक बना देंगे ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग ।

श्री जयंत राज, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से दिया है कि संवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है कि जुलाई, 2022 तक इसको पूर्ण कर लिया जायेगा और हम देख लेते हैं कि उसको जल्द से जल्द हम पूरा करवा देंगे ।

अध्यक्ष : ठीक है । श्री विश्वनाथ राम ।

तारांकित प्रश्न संख्या-260 (श्री विश्व नाथ राम, क्षेत्र संख्या-202, राजपुर (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-261 (श्री अनिल कुमार, क्षेत्र संख्या-24, बथनाहा(अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-262 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र संख्या-226, शेरघाटी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-263 (श्री महबूब आलम, क्षेत्र संख्या-65, बलरामपुर)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-264 (श्री समीर कुमार महासेठ, क्षेत्र संख्या-36, मधुबनी)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न संख्या-265 (श्री राज कुमार सिंह, क्षेत्र संख्या-144, मटिहानी)

श्री नितिन नवीन, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- वस्तुस्थिति यह है कि गंगा नदी के बाढ़ से बचाव के लिए उत्तरी किनारे पर जल संसाधन विभाग का गुप्ता लखमिनियाँ तटबंध है, जो एन0एच0-31 के चकिया BTPS से प्रारम्भ होकर विभाग के मुंगेरघाट-रसीदपुर पथ के 12.00 कि0मी0 (एन0एच0-31 के बलिया) के निकट मिलता है ।

2- जल संसाधन विभाग से NOC प्राप्त कर पथ निर्माण विभाग द्वारा गुप्ता लखमिनियाँ बाँध का 35.05 कि0मी0 लम्बाई में एकल लेन (3.75 मी0 चौड़ाई) पथ का मजबूतीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसे नवम्बर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

3- विषयांकित तटबंध के चौड़ीकरण हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन प्राप्त की जा रही है ।

अध्यक्ष : पूरक पूछिए ।

श्री राज कुमार सिंह : जो जवाब आया है कि इसका सर्वे करा लिया गया है, विगत लगभग 9 महीने पहले ही इसका सर्वे हुआ, मैंने दो बार स्थानीय अभियंता के साथ उस जगह का निरीक्षण करवाया है लेकिन अभी तक सिर्फ सर्वे हुआ है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो दोनों मोहल्ले हैं ये दशकों से इसमें लगभग हजारों परिवारों का घर है, जिनको मुख्य सड़क से इनकी संपर्कता बिल्कुल नहीं बनी हुई है और समय-समय पर इसको रोक दिया जाता है इनका आवागमन इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि क्या अविलंब सरकार की नीतियों के अनुरूप यहां पर संपर्क पथ का निर्माण कराया जायेगा?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

टर्न-7/सुरज/29.06.2022

श्री नितिन नवीन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही प्रश्न के उत्तर में कहा है कि 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है जो काम चल रहा है । जो दूसरा विषय इन्होंने कहा था इसके चौड़ीकरण का विषय उस पर हमलोगों ने तकनीकी संभाव्यता के आधार पर उसका डी0पी0आर0 का काम शुरू किया है । जैसे ही डी0पी0आर0 आता है तो इसको हमलोग स्वीकृति के लिये आगे भेजेंगे ।

तारांकित प्रश्न सं0-266 (श्री ललित नारायण मंडल, क्षेत्र संख्या-157, सुलतानगंज)

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न का उत्तर मिला है इसका उत्तर नहीं मिला है ।

अध्यक्ष : अच्छा ठीक है, माननीय मंत्री जी से मिल लीजियेगा ।

श्री ललित नारायण मंडल : जैसा आदेश हो सर ।

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ । जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं । अब कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 जून, 2022 के लिये माननीय सदस्य, श्री अजीत शर्मा से कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा मतदान एवं बिहार विनियोग विधेयक के व्यवस्थापन का कार्य निर्धारित है । अतएव बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 176(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं रहने के कारण कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को अमान्य किया जाता है । अब शून्यकाल लिये जाएंगे ।

शून्यकाल

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मधुबनी जिलान्तर्गत एक दर्जन से अधिक उच्च विद्यालयों में वर्ष-2017-18 एवं 2018-19 की छात्रवृत्ति, साइकिल एवं पोशाक योजना के करोड़ों की राशि प्रधानाध्यापकों द्वारा वापस नहीं कर गवन करने का प्रयास हो रहा है । शीघ्र प्राथमिकी दर्ज करते हुए राशि वसूली की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री ललन कुमार : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत पीरपैंती प्रखण्ड के रानी दियारा, एकचरी, मोहनपुर, टपूआ, अंठावन, तोहफील में गंगा नदी के कटाव से हजारों लोग बेघर होने के कगार पर हैं ।

अतः सरकार से उक्त स्थल पर यथाशीघ्र कटाव निरोधक कार्य कराने की मांग करता हूं ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : अध्यक्ष महोदय, बांका जिला के कटोरिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कटोरिया प्रखण्ड अन्तर्गत जमदाहा पंचायत के जमदाहा ग्राम में स्थित अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र की चहारदीवारी (घेराबंदी) नहीं होने से भूमि का अतिक्रमण हो रहा है ।

अतः उक्त स्वास्थ्य केन्द्र की चहारदीवारी की मांग करती हूं ।

श्री विद्या सागर केशरी : अध्यक्ष महोदय, अररिया जिलान्तर्गत फारबिसगंज नगर परिषद् में अवस्थित सीताधार के अतिक्रमित होने से जल प्रवाह का मार्ग अवरूद्ध हो जाता है, जिससे प्रतिवर्ष शहर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । फारबिसगंज नगर परिषद् का मास्टर प्लान तैयार कर जलनिकासी एवं सीताधार को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग सदन से करता हूं ।

श्री कुंदन कुमार : अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलान्तर्गत बेगूसराय शहर में ताइक्वांडो तथा वॉलीबॉल एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की मैं सरकार से मांग करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मो0 कामरान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मोहम्मद अंजार नईमी ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

श्री मुरारी मोहन झा : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत बनसारा पंचायत के प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर जो की पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है । इस विद्यालय का शीघ्र निर्माण करना अति आवश्यक है । छात्र हित को देखते हुए विद्यालय भवन निर्माण कार्य करवाने की कृपा की जाय ।

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिला के सुलतानगंज प्रखंड के घोरघट, गनगनियां, फतेहपुर, कमरगंज इत्यादि गांवों में नीलगायों के भयंकर प्रकोप से बचाने के लिए वन विभाग द्वारा नीलगायों को पकड़वाने की मांग करता हूं ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, नई दिल्ली-हावड़ा मेन रेलवे लाइन पर हाजीपुर जोन के दानापुर डिवीजन अंतर्गत जमुई और झाझा स्टेशन के बीच स्थित कटौना हॉल्ट पर ट्रेनों के ठहराव को कोरोना काल के पूर्व की भांति पुनर्बहाल करने की मांग करती हूं ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत संग्रामपुर प्रखंड के किसानों से कैंप लगाकर 2019 में बिजली कनेक्शन हेतु आवेदन लिया गया था लेकिन अभी तक लगभग आधे नलकूपों तक ही बिजली पहुंची है ।

अत: शेष नलकूपों तक अविलंब बिजली पहुंचाये जाने की मांग करती हूं।

श्री राम चन्द्र प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सुरहाचट्टी से हथौड़ी पथ में हमेशा भारी वाहनों का आना-जाना लगा रहता है । सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण वाहनों के आवागमन में काफी कठिनाई होती है।

अत: मैं सरकार से उक्त पथ को चौड़ीकरण कराने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : अध्यक्ष महोदय, नरकटियागंज क्षेत्र में अवस्थित सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों के आवासन की व्यवस्था उपलब्ध कराने के साथ सुविधा-विहीन इकलौते सरकारी ए0एन0एम0 ट्रेनिंग कॉलेज, जहां दूर-दूर से आई लगभग 60 लड़कियां हॉस्टल में रह कर ट्रेनिंग ले रही हैं को मानक अनुरूप सुविधा प्रदान करने की मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करती हूं ।

श्री पवन कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मिर्जाचौकी कहलगांव भागलपुर घोरघट वर्तमान एन0एच0-80 के 10 मीटर चौड़ीकरण सहित निर्माण का दो खंडों में टेंडर एवं

शिलान्यास हो जाने के बाद भी वन विभाग से एन0ओ0सी0 नहीं मिलने के कारण निर्माण प्रारंभ नहीं हुआ है, सरकार से शीघ्र एन0एच0-80 के चौड़ीकरण सहित निर्माण प्रारंभ कराने की मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठ जाइये, कहां जा रहे हैं । माननीय सदस्यगण, प्रश्न अपना शून्यकाल में पूछते हैं और चल देते हैं यह बड़ा विचित्र है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । हमारे तरैया विधान सभा क्षेत्र के 10 मजदूर महाराष्ट्र के कुर्ला में रहते थे और चौथी मंजिल के ढह जाने से हमारे 7 मजदूर भाई की मृत्यु हो गई और 3 घायल हैं । कल माननीय श्रम मंत्री जी को हमने इसकी सूचना भी दे दी है । वैसे तो वहां पर 30 से अधिक लोग दबे हुये हैं तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इन मृतक परिवारों के प्रति सरकार सोचे और उनके शव को वहां से लाने के लिये मैं सरकार से आग्रह करता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय श्रम मंत्री जी यहां बैठे हैं संज्ञान में लेंगे ।

श्री जनक सिंह : वैसे तो...

अध्यक्ष : बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं ।

श्री जिवेश कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त है बिहार सरकार को और हमारे अधिकारी वहां लगातार उनके संपर्क में हैं । मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर यह घटना घटी है और अन्य जगह या उसके बाहर यह घटना घटती तो सीधा बॉडी को हम वहां से यहां ले आते । बी0एम0सी0 का रूल है कि कोई परिजन जायेंगे तभी उस बॉडी को वो हैंडओवर करेंगे । उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और विभाग के अधिकारी के संज्ञान में है । हम बॉडी को घर तक लायेंगे इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और साथ ही नियमानुसार जितनी सुविधा होगी सभी प्रदान करेंगे ।

श्री जनक सिंह : धन्यवाद ।

अध्यक्ष : और किन्हीं की कोई महत्वपूर्ण सूचना है ?

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, भागलपुर जिलान्तर्गत एन0एच0-80 घोघा गोल सड़क से आमापुर के बीच 20-20 फीट लंबे और डेढ से दो फीट गहरे गढ्ढे हो गये हैं जिसकी वजह से पिछले 60 घंटे से महाजाम लगा हुआ है, एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही है । अत: सरकार से तुरंत कम से कम मोटरेबुल करने की मांग करते हैं ।

टर्न–8/राहुल/29.06.2022

अध्यक्ष : आज महत्वपूर्ण सूचना कम हैं । 14 शून्यकाल थे वह पूरे हुए । यह बता दें कि संगत का फर्क, पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है यह संगत का फल है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है और शीप में आती है तो खुद मोती बन जाती है । इसलिए संगत हमेशा सही लोगों के साथ करनी चाहिए और मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी न करे और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत न हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता है, हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बना देते हैं । अभी आप लोग जा रही थीं प्रश्न करके तो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जरा ध्यान दें, हम यहां बैठे हैं जनप्रतिनिधि, बड़े ही भाग्यशाली हैं कि जनता ने हमें अपना आशीर्वाद देकर यहां कि सेवा का महत्वपूर्ण अवसर दिया है । एक वर्ष में यह सदन लगभग 40 से 50 दिन ही चलता है । ऐसी स्थिति में मैं सभी माननीय दलीय नेताओं से, जो अंदर बैठे हैं और जो बाहर भी सुन रहे होंगे, यह करबद्ध आग्रह करता हूं कि सदन में सत्र के दौरान सभी माननीय सदस्यों की शत प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करावें, ऐसा होने पर हम न केवल अपने संसदीय और विधायकी दायित्वों का अधिकाधिक निर्वहन कर सकेंगे बल्कि बिहार के इस गौरवशाली प्रदेश में विधायिका को और भी जनोन्मुखी बना सकेंगे । इससे बिहार के विकास की गति भी बढ़ा सकेंगे और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा परंपराओं को भी मजबूती मिलेगी । माननीय विधायकों की शत प्रतिशत उपस्थिति से नए चुनकर आये सदस्यों के विधायकी ज्ञान और अनुभव में भी अभिवद्धि होती है और उनको जनसरोकार के मुद्दे उठाने का भी मौका मिलता है । आपको ज्ञात होगा कि सत्र के संचालन में लोकनिधि का बहुत अधिक खर्च और मानव संसाधन का बहुत उपयोग होता है और आपके सदन में सार्थक विमर्श करने से ही जनता के पैसे का उपयोग है । सदन से बाहर रहकर आप जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतर पाएंगे, यह गंभीरता से सबको विचार करना होगा । ऐसी स्थिति में उनसे सदुपयोग की प्राथमिक जिम्मेवारी हम सभी की है । हमें अपने संसदीय और विधायकी दायित्वों के प्रति सजग और संवेदनशील बनना होगा, इसमें उदासीनता का भाव लोकतंत्र को कमजोर करेगा और ऐसा होने पर लोकतंत्र की जननी बिहार के लिए यह बड़ी ही असहज स्थिति होगी । हमें अपने लोकतांत्रिक गौरव और संसदीय मूल्यों को गहराई से पुनर्स्थापित करना होगा । आइये हम सब मिलकर, जो अंदर बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं यह संकल्प लें कि सदन की गरिमा बढ़ाने के लिए और 21वीं सदी का राष्ट्र बनाने के लिए हम इस

लोकतंत्र की जननी की धरती का मान बढ़ायेंगे । आपकी सहमति से अब ध्यानाकर्षण सूचनाएं समय से पहले ली जाएंगी । माननीय सदस्य श्री अरूण शंकर प्रसाद अपनी सूचना को पढें ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

श्री अरूण शंकर प्रसाद, एवं श्री बीरेन्द्र सिंह, स0वि0स0 से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उस पर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, ''राज्य के सभी प्रखण्ड संसाधन केन्द्र के लिए बी0आर0पी0 चयन मार्गदर्शिका, 2017 के अनुसार प्रखण्ड साधन सेवी (बी0आर0पी0) के पदों पर चयन अधिकतम तीन वर्षों के लिए करने का प्रावधान है जबकि विभिन्न प्रखण्डों में पांच वर्षों से अधिक समय से प्रखण्ड साधन सेवी (बी0आर0पी0) अपने पदों पर कार्यरत हैं । अधिक समय तक अपने पदों पर रहने के कारण बी0आर0पी0 एवं विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा शिक्षकों का आर्थिक शोषण हो रहा है । सरकार द्वारा प्रखण्ड साधन सेवी की उपयोगिता पर उपयुक्त अनुशंसा देने हेतु विभागीय आदेश संख्या-4820, दिनांक 03.08.2021 के द्वारा उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है परन्तु गठित उच्चस्तरीय समिति द्वारा अभी तक अनुशंसा नहीं किये जाने के कारण वर्षों से वे अपने पद पर बने हुए हैं जिससे राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा है ।

अतः समिति की अनुशंसा आने तक वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए प्रखण्ड साधन सेवी को अपने मूल विद्यालय में वापस करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।''

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है यह बड़ा ही प्रसांगिक है, मौजू है और सरकार के संज्ञान में भी पूर्व से है और हम लोगों ने इसकी समीक्षा भी की है । हम माननीय सदस्य को और सदन को बताना चाहते हैं कि माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है या जो मांग की है हम एक महीने के अंदर सभी बी0आर0पी0 को अपने मूल विद्यालय में वापस भेज देंगे । एक महीने में भेजकर और दूसरी बात जिसकी चर्चा इन्होंने की है बी0आर0पी0 पद की उपयोगिता के संदर्भ में तो हम लोग उसकी जांच करा ही रहे हैं और उसकी उपयोगिता के संबंध में जो कमेटी की अनुशंसा आती है अगर उसकी उपयोगिता होगी तभी यह पद बरकरार भी रहेगा, अगर इसकी उपयोगिता नहीं होगी तो इस पद की भी आवश्यकता नहीं होगी और अगर इसकी

उपयोगिता किसी भी रूप में प्रमाणित हो पाई तो फिर हम नये लोगों का नई पद्धति से चयन करेंगे लेकिन अभी जो है, जो इन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है हम एक महीने के अंदर इन सबको अपने मूल विद्यालय में वापस कर देंगे ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : अब तो इतना सकारात्मक जवाब है अब इसमें क्या पूछ रहे हैं ?

श्री अरूण शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से केवल यह जानना चाहता हूं कि प्रखण्ड संसाधन केन्द्र पर ये जो प्रखण्ड साधन सेवी लोग हैं उनके वहां रहने से शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर कोई असर नहीं हो रहा है बल्कि वे वहां एक बिचौलिये की भूमिका में रह रहे हैं तो क्यों नहीं इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाय और इसकी उपयोगिता वहां से हटा दी जाय । मैं यह माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मुझे नहीं लगता है कि इसमें समिति की जरूरत है माननीय मंत्री जी स्वयं जैसा अभी उन्होंने सार्थक निर्णय किया है उसी प्रकार का निर्णय करके उसकी वहां से सदा के लिए छुट्टी कर दें, उसकी उपयोगिता को ही समाप्त कर दें । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कब तक करा देंगे ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो जो प्रश्न वे पूछ रहे हैं उसका भी उत्तर बता ही दिया है कि आखिर सरकार इस पद की उपयोगिता की समीक्षा क्यों करा रही है । जरूर इसकी उपयोगिता के संबंध में कुछ प्रश्नचिन्ह हैं सरकार के मन में । हमारे मन में भी लग रहा है कि यह उपयोगी है या नहीं है और इसलिए जो इन्होंने मांग की है इन सबको हम मूल विद्यालय में वापस भेज देते हैं और हम लोगों के भी जो प्रथम दृष्टया चीजें संज्ञान में आई हैं उस हिसाब से अगर आवश्यकता नहीं होगी, कोई उपयोगिता नहीं होगी, आखिर कोई पद समाप्त करने की भी एक प्रकिया होती है । इसलिए कमेटी बनाई गई है और कोई उपयोगिता नहीं होगी तो सरकार कभी इस पद को नहीं रखेगी और अगर उपयोगिता भी आयेगी तो जो माननीय सदस्य की मूल चिंता है या मूल विषय है जिस पर इन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है कि अगर आना भी होगा तब दूसरे लोगों का नये तरीके से, नये मैन्डेट के साथ चयन होगा और ये अभी वर्तमान भूमिका में नहीं रह सकेंगें ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : मैं माननीय मंत्री जी को इस सकारात्मक सोच के लिए धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष : बहुत अच्छा । माननीय मंत्री जी से बहुत अपेक्षा है शिक्षा विभाग को ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अगर आपकी, सदन की या आसन की अपेक्षा है तो हम आपके और सदन के सहयोग से ही अपने, मतलब यथा सामर्थ्य कहिये, यथा

सामर्थ्य हमारी भी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से हम आपकी या माननीय सदस्याओं और सदस्यों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे ।

टर्न-9/मुकुल/29.06.2022

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है । इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें हल जरूर निकल जायेगा । माननीय मंत्री जी बड़ी सजगता के साथ आपको इशारा किये हैं ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हम इसमें केवल एक चीज थोड़ा पूरक देना चाहते हैं । आपने कहा कि कठिनाई और परेशानी आये तो शांत रहिये, लेकिन हमारी समझ से सिर्फ शांत रहने से कहां काम चलता है, महोदय । कितनी भी परेशानी आये तो शांत रहिये, संतुलित रहिये, संयमित रहिये और सबसे आगे प्रसन्न रहिये, सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी । महोदय, कहा जाता है कि

''जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दूरियां मिटाते रहो ।''

अध्यक्ष : लेकिन

''जिंदगी हर कदम पर नये रंग दिखाने लगी है,
वह जो मेरे हर राज के राजदार थे,
वह अब हमसे अपनी बात छुपाने लगे हैं ।
सोच रहे थे कि क्या खता हुई हमसे, जो हमको दूर करना चाहते हैं,
आज पता चला कि कोई और उनके करीब आने लगे हैं ।''

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, लेकिन हम तो आपके आने की और आपके नजदीक आने की आहट बहुत पहले से जान लेते हैं ।

हम तो आपके आने की पहल मतलब आहट, बहुत पहले से जान लेते हैं और हम तो महोदय इस आसन को बहुत नजदीक से पहचान लेते हैं ।

अध्यक्ष : अनुभव की किताब बाजार में बिकती नहीं और आपके अनुभव को पूरा सदन जान लेता है । माननीय सदस्य, श्री निरंजन कुमार मेहता अपनी सूचना को पढ़ें ।

सर्वश्री निरंजन कुमार मेहता, श्री राज कुमार सिंह एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (योजना एवं विकास विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य भर में ऐसा देखा जा रहा है कि सुदूर देहाती क्षेत्रों में गरीब, खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्तियों की मृत्यु हो

जाने पर उसके दाह-संस्कार की कोई व्यवस्था नहीं होने से मृतक के शव को जहां-तहां खुले नदी में फेंक दिया जाता है साथ ही पूर्व में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि योजना से छोटे-छोटे पुल या कल्भर्ट निर्माण का प्रावधान था, जिसे अब बन्द कर दिया गया है, जिससे आम जनता को सुलभ आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ।

अतः देहाती क्षेत्रों में पंचायतवार सरकारी जमीन चिन्हित कर मुक्ति धाम एवं छोटे-छोटे पुल-पुलिया कल्भर्ट निर्माण हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि योजना से माननीय विधायकों को अनुशंसित करने का अधिकार देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक-3210, दिनांक-22.06.2016 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका-2014 की कंडिका-06 की उप कंडिका (30) में विद्युत शवदाह गृह का निर्माण की योजना सम्मिलित है ।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना विभागीय संकल्प संख्या 3439, दिनांक-30.06.2017 के द्वारा सम्यक विचारोपरांत 'छिलका, फॉल, चेक डैम एवं चेक वॉल के निर्माण की योजना' को मार्गदर्शिका में सम्मिलित किया गया है तथा इस योजना के तहत विधानमंडल के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर कार्यान्वित करायी जाने वाली सम्पर्क पथ निर्माण संबंधी योजना में आवश्यकतानुसार कल्भर्ट/छोटे-छोटे पुलियों का निर्माण कराया जाता है ।

वर्तमान में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका में अलग से मुक्तिधाम एवं छोटे-छोटे पुल-पुलिया कल्भर्ट निर्माण की योजना को सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमलोग अपने क्षेत्र में बराबर घूमते रहते हैं और मैं अपनी आंखों से देखता हूं कि महादलित परिवार के शव को उठाकर पानी में फेंक दिया जाता है ।

(व्यवधान)

हम दोनों पर आ रहे हैं, मेरा पूरक प्रश्न है इसलिए मुझे बोलने दीजिए । यह सबों के हित की बात है । एक तो उसका आदेश होना ही चाहिए मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में । पंचायती राज विभाग के द्वारा बोला गया है कि मुक्ति धाम की स्थापना होगी लेकिन कब तक होगी, वह भी हमको नहीं लगता है कि कब तक होगी । लेकिन मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि हमलोगों को सरकार की ओर से

जो अपना पावर दिया गया है और आम जनता का पावर है, छोटा-छोटा कल्भर्ट, हमारे क्षेत्र में तीन जगहों पर मांग की गई है लेकिन छोटा-छोटा कल्भर्ट मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में पहले था । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि अगर छोटा-छोटा कल्भर्ट हमलोगों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में आ जाता है और आ जाना चाहिए, उससे हमलोगों को बड़ी सुविधा होगी और इसमें सभी माननीय सदस्यों का ख्याल है, यह सभी माननीय सदस्यों की बात है और उस कल्भर्ट के लिए हमलोग तुरंत लिखेंगे, अनुशंसा हमलोगों के हाथ में आपने हस्तगत किया है, सरकार पावर दी है, हमलोग अनुशंसित करते हैं । आज कैसे छतदार चबूतरा बनाते हैं, आज कैसे कलामंच बनवाते हैं, आज पी0सी0सी0 का निर्माण हमलोग कराते हैं तो इसमें इस कल्भर्ट को आ जाना चाहिए और सीधा इसमें आना चाहिए । जो अभी माननीय मंत्री महोदय बताये हैं, उससे श्रीमान् नहीं बनने वाला है हमलोगों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में । अध्यक्ष महोदय, हम आपसे और सरकार से आग्रह करेंगे कि यह आना चाहिए और माननीय मंत्री जी के द्वारा आज आश्वासन मिलना चाहिए और दोनों का आदेश निर्गत होना चाहिए ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, यह पुल-पुलिया वाला हमलोगों का एकदम....

(व्यवधान)

अध्यक्ष : इसमें जिनका नाम है, केवल वही बोलिये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : नहीं । हमलोगों का करवा दीजिए ।

अध्यक्ष : आप सब 10 से ज्यादा विधायक उठे हुए हैं, प्रश्न की गंभीरता दिखाई पड़ रही है।

(व्यवधान)

श्री कुमार शैलेन्द्र : अध्यक्ष महोदय, हमलोग चाहते हैं ।

अध्यक्ष : सारे विधायक । अब बैठ जाइये, बैठ जाइये ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : महोदय, पहले यह था । महोदय, ये वर्ष 2010-15 में हमलोगों का था ।

अध्यक्ष : आपका इसमें नाम नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है । इसमें राज कुमार सिंह जी का, राजीव कुमार सिंह जी का, दिलीप राय जी का और दामोदर रावत जी का हस्ताक्षर है, इनमें से कोई बोलिए ।

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है । मेरा तो यही सजेशन है कि क्षेत्र के विकास के लिए जितने भी कार्यक्रम हैं, मुख्यमंत्री जो विकास फंड है उसको उसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि किसी भी विधायक को अपने क्षेत्र में सर ऊंचा करके और लोगों की समस्या का समाधान करने में कोई यह न हो । चूंकि यह फंड है और इसका नाम मुख्यमंत्री क्षेत्र

विकास योजना है तो क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी योजना हो उसको इसमें सम्मिलित करना चाहिए, यह मेरा सजेशन है । महोदय, क्षेत्र विकास में जितनी भी चीजें हैं, उसको इसमें सम्मिलित करने में कोई बुराई नहीं है ।

अध्यक्ष : आपलोग कार्यालय के लिए भी इंट्रेस्टेड हैं न ?

श्री राज कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, जी । कार्यालय के लिए भी कर सकते हैं तो कर दें ।

अध्यक्ष : ठीक है, बैठ जाइये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा ।

अध्यक्ष : पूरा संरक्षण है, आज तो कोई संरक्षण में बाधक भी नहीं है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव होगा कि मुक्ति धाम और छोटा-छोटा कल्भर्ट के लिए सरकार...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप लोग इनकी बात सुन लीजिए, गंभीरता से सुनिये ।

श्री निरंजन कुमार मेहता : कल्भर्ट पुल-पुलिया वही हो गया, बड़ा पुल तो ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा बनता ही है, छोटा-छोटा कल्भर्ट पुल-पुलिया और मुक्ति धाम का, मेरा सुझाव है कि एक प्राक्कलित राशि निर्धारित कर दे, 10 लाख, 15 लाख उससे आगे हमलोग अनुशंसा नहीं करें और जो करें उसके अंतर्गत रहे और उससे छोटा-छोटा कल्भर्ट पुल-पुलिया और मुक्ति धाम की भी सरकार एक राशि निर्धारित कर दे ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी बहुत उदारता के साथ उठे हैं ।

टर्न-10/यानपति/29.06.2022

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है वह वाजिब है । सरकार भी माननीय सदस्य की चिंता से चिंतित हो जाती है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मनरेगा योजना से भी हमलोग काम करते हैं । पंचायत समिति के 15वें योजना से भी कार्य होते हैं महोदय । जिला परिषद् भी...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: यह उचित नहीं है बैठ जाइये, माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए । पहले बोल लेने दीजिए फिर मौका देंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: आपका सुझाव नकारात्मक नहीं है, मैंने कहां कहा ।

अध्यक्ष: इन्होंने तो स्वीकार किया कि सही है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: मैंने कहा कि यह अच्छा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा से भी हमलोग काम करते हैं जहां कच्ची सड़क बना रहे हैं उसमें पुल-पुलिया देते हैं,

जहां अलंग का निर्माण करते हैं उसमें देते हैं, जहां पईन की उड़ाही करते हैं उसमें आवश्यकतानुसार देते हैं ।

अध्यक्ष: मुक्तिधाम भी बनता है मनरेगा से ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: इसमें तो है, नियमावली में है । नियमावली में मैंने कहा है...

अध्यक्ष: नियमावली में क्या-क्या है एक बार बता दें ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: शवदाह गृह निर्माण का इसमें प्रावधान किया हुआ है ।

अध्यक्ष: एक बार पढ़ दीजिए, सब नहीं सुन रहे हैं । आपलोग ध्यान से सुन लीजिए, आपलोगों के ध्यान में आ जाय जो चीज है ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विभागीय संकल्प ज्ञापांक संख्या-3210 दिनांक-22.06.2016 द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका में 2014 की कंडिका 6 के उपकंडिका 30 में विद्युत शवदाह गृह के निर्माण की योजना है । इसी को हमलोग नीचे के स्तर पर भी करा देंगे महोदय । यह संशोधित करके...

अध्यक्ष: मुक्ति धाम भी करवा देंगे ?

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: मुक्ति धाम भी हो जाएगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आपका नाम इसमें नहीं है । अभी उन्हीं का है ।

श्री निरंजन कुमार मेहता: माननीय अध्यक्ष महोदय, मनरेगा से नहीं, हमलोगों को जो अपना पावर दिया गया है, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि, कैसे काम होता है, कहां काम होता है, उतना बोलने की सदन में जरूरत नहीं है, सभी लोग जानते हैं लेकिन सरकार के हमलोग सत्ताधारी हैं, हमलोग काम कराते हैं, हरेक काम पर ध्यान रखते हैं और काम करवाते हैं । हमलोग क्षेत्र घूमते हैं । छोटा-छोटा पुल, कलवट का जो है, मुक्ति धाम का, मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि में सीधा निर्देश दे दिया जाय, सबको सुविधा होगी और हमलोग बनवा देंगे ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्य सभी लोग चिंतित हैं और माननीय सदस्य की चिंता से सरकार वाकिफ हो गई है, सरकार इसपर विचार करेगी ।

अध्यक्ष: सरकार भी चिंतित हो रही है । आश्वासन हो गया, इसको सरकार गंभीरता से लेगी । सरकार इतनी सजगता के साथ विषय को रखी है ।

(व्यवधान)

नहीं आपका नहीं है । राजकुमार जी, आप बोलिये ।

श्री राजकुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, सभी सदस्यों की भावना है और मैं शेयर करना चाहूंगा कि सरकार की योजनाएं अपना काम करती हैं लेकिन क्षेत्र में जब विधायक अपनी योजना से कुछ कार्य करता है तभी क्षेत्रवासियों को लगता है कि हमारे विधायक ने भी हमारे लिए कुछ किया है इसलिए पुल-पुलिया का निर्माण हो, मुक्ति धाम का निर्माण हो, इन चीजों का मुख्यमंत्री विकास फंड से विधायक को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अनुशंसा कर सके ताकि क्षेत्रवासियों को लगे कि उनका विधायक भी उनके लिए कुछ कर रहा है सरकार के अतिरिक्त । यही भावना है सारे सदस्यों की और मैं सरकार से आग्रह करूंगा...

अध्यक्ष: बैठिये, सबका विषय आ गया बहुत-बहुत धन्यवाद ।

(व्यवधान)

पूर्व मुख्यमंत्री जी बोलिये ।

श्री जीतन राम मांझी: अध्यक्ष महोदय, इस ध्यानाकर्षण में हमने हस्ताक्षर नहीं किया है लेकिन हम व्यवस्था के अनुसार काम करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं । आप अवगत हैं सर कि 1980 से हम विधायक हैं और जबसे क्षेत्र विकास योजना या ऐच्छिक योजना जो 50 हजार पहले था 1 लाख किया गया था उस समय किसी प्रकार का बैरियर नहीं लिखा गया था, हुआ था कि विधायक अपने मन के अनुसार अपने क्षेत्र में काम करा सकेंगे तो हम समझते हैं पुराना वह है, अब बैरियर लगाने की क्या जरूरत है कि अमुक काम कीजिए, अमुक काम नहीं कीजिए । मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना को एकदम फ्री कर देना चाहिए जहां जो विधायक काम करना चाहें वह करावें, मैं यह प्रस्ताव देता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इनके विचार को सबसे, अभी सदन में सीनियर हैं, विधायक हैं आप गंभीरता से लें और माननीय सदस्यों की भावना का सम्मान तो आप करने के लिए आश्वासन भी दिए हैं तो इसको गंभीरता से अगले सत्र के पहले दिखाई भी पड़े ।

(व्यवधान)

अब हो गया, बैठ जाइये । माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम, 1981 की कंडिका 26 (3) के तहत् ''बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2022'', ''बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित

मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022'' एवं ''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022'' की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: बिहार राज्य मदरसा बोर्ड अधिनियम, 1981 की कंडिका 26 (3) के तहत् ''बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा (मौलवी स्तर तक) शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारी (नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2022'', ''बिहार राज्य गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अनुदानित मदरसा प्रबंध समिति गठन नियमावली, 2022'' एवं ''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड नियमावली, 2022'' की एक-एक प्रति सदन पटल पर 14 दिनों तक रखी रहेगी ।

माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति ।

श्री दामोदर रावत: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत् राजकीय आश्वासन समिति का लघु जल संसाधन विभाग से संबंधित 320वां प्रतिवेदन एवं ग्रामीण कार्य विभाग से संबंधित 322वां प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन में उपस्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति ।

श्री नंद किशोर यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के तहत् प्राक्कलन समिति का 161वां प्रतिवेदन सदन पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष: अब सभा की कार्यवाही 2:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/अंजली/29.06.2022

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, वित्तीय वर्ष-2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों का व्यवस्थापन होगा । उक्त विवरण में सम्मिलित अनुदानों की मांगों की कुल संख्या 39 है । आज इसके लिए एक ही दिन का समय निर्धारित है ।

अत: किसी एक विभाग की अनुदान की मांग के प्रस्ताव पर वाद विवाद एवं सरकार का उत्तर तथा मतदान हो सकता है । मैं मांग संख्या-21 शिक्षा विभाग को लेता हूं, जिस पर वाद विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । शेष मांगों का व्यवस्थापन गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा किया जायेगा । इसके लिए 03 घंटे का समय उपलब्ध है ।

विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है । इसी समय में से सरकार के उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा ।

भारतीय जनता पार्टी	- 57 मिनट
राष्ट्रीय जनता दल	- 56 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	- 33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 14 मिनट
सी0पी0आई0(एम0एल0)	- 09 मिनट
ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन	-04 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 03 मिनट
सी0पी0आई0एम0	- 02 मिनट
सी0पी0आई0	- 02 मिनट

माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग अपनी मांग प्रस्तुत करें ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''शिक्षा विभाग के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग संख्या-2 अधिनियम, 2022 के उपबंध के अतिरिक्त

12013,86,33,000/- (बारह हजार तेरह करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार रुपये) से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

महोदय, यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव, श्री महबूब आलम, श्री विजय शंकर दूबे एवं श्री अख्तरूल ईमान से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो व्यापक हैं । जिनपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री ललित कुमार यादव का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव, माननीय सदस्य, श्री ललित कुमार यादव अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें । श्री ललित कुमार यादव जी नहीं हैं । श्री महबूब आलम, वे भी नहीं हैं । श्री विजय शंकर दूबे वे भी अनुपस्थित हैं । श्री अख्तरूल ईमान ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

माननीय सदस्यगण, कटौती प्रस्ताव मूव नहीं हुआ, इसलिए अब मूल प्रस्ताव पर ही विचार-विमर्श होगा । माननीय सदस्य, श्री संजीव चौरसिया अपना पक्ष रखें ।

श्री संजीव चौरसिया : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । जैसा कि ज्ञात है कि बिहार की शिक्षा की स्थिति जो आबादी का प्रतिफल है उसके हिसाब से साक्षरता दर की जो वृद्धि हुई है उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत के 12वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना यह बिहार है और उसमें शिक्षा दर 2001 में गणना के हिसाब से 47 प्रतिशत शिक्षा का दर था और वर्तमान संदर्भ में 2011 का 60.82 प्रतिशत शिक्षा का दर है । पूरे भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो 74 प्रतिशत है तो यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि शिक्षा के आयाम का बहु पैमाना जो सरकार ने तय किया है वह माध्यमिक से लेकर, वह उच्च से लेकर और प्रारंभिक से लेकर सभी शिक्षा का पैमाना अलग-अलग स्तरों पर तय होने का काम हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर शैक्षणिक स्तर तक शिक्षकों की बहाली से लेकर यानी की बहुआयामी विचार को अपने पैमानों को संग्रह करते हुए शिक्षा को ज्ञान की गंगा को बहाने की जो संकल्पना सरकार ने स्वीकार किया है, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय का संदर्भ हमलोग निश्चित तौर पर जानते हैं कि बिहार के शिक्षा की रीति-नीति, संदर्भ कितने अपने आप में पैमाने हैं कि बिहार के निकले हुए शिक्षा ग्रहण किए हुए बहुआयाम में नेतृत्व करने वाले अलग-अलग विधा में देश के अंतर्गत वह ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में हो, पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, सभी जगह हो कहीं न कहीं बिहार के शिक्षा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति

ही वह प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से निकलकर जाता है तो प्रतिभा को सुशोभित करने का काम विश्व के मानस पटल पर करता है । यह बिहार की मिट्टी ही है, बिहार की सुगंध ही है कि शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करता है । यह चाणक्य की धरती है कि उसको आगे बढ़ाने का काम करता है । आपको ज्ञात तो होगा कि शिक्षकों की बहाली के लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं उसके लिए भी प्रशंसनीय कदम हैं और 90 हजार की संकल्पना के साथ 42 हजार की शिक्षकों की बहाली के नियोजन की जो कार्रवाई थी वह हो चुकी है, आगे प्रधान शिक्षक हेतु 40 हजार 518 पद जो मध्य विद्यालय के लिए सारे शिक्षा के लिए जो थे वह बी0पी0एस0सी0 की प्रक्रियाधीन है, एडवरटाइजमेंट दे दिया गया है उसके लिए बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है । इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए समग्र शिक्षा के आलोक में जो सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं शिक्षा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम समग्र शिक्षा के माध्यम से किए हैं वह अपने आप में प्रशंसनीय कदम हैं । माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व बालपन शिक्षा की नीति के, अर्ली चाईल्ड हुड एजुकेशन की दृष्टि से 12वीं कक्षा तक के शिक्षा को आच्छादित किया जा रहा है और सबसे बड़ा अभियान समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो 21 हजार 286 नए प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, साथ ही साथ 19 हजार 633 प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है फलस्वरूप यह अपने आप में ऐतिहासिक कदम है कि 98.63 टोले को कवर्ड करने का काम किया है । प्राथमिक विद्यालय की दृष्टि से भी 99.19 प्रतिशत लगभग शत् प्रतिशत कवर्ड करने का काम टोलों के माध्यम से किया गया है और असैनिक कार्य के अंतर्गत 15 हजार 941 प्रारंभिक विद्यालयों के विद्यालय भवन के विरुद्ध 15 हजार 653 विद्यालय भवन का निर्णय लिया गया है यह अपने आप में अनूठा कदम है और सबसे बड़ी बात की बिहार सरकार ने वर्ष 2021 के कोविड-19 के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसके लिए जो सरकार ने कदम उठाए हैं वह बहुत ही प्रशंसनीय है । प्रवेशोत्सव के माध्यम से विशेष नामांकन अभियान चलाने का सरकार ने जो अभियान चलाया है, इसके तहत 6 से 18 आयु के वर्ग के सभी बच्चों को नामांकन नजदीक के विद्यालयों में कराया गया है इस अभियान के तहत पूरे राज्य में 36.77 लाख बच्चों को बिहार के विभिन्न विद्यालयों में नामांकित करने का काम किया गया है और इसके साथ-साथ शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए 1 से 8 तक के बच्चों के लिए अलग-अलग प्रकार से 402.71 करोड़ का जो आवंटन निशुल्क पुस्तक पाठ्यक्रम के लिए कि लगभग एक करोड़

29 लाख 65 हजार 878 बच्चों के लिए 402.71 करोड़ का निशुल्क पाठ्यक्रम जो लगभग एक करोड़ 39 लाख 69 हजार 278 बच्चों के लए 898.15 करोड़ का पोशाक भी उपलब्ध कराने का उद्देश्य उनके खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया गया है जो अब तक के पहले के पैमाने में, इन सरकार की बहुत सारी योजनाओं को लग जाता था कि घोटालों के अंकुश का पैमाना तय करना पड़ता था सरकार की यह पारदर्शिता कदम के कारण ही इतनी बड़ी आबादी की संख्या पर सीधा डी0बी0टी0 के माध्यम से जो देने का काम हुआ है यह अपने आप में प्रशंसनीय कदम है । कोविड-19 के संक्रमण के फलस्वरूप मध्याह्न भोजन के अंतर्गत भी डी0बी0टी0 के माध्यम से अलग-अलग प्रकार से सामग्री से राशि देने का काम हुआ है । ई-लोटस पर भी कक्षा-1 से 12 में भी सभी पाठ्यक्रम पुस्तक, पाठ आधारित वीडियो, संदर्भ वीडियो, बच्चों के स्वमूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सामग्री अपलोड किया गया है । कोविड के माध्यम से वर्चुअल शिक्षा का जो आधार हुआ है उसमें भी बिहार पीछे हटने का काम नहीं किया है । इसके माध्यम से आगे बढ़ाने का काम हुआ है चूंकि 2 से 10 तक के बच्चों के जो लर्निंग लॉसेस हुए थे उसको पूरा करने के लिए कैचअप कोर्सेस की व्यवस्था की गई है ताकि ई-कन्टेंट के माध्यम से मेरा दूरदर्शन, मेरा विद्यालय इसके प्रतिदिन 5 स्लॉट, एक-एक घंटा तक का स्लॉट डिजिटल पढ़ाई के लिए किया गया था जो अपने आप में एक प्रशंसनीय कदम है यानी कि विद्यावाहिनी मोबाइल एप के माध्यम से 1 से 12 का पाठ्यक्रम बच्चों को उपलब्ध कराने का काम किया गया था । डिजिटल के माध्यम से भी शिक्षा अवरुद्ध न हो पाए तो डिजिटल के माध्यम से ही बच्चों में शिक्षा का ज्ञान निश्चित तौर पर पूरे सामग्रता के साथ बढ़ने का काम हो, सरकार ने उसकी पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाज के समजोर वर्गों के लिए भी सरकार ने क्षितिज बालिकाओं के प्रारंभिक शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए 535 कस्तूरबा गांधी बालिका उच्च विद्यालय को संचालित करने के लिए उनमें कुल 50 हजार 963 बालिकाओं को नामांकित करने का काम किया गया है । भारत सरकार की संस्था एलिम्को के द्वारा राज्य के सभी जिलों में दिव्यांग बच्चों की पहचान चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आकलन सह मूल्यांकन शिविर का आयोजन जो करने का काम हुआ था यह अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय कदम है कि.... (क्रमशः)

टर्न-12/सत्येन्द्र/29-06-22

श्री संजीव चौरसिया (क्रमशः) एक मानवीय पक्ष को केन्द्र की सरकार और राज्य की सरकार ने रखने का काम किया कि दिव्यांगों के लिए भी चिन्हित कर के, वो भी अलग-अलग प्रकार से उसमें समाहित हो पाये, 03 दिसम्बर, 2021 को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिले, प्रखंड में दिव्यांग बच्चों के बीच विभिन्न प्रकार के खेलकूद एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों को भी आयोजित करने का काम किया गया था । उसके साथ-साथ जो सबसे बड़ी पहल बिहार के दृष्टि से हुई है कि दिव्यांग बच्चों के लिए शुभम् ब्रेल प्रेस, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के ब्रेल प्रेस के द्वारा निःशुल्क ब्रेल पुस्तकों को उपलब्ध कराया जाना, यह अपने आप में एक पहल जो रही है सरकार के द्वारा, बिहार की पहल प्रशंसनीय है महोदय । अध्यक्ष महोदय, माध्यमिक उ0वि0 के लिए 30,620 पदों का छठे चरण में नियोजन करने की जो कार्रवाई की जा रही है उसको भी आगे बढ़ाने का काम हुआ है । राज्य के उत्क्रमित नवस्थापित उ0वि0 के लिए भी 6,421 प्रधानाध्यापकों का पद सृजित करने का काम हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना के अन्तर्गत 7 लाख 86 हजार 414 बालिकाओं को प्रति बालिका 3 हजार रू0 की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से जो देने का काम हुआ है, 2 अरब 35 करोड़ 92 लाख 42 हजार रू0 उपलब्ध कराया गया है जिससे अपने आप में एक पहल, ये बिहार का पूरे देश में, अपने आप में एक पहल दिखाई दी है कि बिहार में बालिका साईकिल योजना जब हमारी बालिकाएं पूरे ग्रामीण क्षेत्र में निकलकर आगे बढ़ती हैं तो अपने आप में उस हिम्मत की दाद है कि बिहार की बालिकाएं किस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रही हैं । यह एक प्रशंसनीय कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है । बालिका साईकिल योजना के साथ-साथ बालक साईकिल योजना के अन्तर्गत भी 3 हजार रू0 देने का काम हुआ है । वित्तीय वर्ष 2021-22 के तहत मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत भी डी0बी0टी0 के माध्यम से जो राशि दी गयी है, 3 अरब 9 करोड़ 47 लाख 84 हजार रू0 देने का काम हुआ है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य बालक, अल्पसंख्यक सहित जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 50 हजार के अन्तर्गत है, 34 हजार 46 छात्रों को प्रति छात्र 10 हजार रू0 की दर से डी0बी0टी0 के माध्यम से 34 करोड़ 44 लाख रू0

उपलब्ध कराया गया है यानी कि प्रोत्साहन देकर सरकार द्वारा वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम हुआ है । शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए कैरियर काउंसलिंग के लिए 'बिहार कैरियर पोर्टल' के माध्यम से भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा पंजीकृत कक्षा 10 के विद्यार्थी हेतु कैरियर गाइडेंस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 10 के लिए 13,03,968 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का काम किया गया है । बी0बी0ओ0एस0ई0 के द्वारा यानी बिहार मुक्त विद्यालीय शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड की स्थापना वर्ष 2011 में की गयी थी । उस बोर्ड के माध्यम से कक्षा 10 एवं 12 की शिक्षा प्रदान कर, उनकी परीक्षा लेकर प्रमाणीकरण करने का भी कार्य किया गया है । साथ ही, कौशल विकास के क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में मान्यता दी गयी है । यानी कि बी0बी0ओ0एस0ई0 के द्वारा कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कक्षा 06 से कक्षा 08 तक की बालिकाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, अलग अलग प्रकार से Center for Stem cell Technology ,Centre for Astronomy and Centre of Philosophy की स्थापना की गयी है । यानी की शैक्षणिक संस्थान के रूप में इसको आगे बढ़ाने के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में स्थापित तीन शैक्षणिक संस्थानों क्रमशः Centre for Geographical Studies, School of Journalism and Mass Communication and Patliputra School of Economics के साथ-साथ 03 अन्य शैक्षणिक संस्थान के रूप में Centre for Stem cell Technology , Centre for Astronomy and Centre of Philosophy की स्थापना की गयी है । राज्य सरकार द्वारा पूर्व में भी 13 सरकारी विश्वविद्यालयों के अलावा 07 निजी विश्वविद्यालयों यथा- अमिटी विश्वविद्यालय, पटना, संदीप विश्वविद्यालय, मधुबनी ऐसे निजी विश्वविद्यालयों को भी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है । अध्यक्ष महोदय, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अन्तर्गत ऐसे विद्यार्थियों को लाभ नहीं मिलने के कारण जो असुरक्षित भाव महसूस होता था सरकार ने उसको दूर करने का, उनको आगे बढ़ाने का काम किया है और अबतक कुल 1 लाख 63 हजार 331 आवेदकों में 4989 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा चुकी है । इस प्रकार से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्य योजना जैसे सफलतम योजना को आगे बढ़ाने का काम हुआ है । महोदय, विद्यालयों के पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु सभी विद्यालयों के पुस्तकालय को क्रियाशील बनाने की कार्रवाई की जा रही है । राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत, मैं बिहार सरकार को बधाई देना चाहूंगा कि यहां के भाषाओं को संरक्षित करने के लिए और बिहार की सरकार ने इसी रूप में स्वीकृत

करने का काम किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत जो स्थानीय भाषा है, यानी यहां के छात्र भी जिनको कठिनाईयां होती थीं अंग्रेजी में समझने में, बुझने में, हिन्दी में भी अब हम उसको बढ़ाते हुए, चाहे कोई इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो या मेडिकल के क्षेत्र में हो उसको आगे बढ़ाने की शिक्षा नीति जो लंबे समय से लंबित थी और नई शिक्षा नीति के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक राह देने का काम किया है । माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए बहुत-बहुत बधाई और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री को बधाई कि शिक्षा नीति को अपनाकर आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया है । यानी कि देश की नई शिक्षा नीति को अपने आप में बढ़ाने का काम हो रहा है । महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि डी0बी0टी0 के माध्यम से एक अनूठा कार्य इस राज्य के अन्तर्गत हुआ है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं । साथ ही साथ हम राज्य के सभी पहलुओं पर विशेष कर के उच्च शिक्षा के पहलुओं पर हम आगे बढ़ने का काम किये हैं ताकि उच्च शिक्षा के पहलू पर जब हम उसको आगे ले जाने का काम करेंगे तो उसका बड़ा पैमाना तय होने का काम होगा ताकि उसी के माध्यम से राज्य के सभी जिलों में जो राज्य सरकार ने तय किया था कि सभी जिलों में हम उसको आगे बढ़ायेंगे सभी जिलों में पोलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम करेंगे तो सरकार ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसको लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है । आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि टीचर की बहाली की प्रकिया भी उच्च शिक्षान्तर्गत कॉलेजों में भी करने का काम सरकार ने किया है । इसके तहत बिल्डिंग का आवंटन, बिल्डिंग को बढ़ाना सब कुछ हो चला है । जब हमलोग भी छात्र आन्दोलन के नाते विश्वविद्यालय कैम्पस में जाकर कार्य करते थे तो उस समय कैम्पस किस प्रकार की थी, विश्वविद्यालय कैम्पस में पहले किस प्रकार की दुर्दशा रहती थी लेकिन आज वहां जाने पर उच्च शिक्षा का एक परिदृश्य दिखलाई देता है । इस प्रकार हम बिहार में उच्च शिक्षा के स्वर्णिम काल की ओर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं । इसके साथ-साथ नन टीचिंग स्टाफ की बहाली करने का भी काम हमलोग कर रहे हैं, इसमें और चार चांद लगने का काम होगा । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उच्च शिक्षा में रिक्त पदों को भरने के लिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग के गठन का काम जो लंबित था उसको भी पूर्ण करके बहाली की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का काम किया है, उसके लिए भी साधुवाद है । उसको और आगे बढ़ाने का काम किया जायेगा । यानी हम उच्च शिक्षा के माध्यम से भी अलग-अलग पहलुओं से, पैमाने से देने का काम किये हैं, आज आर्यभट्ट विश्वविद्यालय से लेकर, अलग-अलग आई0आई0टी0 से लेकर, चाणक्य

लॉ यूनिवर्सिटी से लेकर, मैनेजमेंट संस्थान से लेकर, आई0आई0बी0एम0 से लेकर सभी क्षेत्रों में काम हुआ है । आज बिहार का कोई व्यक्ति अगर दूसरे जगहों पर जाता है तो महसूस करता है कि हमारे यहां भी उच्च शिक्षा का केन्द्र बिन्दु बिहार में स्थापित है जो इस बात को अवलोकित करता है और गौरवान्वित महसूस कराता है । चाहे लॉ के क्षेत्र में हो, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हो, आई0आई0टी0 के क्षेत्र में हो, सभी यहां स्थापित हैं । बिहार में इसको खुलवाने का काम हुआ है जो कि बिहार सरकार की बड़ी उपलब्धि अपने आप में है जिसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे । आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, इन धरोहरों को भी हम आगे ले जाने का काम करेंगे और अंत में बताना चाहेंगे कि हमने जो संकल्प के साथ नालंदा विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाते हुए, उसके पौराणिक इतिहास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है यह अपने आप में इतिहास को रचने का काम, बिहार में शिक्षा जगत को बढ़ाने का काम हुआ है । इस प्रकार यहां बहुआयामी चौतरफा विकास को, पूरे बिहार को पैमाना देने का काम हुआ है । यह अपने आप में अनूठा पहल है कि प्रारंभिक से लेकर, उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अलग-अलग प्रकार से इसकी गुणवत्ता के ऊपर, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सब बिन्दुओं पर हमलोगों ने विचार करने का काम किया है इसके लिए बिहार सरकार को बहुत-बहुत साधुवाद है और माननीय मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद और केन्द्र की योजना से चलने वाली माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार को भी बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री ललित नारायण मंडल ।

श्री ललित नारायण मंडल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने विधान-सभा में मुझे इस अनुपूरक प्रथम शिक्षा बजट पर बोलने का मौका दिया है । मैं शुक्रगुजार हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का जिनके सौजन्य से आज इस विधान-सभा में बोलने का हकदार हूँ । मैं शुक्रगुजार हूँ अपने मुख्य सचेतक श्री श्रवण बाबू का जिन्होंने मुझे इस विधान-सभा में बोलने का मौका दिया है । अध्यक्ष जी, इस अनुपूरक बजट की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि सरकार के शिक्षा विभाग को जितना बजट चाहिए था उतनी मांग पूरी नहीं हुई है (क्रमश:)

टर्न–13/मधुप/29.06.2022

..क्रमशः..

श्री ललित नारायण मंडल : पहले शिक्षा विभाग द्वारा कितना काम बिहार में हुआ है और कितना काम हो रहा है, अगर इसपर हमलोग गौर करें तो हमको लगेगा कि हर जगह बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग में और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत काम किया है । यहाँ पर जो बजट है शिक्षकों का चाहे प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, सभी के शिक्षकों को वेतन देना पड़ता है और जो रिटायर्ड शिक्षक हैं या कर्मचारी हैं उनको पेंशन देना पड़ता है। उसके लिए राशि की आवश्यकता पड़ती है । हमारे यहाँ बहुत सारे स्कूल्स को बनाया गया है और प्राइमरी स्कूल के निर्माण में बहुत सारा खर्च होता है उसके लिए भी हमको बजट की आवश्यकता होती है ।

हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जो बिहार में बालिका शिक्षा पर जोर दिया है जैसे बालिका शिक्षा योजना है उसी को देखकर जब बालकों ने माँग किया तो इन्होंने बालक साइकिल योजना भी लागू किया है । उसके लिए भी बजट की आवश्यकता होती है । बजट का प्रावधान है शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है । उसी प्रकार जो लड़कियाँ इन्टर पास करती हैं, फर्स्ट डिवीजन जो करती हैं, 10 हजार रू0 से बढ़ाकर 25 हजार रू0 का प्रोत्साहन राशि उसको दिया जाता है । जो लड़कियाँ बी0एस0सी0/बी0ए0 पास करती हैं, स्नातक पास करती हैं, उनको 50 हजार रू0 एक बार प्रोत्साहन राशि दिया जाता है जिससे कि बच्चियाँ आगे की पढ़ाई अपना जारी रखे । उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी हो इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री महोदय यह सब प्रावधान किया है । इसके लिए भी हमें बजट में राशि की आवश्यकता पड़ती है ।

बहुत सारी योजनाएँ शिक्षा विभाग में ऐसी चल रही हैं जिसकी चर्चा अगर हमलोग करें तो बहुत समय लगेगा । हमारे मित्र ने अभी शिक्षा बजट पर चर्चा किया है । बहुत सारी योजनाएँ ऐसी हैं जिसकी चर्चा हमलोग करना चाहेंगे । नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रबंधन एवं वेतन–पेंशन भुगतान, मध्य विद्यालय के छात्रों के परिभ्रमण, सर्व शिक्षा अभियान, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, मुख्यमंत्री बालक–बालिका साइकिल योजना, पोशाक योजना, बिहार स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड, आप जानते हैं कि हमारे गरीब बच्चे जब आगे पढ़ नहीं पाते हैं, आगे की पढ़ाई उनकी नहीं चल पाती है, लोन नहीं मिलता है तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने उसके लिए स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था किया कि हमारे विद्यार्थी गरीबी के कारण इधर–उधर से लोन नहीं लेंगे

और बैंक से क्रेडिट कार्ड से लोन लेकर अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे । इन्होंने यह भी घोषणा किया है कि नौकरी लगने के बाद ही उनको लौटाना और अगर कहीं असमर्थता हुई तो बिहार सरकार उसके लिए खुद सक्षम होगा, ऐसी घोषणा हुई है ।

अध्यक्ष जी, यह अनुपूरक बजट है । जितनी राशि का डिमांड हुआ था उस राशि में कुछ कमी आयी है, जैसे कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट प्राक्कलन में राज्य स्कीम मद में शिक्षा विभाग द्वारा 17538.79 करोड़ रू0 की मॉग प्रस्तावित थी जिसके विरूद्ध मात्र 7012 करोड़ रू0 ही विभाग को प्राप्त हुई है तथा केन्द्र प्रायोजित योजना में केन्द्रांश की राशि के रूप में विभाग 6785.38 करोड़ रू0 प्राप्त होने की अपेक्षा की थी परन्तु अपेक्षा अनुरूप केन्द्र से राशि प्राप्त नहीं हो सकी । सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत शिक्षकों को 15 परसेंट वेतन वृद्धि का बकाया भुगतान करना भी अनिवार्य है जिसके कारण जो राशि की कमी आयी है वह लगभग 94.40 करोड़ रू0 का प्रस्ताव है । राज्य स्कीम में शिक्षा विभाग द्वारा 17538.79 करोड़ रू0 की मॉग प्रस्तावित थी जिसके विरूद्ध मात्र 7012 करोड़ रू0 ही विभाग को प्राप्त हुई है । लाभुक आधारित योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इसमें 1291.38 करोड़ रू0 का प्रस्ताव है जो मिलना चाहिये इसको अनुपूरक बजट के रूप में । मध्याह्न भोजन योजना में भी इसी तरह से कुछ राशि में कमी आयी है, 856.28 करोड़ रू0 का उसमें प्रस्ताव है अनुपूरक बजट के रूप में, महादलित एवं अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग अक्षर ऑचल योजना के तहत शिक्षा विभाग के द्वारा 476 करोड़ रू0 की मॉग की गयी थी लेकिन विभाग को इस मद हेतु केवल 300 करोड़ रू0 ही प्राप्त हुई है इसलिये अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु 180.36 करोड़ रू0 का अतिरिक्त अनुपूरक मॉग का प्रस्ताव है । स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में नियोजित शिक्षकों को 200 रू0 प्रतिमाह पेंशन हेतु यू0टी0आई0 को भुगतान दी जानी है इस मद में भी समेकित रूप से 215.08 करोड़ रू0 का प्रावधान है ।

अध्यक्ष जी, अगर हम प्वायंट-वाइज देखते जायें तो बहुत लम्बी सूची होगी और सब मिलाकर हम देखते हैं कि स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत कुल 2,15,08,27,000 रू0 मात्र का प्रथम अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । उसी तरह केन्द्र प्रायोजित एवं राज्य योजना अन्तर्गत जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना, सेनिटरी नैपकिन इत्यादि में, बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका योजना, पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना, छात्रवृत्ति योजना, इन सबको मिलाकर लगभग 12,91,38,00,000 रू0 मात्र

का प्रथम अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । समग्र शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना, राज्य के प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत शिक्षा के अधिकार, मध्याह्न भोजन योजना, महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अंक्षर ऑचल योजना, इन सभी योजनाओं में जो केन्द्र प्रायोजित और राज्य योजना अन्तर्गत 118,78,42,00,000 रू0 मात्र प्रथम अनुपूरक से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

..क्रमशः..

टर्न–14/आजाद/29.06.2022

.... क्रमशः ....

श्री ललित नारायण मंडल : अध्यक्ष जी, हम जानते हैं कि जब हम कोई बजट बनाते हैं और बजट को पूरा करने के लिए जब तक राशि पूरी हमको नहीं मिलेगी, तब तक हम विकास का काम नहीं कर सकेंगे । हमारा जो शिक्षा का बजट है, उसके बारे में हमने सुना अपने मित्रों से और प्वायंटवाईज हमने देखा कि जितनी अपेक्षा हमको थी, जितना बजट में प्रावधान किये थे, उतना नहीं मिल सका । इसलिए प्रथम अनुपूरक बजट में हम सदन से अनुरोध करते हैं कि अनुपूरक व्यय विवरणी के इस प्रस्ताव को पारित किया जाय एवं बिहार में शिक्षा के विकास के लिए किये जा रहे प्रयासों के प्रति सकारात्मक समर्थन व्यक्त किया जाय । जयहिन्द ।

अध्यक्ष : बहुत कम समय बोलें ।

श्री ललित नारायण मंडल : कहा जायेगा सर तो और बोलेंगे ।

अध्यक्ष : मैटेरियल खतम हो गया ।

श्री ललित नारायण मंडल : बोले सर, आदेश ।

अध्यक्ष : शिक्षा पर कुछ विचार है, शिक्षा से जुड़े हैं ।

श्री ललित नारायण मंडल : ठीक है सर । अध्यक्ष महोदय, बहुत अच्छा लगा ।

अध्यक्ष : दिल से बोलियेगा तो बहुत अच्छी बात आयेगी ।

श्री ललित नारायण मंडल : जी सर, बहुत अच्छा लगा कि हमको और अधिक बोलने का मौका मिला है । आपके जैसा अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री के रूप में बड़े भाई, मुख्यमंत्री के रूप में बहुत अच्छा आदर्श पुरूष और हमारे मुख्य सचेतक के रूप में हमें बड़ा भाई मिला है । यह हमारे लिए बहुत गौरव की बात है ।

शिक्षा विभाग में हम खुद शिक्षक रहे हैं और हम जानते हैं कि शिक्षा विभाग में कितना खर्च होता है और आज कितने सारे मध्य विद्यालयों को हाई स्कूल के रूप में प्रोन्नत किया गया है । आप जाकर देखिए, हम सब लोग

अपने-अपने इलाकों में घुमते हैं । आज एक भी पंचायत ऐसा नहीं बचा है, जहां पर कि हाई स्कूल नहीं है । बिहार सरकार के शिक्षा नीति के कारण आज हमारे पंचायतों में हाई स्कूल है । आज हम अपने दिनों को याद करते हैं, अगर याद करें तो हमलोग दूर-दूर तक पढ़ने के लिए जाते थे हाई स्कूल में, साईकिल लेकर के या पैदल 3-4 कोस दूर पैदल चलकर पढ़ने के लिए स्कूल जाते थे । गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में हमलोगों को बहुत परेशानी होती थी । लेकिन जब हम आज अपने गांव जाते हैं तो देखते हैं कि गांव में हाई स्कूल है । इसके लिए हम अपनी सरकार को, हम अपने शिक्षा मंत्री जी को बहुत, बहुत बधाई देते हैं कि आपने शिक्षा का इतना विकास किया है । अब तो सरकार की नीति है कि जिस पंचायत में हाई स्कूल नहीं है, वहां पर हाई स्कूल के लिए मध्य विद्यालय को उत्क्रमित कर देना है या नया हाई स्कूल खोलने की बात है । शिक्षकों की बहाली हो रही है । कल हमने अखबारों में देखा कि कॉलेज में बहुत सारे शिक्षकों की बहाली हो रही है, बहुत सारे छात्र पढ़-लिखकर के या पी0एच0ई0डी0 करके शिक्षक के रूप में ज्वाईन कर रहे हैं, यह देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है । हम कहना चाहेंगे कि हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत आदर्श के रूप में काम कर रहे हैं । अब तो बात हो रही है कि हरेक प्रखंड में, हरेक अनुमंडल में एक कॉलेज खोलने की बात हो रही है । अगर किसी प्रखंड में कॉलेज नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से कॉलेज खोलेगी ताकि बच्चों को दूर-दूर नहीं जाना पड़े । इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज इतना खोला जा रहा है कि जिस जिला में मेडिकल कॉलेज नहीं है, जिस जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव है और धड़ल्ले से खोला जा रहा है, बहुत सारा एक्जामपुल आपके सामने है । इससे क्या होगा कि हमारे जो गरीब बच्चे दूर-दूर जाकर इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकते थे, अब अपने घर से खाकर के साईकिल से आकर के इंजीनियर बनेंगे और एम0बी0बी0एस0 डॉक्टर बनेंगे और बिहार का विकास करेंगे, बिहार का सेवा करेंगे। इसके लिए हम बिहार सरकार को बहुत, बहुत बधाई देते हैं कि आपने बिहार के विकास के लिए, बिहार को शिक्षित करने के लिए आपने बहुत सारा योगदान दिया है ।

अब बहुत सारे हमारे मित्र बोलेंगे, हम अनुपूरक बजट की बात करने आये हैं, हम अनुपूरक बजट की बात करते हैं । अध्यक्ष महोदय, हम सदन से फिर अनुरोध करते हैं कि जो बिहार सरकार को , शिक्षा विभाग को आगे बढ़ाने के लिए

जो पैसे की कमी हो रही है, उस प्रस्ताव को, हमलोग अनुपूरक बजट को पास करें।

अध्यक्ष : आपके पास तो इतना बड़ा भंडार है नई शिक्षा नीति पर, उसपर आपने कोई चर्चा नहीं की । कॉलेज में एक-एक, डेढ़-डेढ़ घंटा क्लास लेते हैं ।

श्री ललित नारायण मंडल : जी सर, लेते हैं ।

अध्यक्ष : ठीक है अब बैठ जाइए माननीय सदस्य ।

श्री ललित नारायण मंडल : धन्यवाद सर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कुमार शैलेन्द्र ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत खुशी लग रहा है कि आदरणीय शिक्षा मंत्री जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में शिक्षा विभाग का वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग के समर्थन के लिए हम खड़ा हुए हैं । महोदय, शिक्षा पर चर्चा हो रही है और सामने जो विपक्ष की भूमिका है और जनता ने जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए इनको दिया है, आज इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि ये हमारे बिहार के लिए शिक्षा के प्रति कितने जागरूक हैं, मैं अपने तमाम साथियों के माध्यम से विपक्ष को आग्रह करता हूँ कि आप भी आये और यहां पर इस डिवेट में भाग लें क्योंकि बिना शिक्षा प्राप्त किये कोई व्यक्ति अपने परम ऊँचाईयों को छू नहीं सकता । शिक्षा मनुष्य के अन्दर अच्छे विचारों को लाती है और बुरे विचारों को बाहर करती है । शिक्षा मनुष्य के जीवन का मार्ग दिखाती है, यह मनुष्य को समाज में प्रतिष्ठित काम करने के लिए प्रेरणा देती है । आज आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जो दिन-रात बिहार में शिक्षा का स्तर ऊँचा हो, विद्यालय में बच्चे अधिक से अधिक आये, विद्यालय में अगर बच्चों को पढ़ने के लिए कमरे नहीं हों तो उनको कमरा कैसे बनाया जाय तो ऐसे अपने शिक्षा मंत्री जी के लिए -

जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है,
हमारे इरादों का अभी इम्तहान बाकी है,
अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन,
अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है।

ऐसे यशस्वी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी जो अपने यहां दिन-रात काम कर रहे हैं और हमें भी उनके मार्गदर्शन में काम करने का मौका मिला है ।

टर्न-15/शंभु/29.06.22

अध्यक्ष : जारी रहे क्रम ।

श्री कुमार शैलेन्द्र : असल में शिक्षा विभाग इतना व्यापक स्तर है- शिक्षा में जो काम हो रहा है । पहले राजद शासनकाल में क्या था कि कहीं स्कूल नहीं थे, कमरे नहीं थे, लेकिन आज जब बिहार से बाहर के लोग आते हैं तो चमचमाती स्कूल को देखकर सड़कों पर जब बच्चियां चलती है और वह साइकिल पर चलती है, पोशाक में एक तरह से जो दृश्य रहता है उसको देखकर बाहर के लोग भी कहते हैं कि अब सुशासन का बिहार आये हैं, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश जी का बिहार आये हैं, लेकिन 15 साल पहले जब कोई बाहर से बिहार आते थे तो उनकी गाड़ी डगमगाने लगती थी, एक्सीडेंट हो जाता था, गड्ढों से भरा बिहार था और उसको देखकर या समझकर कहने लगते थे कि यह राजद शासनकाल यानी लालू राबड़ी का बिहार आया है । यह अंतर आया है पहले और अभी के बिहार में । महोदय, राजद शासनकाल में शिक्षा का क्या माहौल था चरवाहा विद्यालय खोला जाता था और उनके 15 वर्षों में जो उनका स्वर्णिम काल था, शिक्षकों से कितना प्रेम करते थे या शिक्षा के प्रति इनकी कितनी अभिरूचि थी इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि 15 वर्षों में केवल मात्र 30 हजार शिक्षक की बहाली हुई । इतना ही इनका शिक्षा से प्रेम था कि 15 वर्षों में शिक्षकों की बहाली केवल 30 हजार किया। वहीं आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब बिहार की बागडोर को संभाले तो 2 लाख 36 हजार शिक्षक की भर्त्ती किये । महोदय, यह सिलसिला चलता रहा और अभी 4 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है । महोदय, जब साइकिल योजना लायी गयी थी तो ये लोग हंसी उड़ाते थे कहते थे कि लड़की साइकिल चलायेगी । पोशाक योजना- वर्ग 1 से 8 तक महोदय 65878 बच्चों के लिए 1 करोड़ 29 लाख का- महोदय, पहले बच्चों की पढ़ाई में विसंगतियां थी, अमीर और गरीब बच्चे में फर्क था । गरीब बच्चे बिना पुस्तक के पढ़ नहीं पाते थे । हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री विजय बाबू ने उन गरीब बच्चों के लिए जो अमीर बच्चों के आगे पढ़ नहीं पाते थे, न उनके पास किताब होता था, न उनके पास अच्छा पोशाक होता था । वह घर में जाकर अपनी मां के पास रोती थी और कहती थी कि मां हमारे पास तो किताब नहीं है, पिताजी हमारे पास पोशाक नहीं है हम कैसे विद्यालय जायेंगे ? हमें शर्म आती है, लेकिन आज हम धन्यवाद देते हैं अपने यशस्वी शिक्षा मंत्री को अपने शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि इन्होंने पोशाक के लिए जो बच्चों को राशि दिया है वर्ग-1 से 8 तक के लिए 1 करोड़ 29 लाख जो 65878 बच्चे आज पुस्तक खरीद रहे हैं । महोदय, पहले

जब बच्चे स्कूल जाते थे तो पहनावा से साफ-साफ दिखायी देता था और जो बच्चे गरीब होते थे वह अपने को हीन भावना से ग्रस्त समझते थे क्योंकि बड़े घराने के बच्चे तो अच्छे-अच्छे कपड़े पहन के जाते थे । उनको लगता था कि उनके मां बाप को पैसा है वे अच्छे ड्रेस देते थे, लेकिन गरीब मां बाप जो अपना घर भी नहीं चला पाते थे वे बच्चे को अच्छा ड्रेस कहां से देते, अच्छा जूता कहां से देते । आज आदरणीय यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी बच्चों को पोशाक यानी स्कूल ड्रेस उसके लिए 898.15 करोड़ रूपया डायरेक्ट डी0बी0टी0 के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया है । महोदय, हमारी जो कमजोर वर्ग की बालिका है, जो उपेक्षित थी, समाज में कमजोर थी वह स्कूल जाने से कतराती थी, लेकिन उस बच्चे को धन्य हैं हमारी आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप गरीबों के मसीहा हैं । आपने गरीबी क्या होती है करीब से देखा है । आपकी आंखों के सामने जब शुरूआती दौर में जब राजनीति शुरू की तो आपने देखा कि कमजोर वर्ग की बालिका को कैसी-कैसी यातनाएं शिक्षा के बिना झेलनी पड़ती है । आप उसी वक्त सपना देखे थे जब देव दुर्लभ जनता मालिक मौका देगी तो उपेक्षित और कमजोर वर्ग की बालिका के लिए काम करेंगे और आज उसी का परिणाम है कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए राज्य में 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोलकर कुल 50963 बालिकाएं पढ़ रही है । यह कस्तूरबा गांधी विद्यालय है । बच्ची क्या होती थी शर्म से स्कूल नहीं जा पाती थी, कमजोर वर्ग की बालिकाएं स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री ने 535 कस्तूरबा गांधी विद्यालय बालिका के लिए खोला गया है । हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी उन कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए भी जो हमारी बच्ची पढ़ नहीं पाती थी उनको पढ़ने के लिए कस्तूरबा गांधी का और विद्यालय में रहने की व्यवस्था भी की है । महोदय, हमारे शिक्षा अभियान के तहत 21286 नये प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के साथ-साथ 19633 प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया । महोदय, हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो कई विकट परिस्थितियां भी सामने आती है- बच्चे अधिक हैं, कमरा कम है और कहीं कमरा है तो बच्चे कम हैं और यदि दोनों हैं तो शिक्षक की कमी है । हम अपने यशस्वी शिक्षा मंत्री से इस बात के लिए संवाद किया कि आखिर ये विसंगतियां कैसे दूर होगी । इन्होंने कहा कि इंजीनियर शैलेन्द्र जी आप जाइये अपने क्षेत्र में और पूरे विधान सभा में जहां-जहां जो कमी हो उसको हमें बताइये, हम उसको दूर करेंगे और जो मैंने लिखकर दिया वह इन्होंने पूरा भी किया । अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहते हैं कि एक बहुत बढ़िया सलाह इन्होंने दिया था और मैंने उस सलाह

को माना भी । इन्होंने कहा कि आप विधायक जी स्कूल जाइये, स्कूल में बच्चे के साथ बैठिए, आप वहां पर शिक्षक के साथ संवाद कीजिए । हमने वहां की कमियों को देखा, हम जब साढ़े 6 बजे मॉर्निंग क्लास होता था तो हम वहां गये और साढ़े 6 बजे बच्चों के साथ झाड़ू लगाये, वहां पर प्रार्थना किये उसके बाद उसके बाद जो क्लास चलता था 11 बजे तक चार क्लास में पीछे जाकर बैठे भी- टीचर कैसे पढ़ाते थे उस पढ़ाई को भी मैंने देखा और जब क्लास समाप्त हुआ तो सारे टीचर को एक साथ हेड मास्टर के रूम में बैठाया और जो अच्छा पढ़ाते थे उनको मैंने पुरस्कार भी दिया । ये सारा हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बताया था कि तुम करो यह काम और मैं वह कर रहा हूँ । आज उसका परिणाम है महोदय वहां पर शिक्षक नहीं थे शिक्षक की कमी थी वहां पर हमलोग गांव में घूमकर जो बच्चे अभी पढ़ाई करके बैठे हुए थे ।

क्रमशः

टर्न-16/पुलकित/29.06.2022

श्री कुमार शैलेन्द्र (क्रमशः) : क्योंकि कक्षा एक से कक्षा आठ तक पढ़ाने के लिए कोई आई0आई0टी0एन0 नहीं चाहिए, कोई आई0ए0एस0 नहीं चाहिए, कोई आई0पी0एस0 नहीं चाहिए तो वैसे बच्चों के साथ हमने आग्रह किया और वे बच्चे क्लास लेने शुरू किये और वे बच्चे पढ़ने के लिए जाने लगे और जब क्लास समाप्त होती थी तो प्रत्येक वर्ग से पांच लड़कियां और पांच बच्चे जो अबसेंट होते थे, उनके अभिभावकों से मोबाइल पर बात करते थे । उनको आश्चर्य होता था कि एक विधायक फोन पर बात कर रहा है और उनको बुलाते थे कि आपकी बच्ची क्यों नहीं आयी ? आपके बच्चे क्यों नहीं आये और जब मैंने यह शुरू किया तो बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी । कोरोना काल में जो डर, भय समा गया था उसको भी हमलोग धीरे-धीरे समाप्त कर रहे हैं । कहीं-कहीं ऐसी भी परिस्थिति आई कि लोग, गार्जियन जो आते थे और कई तरह की विसंगतियां और कई तरह की शिकायतें करने लगे । मैंने कहा कि पूर्व काल में क्या होता था ? जब हमारे पिता जी पढ़ा करते थे तो दूर-दूर से बक्सर के, आरा के, छपरा के टीचर हमारे घर पर रहते थे और हम दरवाजे पर सोते थे । हम सुबह का इंतजार करते थे कि हम कब उनको कुएं पर स्नान करने के लिए ले जाए और उनको स्नान कराते थे । हमारी माताएं-बहनें भी इंतजार करती थी कि वे टीचर कब स्नान करके आयेंगे, ताकि उनको हम खाना खिलायें । लेकिन आज वह संस्कार कहां चला गया, आज वह संस्कार क्यों नहीं है ? न अभिभावक में है, न टीचर में है और न बच्चे में हैं । यह सामंजस्य करना पड़ेगा और मैंने अभिभावकों के साथ संवाद किया कि पूर्व में

हमारे पूर्वज शिक्षकों के प्रति समानता किया करते थे वह सम्मान आप शिक्षकों को दीजिये । शिक्षक जो पढ़ाना नहीं जानते, जो कमी है उसमें, उसके लिए भी हमलोगों ने व्यवस्था की हैं । इसलिए हम अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हमलोग भी बहुत व्यवस्था कर रहे हैं । हमलोग भी स्कूल जाकर अपनी बातों को बताते हैं । हमलोग चाहते हैं कि शिक्षा में और गुणवोत्तर सुधार हो । आप बहुत काम कर रहे हैं । यह जो लिखा हुआ है, इसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है चूंकि सभी जानते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है लेकिन कुछ मूलभूत समस्या हैं । उस समस्या का निदान जरूर हो क्योंकि जो व्यवस्था है हमने हर पंचायत में हाई स्कूल खोल दिये, हमने उत्क्रमित भी कर दिया और हमने प्लस-टू कर दिया लेकिन उसमें टीचरों की अभी भी कमी है । हम टीचर खोज रहे हैं । गांव में, समाज में हम सरकार की मदद कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो क्योंकि खुद हमारे नीतीश कुमार जी इंजीनियर हैं, हमारे विद्वानजन शिक्षा मंत्री हैं । हम चाहते हैं कि हमारे बिहार का विकास हो लेकिन उसमें जो गुणवोत्तर सुधार होना चाहिए । उस सुधार में इनकी महती भूमिका है । हम इनसे आग्रह करते हैं कि जहां भी अभी शिक्षकों की कमी हैं, विद्यालयों में कमरों की कमी हैं, कहीं-कहीं शौचालयों की कमी हैं और कहीं-कहीं बाउंड्री की कमी हैं । जब इन्होंने कहा तब इनके आग्रह पर ही मैंने कहा कि बाउंड्री नहीं है, कमरा नहीं है । इन्होंने कहा कि विधायक जी आप अपना निधि भी दे सकते हैं । मैं आज आपको बताते हुए गर्व महसूस कर रहा हूं कि 03 करोड़ में 70 परसेंट यानी 02 करोड़ 10 लाख मैंने लिख दिया है । विद्यालय में कहीं कमरा नहीं है, कहीं शौचालय नहीं है, कहीं बाउंड्री नहीं है । मैंने 02 करोड़ 10 लाख रूपया अपने क्षेत्र के विद्यालयों के लिए लिख दिया है लेकिन उसके बावजूद भी उससे क्या होना है ? इसलिए मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि समीक्षा करिये । अच्छे ढंग से बच्चे पढ़ें चूंकि बच्चे जबतक नहीं पढ़ेंगे तब तक वे सरकारी अनाज खाने के लिए मजबूर रहेंगे क्योंकि उनके गार्जियन, उनके बच्चे अभी भी राशन की दुकान पर भीड़ लगाते हैं, क्योंकि उनके मां-बाप उनको नहीं पढ़ायें । क्या हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा भी वही राशन की दुकान पर जाये । उसी राशन की दुकान में लाईन लगाये । अगर इससे मुक्ति दिलाना चाहते हैं तो बच्चों में सुधार करना और बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी । इसके लिए सफल प्रयास करना होगा । महोदय, बस इतना ही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : आज बड़ी जल्दी सब लोग थक रहे हैं । माननीय सदस्य, श्री पंकज कुमार मिश्र ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, सप्तदश बिहार विधान सभा के षष्ठम सत्र में शिक्षा के प्रथम अनुपूरक एवं सरकार की उपलब्धियों पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं । हमलोग जानते हैं कि बिहार अत्यंत कालांतर से ही ज्ञान की धरती रही है । यह विज्ञान की जननी भी रही है । यहां भगवान, बुद्ध, महावीर और आर्यभट्ट जैसे महाज्ञानी अपने ज्ञान से देश और दुनिया को प्रकाशित किये हैं । यहां नालंदा एवं विक्रमशिला जैसे महा विश्वविद्यालय हुए हैं जिसने बिहार के गौरव को पूरे विश्व में बढ़ाया । आज बिहार सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री बालक साईकिल योजना, मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना, बालिका पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मध्याह्न भोजन योजना जैसी अनेकों योजना संचालित की जा रही है । जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन हो रहे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री एवं सरकार के शिक्षा मंत्री के प्रति गंभीरता, सजगता को दर्शाते हैं । आज माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा जी के द्वारा शिक्षा के लिये जो कार्य किया जा रहा है इसके लिए मेरी तरफ से कोटि-कोटि और पूरे बिहार की जनता की तरफ से मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आज जो शिक्षा व्यवस्था इतनी बढ़िया, सुदृढ़ ढंग से चल रही है । जब कभी हमलोग स्कूल में जाते थे, हमलोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हुए हैं । आज भी सरकारी स्कूल की जो व्यवस्था है जो माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो काम किया जा रहा है । उस व्यवस्था पर मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज की डेट में बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है ।

अध्यक्ष : आसन की ओर देखकर बोलिये । आप बार-बार माननीय सदस्य, श्री राणा रणधीर जी को देख रहे हैं ।

श्री पंकज कुमार मिश्र : सरकार द्वारा चलायी जा रही सभी योजनाओं से राज्य में साक्षरता दर एवं शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है । महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक, अतिपिछड़ा वर्ग, आरक्षण योजना संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत 300 करोड़ की राशि दी गयी है । जिससे समाज के हरेक तबकों के बच्चों को शिक्षा पहुंच रही हैं एवं राज्य में साक्षरता दर में वृद्धि हो रही है । जो सरकार की दूरदर्शिता को परिलक्षित करती है ।

आज राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों को बिजली से आच्छादित किया जा चुका है जिससे विद्यालय में बुनियादी अवसर का विकास हुआ है । जिसका प्रत्यक्ष भाव राज्य में दिख रहा है । आज सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजनाओं से राज्य में न सिर्फ शिक्षा का विकास हुआ है बल्कि बच्चों को पढ़ाई के साथ पौष्टिक आहार दिया जा रहा है जिससे कुपोषण जैसी

समस्या को दूर करने में मदद मिल रही है । राज्य में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में डिजिटल शिक्षा का महत्व बढ़ गया है । इस दिशा में सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सभी 30,300 मिडिल स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था को प्रभावित ढंग से लागू करने एवं स्कूलों में बच्चों के लिए डिजिटल शिक्षा के लिए मददगार साबित होगा । इससे उनका भविष्य उज्ज्वल होगा और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी डिजिटल भारत की अवधारणा को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा । आज बिहार में 71,832 विद्यालयों में 2 करोड़ 34 लाख छात्रों का नामांकन हैं और वे पढ़ाई कर रहे हैं । वर्ष 2004-05 के दौरान जो साक्षरता दर 47 प्रतिशत थी, आज वह 70 प्रतिशत हो गयी है । जो सरकार के अथक प्रयास का नतीजा है । अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : शब्दों को कोई स्पर्श नहीं कर सकता लेकिन शब्द सबको स्पर्श कर लेते हैं । शब्द की कमी कहीं-न-कहीं इस सदन में खल रही है ।

माननीय सदस्य, श्री रत्नेश सादा ।

टर्न-17/अभिनीत/29.06.2022

श्री रत्नेश सादा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आज शिक्षा विभाग के अनुपूरक अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार और शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई क्रांति लायी है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आजादी से लेकर 2005 तक शिक्षा व्यवस्था इतनी गिरी हुई थी कि लोग, गरीब-गुरबे के बच्चे दूर-दूर तक पढ़ने जाते थे और शिक्षा की कमी महसूस होती थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर का दूसरा रूप धारण करके शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाये हैं । माननीय महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी पंचायतों के मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करते हुए टेन प्लस टू की व्यवस्था लागू की है जिससे दलित हो, महादलित हो या अतिपिछड़ा का बाल-बच्चा हो सभी को मैट्रिक से इंटर तक पढ़ने की सुविधा मुहैया कराने का काम किया गया है । महोदय, यह एक सराहनीय काम है । हमारी बच्ची जो 5 किलोमीटर दूर तक पढ़ने के लिए जाती थी आज वह घर में ही टेन प्लस टू की शिक्षा प्राप्त करेगी । महोदय, माननीय मुख्यमंत्री ने बच्चे और बच्ची को शिक्षा से जोड़ने के लिए, उनमें लगन पैदा करने

के लिए साईकिल योजना चलाकर एक क्रांति इस 21वीं सदी में लायी है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आज आप देखेंगे कि अगर बच्ची स्कूल जाती है तो पता नहीं लगता है कि कौन अमीर की बच्ची है, कौन गरीब की बच्ची है सबका एक ड्रेस, एक पोशाक रहता है और सब एक कतार से साईकिल पर चढ़कर चलती है महोदय । आज माननीय मुख्यमंत्री की देन है कि इस तरह की नई क्रांति आयी है । महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा वह तलवार है जो अंधकार रूपी विशाल वृक्ष को काटते हुए ज्ञानरूपी प्रकाश लेकर और सरकार की नई-नई योजना को लेकर काम करती है । महोदय, आज शिक्षा नहीं रहती तो मैं यहां तक नहीं आता । जिस समाज से मैं आता हूं महोदय, उस समाज में गिने-चुने ही पढ़े-लिखे होते हैं लेकिन महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिस शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीने के बाद हम अंधकार रूपी वृक्ष से लड़ सकते हैं । इसी पर मैंने संस्कृत में पढ़ा था-

विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन,
स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते ।
माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः
न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये बको यथा ।

महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि विद्वान और राजा में बहुत अंतर होता है । आज अगर कोई राजा है तो अपने राज्य भर में ही उसका नाम प्रचलित होगा लेकिन अगर कोई विद्वान है, डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उनकी देश ही नहीं विदेशों में चर्चा होती थी इसलिए विद्वान की विद्वता के आगे राजा की बराबरी नहीं होती है। जो मां-बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं उससे बड़ा शत्रू इस दुनिया में कोई नहीं है ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अगर आज हमारे मां-बाप नहीं पढ़ाते तो आपके बीच महोदय, मैं यहां विधायक नहीं बनता, इसलिए शिक्षा रूपी तलवार से हमें अंधकार रूपी विशाल वृक्ष को काटने की जरूरत है । माननीय महोदय, मैं शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अभी भी हमारे समाज में शिक्षा के प्रति उतनी जागरूकता नहीं है । महोदय, मैं आपसे और प्रधान सचिव से निवेदन करूंगा कि आप खासकर महादलित बस्तियों में शिक्षा का जन-जागरण चला दें ताकि हमारे समाज की माता-बहनें और गार्जियन में शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो और अपने बच्चों को स्कूल भेजने का काम करें । आपने तो बच्चों के लिए पोशाक राशि की व्यवस्था किया है, यह भी बहुत

अच्छी बात है । भोजन की व्यवस्था किये हैं लेकिन उनमें जागरूकता की कमी है, वे स्कूल जाने से कतराते हैं । महोदय, सरकारी स्तर पर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था, जन-जागरण की व्यवस्था हो जाये, खासकर महादलित मुसहर समुदाय के बीच में जो पढ़ने से भागते हैं । मैं सच्ची बात कह रहा हूं शिक्षा मंत्री महोदय कि इस पर थोड़ा गंभीारतापूर्वक विचार किया जाय । प्रधान सचिव महोदय, आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस पर एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाय और खासकर महादलित मुसहर के बच्चे जो स्कूल नहीं जाते हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । महोदय, वैसे बहुत सारे संगठन शिक्षा पर काम रहे हैं, खासकर मुसहर के बच्चों के बीच में लेकिन अगर बिहार सरकार की ओर से इस तरह की मुहिम चलायी जायेगी तो हमारे समाज का आगे आने वाले दिनों में, भविष्य में कल्याण होगा नहीं तो यह समाज शिक्षा से बहुत दूर रहेगा । तो, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन, विद्वान और राजा में बहुत फर्क होता है । स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, राजा की पूजा राज्य भर में होती है और विद्वान की पूजा पूरे देश में होती है, पूरे विश्व में होती है । माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः, जो मां-बाप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है । पंचवसानी लाड्यते, पांच वर्ष तक बच्चे को लाड-प्यार करना चाहिये । दसवसानी ताज्यते, दस वर्षों तक महोदय, जैसे कुम्हार अपने बर्तन का सृजन करता है, उसको चोट मारकर बड़ा करता है उसी तरह 10 वर्ष तक बच्चे को शासन करके स्कूल भेजने का काम करें । महोदय, मैं विशेष करके शिक्षा मंत्री से कहूंगा कि हमारे महादलित परिवार के बच्चों की पोशाक राशि जो बंद हो गयी है उसे भी चालू करने का काम करें । महोदय, मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ समाप्त करता हूं । जय हिन्द, जय बिहार, जय नीतीश कुमार ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राज कुमार सिंह ।

श्री राज कुमार सिंह : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आज आकस्मिक रूप से बोलने का निर्देश दिया गया है । वैसे जब मैं इस सदन में आया और आज वाद-विवाद का कार्यक्रम पहले से निर्धारित था तो हमने जो राजनीति विज्ञान में पढ़ा था कि विपक्ष के द्वारा जब कटौती प्रस्ताव लाया जाता है तो वह सभी सदस्यों को वाद-विवाद करने का एक अवसर प्रदान करता है । लेकिन आज मैं अचंभित हुआ कि विपक्ष द्वारा बगैर किसी कटौती प्रस्ताव के भी हमलोग आज यहां वाद-विवाद में शामिल हैं इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय का शुक्रगुजार हूं, उनको धन्यवाद देता हूं । अपनी सरकार, अपने मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि विपक्ष के द्वारा बिना किसी

कटौती प्रस्ताव के हमलोग सरकार की नीतियों पर विमर्श कर रहे हैं । सरकार ने अपनी सारी योजनाएं सदन के माध्यम से प्रस्तुत कर दी हैं, तो उन आंकड़ों में ज्यादा जाने की आवश्कता नहीं है और आंकड़े मेरे पास अभी उपलब्ध हैं भी नहीं। मैं इतना जानता हूं कि वर्ष 2022-23 के लिए जो लगभग साढ़े 17 हजार करोड़ से अधिक का व्यय होना था उसमें विभाग को समुचित मात्रा में राशि उपलब्ध नहीं हो पायी जिसके कारण विभाग को यह अनुपूरक बजट लाने की आवश्यकता पड़ी है । एक जो खेद की बात है कि अभी तक बिहार सरकार को केंद्रांश की राशि भी विभिन्न मदों में उचित मात्रा में नहीं मिल पायी है जिसके कारण इस अनुपूरक बजट की आवश्यकता पड़ी है । हम सभी जानते हैं कि बिहार ज्ञान की, विज्ञान की और महापुरूषों की धरती रही है लेकिन कालांतर में...

-क्रमशः-

टर्न-18/हेमन्त/29.06.2022

श्री राज कुमार सिंह(क्रमशः) : बिहार की शिक्षा का जैसे-जैसे अवमूल्यन होता गया और उसमें जो 15 वर्षों का शासनकाल रहा, लगभग 1990 से लेकर 2005 तक का, वह बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में इतना पीछे ले गया कि सरकार के द्वारा विगत 15 वर्षों में किये जा रहे अभूतपूर्व कार्यों के बावजूद भी शिक्षा के कई क्षेत्रों में हम लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं । विपक्ष के लोग रहते तो शायद इसका महत्व समझते। अगर वह होते तो, चूंकि मैं दिनकर की जन्मभूमि से हूं, तो मैं उनको जरूर कहता कि

अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा ।

साक्षी हैं जिनकी महिमा के सूर्य, चन्द्र, भूगोल, खगोल,

कलम आज उनकी जय बोल ।

इस कलम की महिमा तभी समझ में आती है जब बिहार का हर युवा, हर बच्चा, हर परिवार शिक्षित होता है और माननीय शिक्षा मंत्री जैसे विद्वान, प्रबोध और सतत शिक्षा के प्रति प्रयत्नशील जो इनके विचार रहे हैं उसकी वजह है कि आज हम लोग सर ऊंचा कर किसी भी राज्य में जाते हैं तो अपने बिहार की शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करते हैं । बिहार के छात्र काफी मेधावी हुआ करते हैं और पहले भी जब हम बाहर पढ़ने जाते थे, पहले जब यहां पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं

थी, तो लोग कहते थे कि आप बिहार से यहां क्यों आये हैं ? मुझे अपना याद है। मैं जब साइंस कॉलेज से रामजस कॉलेज में गया और वहां पर रैगिंग के दौरान बच्चों ने पूछा कि आप कहां से आये हैं ? यह 1987 की बात है, तो मैंने कहा कि साइंस कॉलेज से, लोगों को आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा कि साइंस कॉलेज से यहां क्या करने आ गये ? तो उस वक्त की शिक्षा व्यवस्था कमोबेश काफी अच्छी थी । लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि 1990 के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में काफी अवमूल्यन हुआ । शिक्षा पर कोई ध्यान ही नहीं दिया गया । शिक्षा के नाम पर चरवाहा विद्यालय का एक प्रपंच रचा गया । जिसके कारण शिक्षा बद से बदतर होती चली गयी । लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं अपनी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जिनके प्रगतिशील नेतृत्व में शिक्षा को महत्व दिया और विभिन्न प्रोत्साहन के माध्यमों से, चाहे बालिका साइकिल योजना हो, बालक साइकिल योजना हो, मध्याह्न भोजन योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो विभिन्न स्तरों पर बच्चों को प्रोत्साहित कर शिक्षा के प्रति उनके उत्साह को बढ़ाने का कार्य किया और उसका कारण है कि आज 47 प्रतिशत से बढ़कर आज हमारी साक्षरता दर लगभग 70 प्रतिशत से ऊपर हो चुकी है इसके लिए इस सरकार का साधुवाद सभी लोगों को देना चाहिए और हम सभी लोगों को सहयोग करना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में हम ऐसे ही विकास करते रहें । चूंकि मैं पूरी तैयारी से आया नहीं यहां पर, तो मुझे लगता है कि जो मेरी मंशा थी, तो भावना थी, एक सुझाव मैं जरूर माननीय शिक्षा मंत्री को देना चाहूंगा कि बिहार के लगभग कई स्कूलों में चाहरदीवारी नहीं बनी हुई है । मैं सुझाव यही देना चाहूंगा कि चाहरदीवारी को शिक्षा की आधारभूत संरचना का ही भाग माना जाय, उसको मुख्य अंश मानकर सभी स्कूलों में चाहरदीवारी का निर्माण यदि हो जाता है तो निश्चित रूप से काफी प्रगति होगी, लोगों को एक सुरक्षित माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए और अपने क्षेत्र के लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूर्व में भी आग्रह कर चुका हूं कि मेरे क्षेत्र में सामौह प्रखंड एक ऐसा प्रखंड है जिसे आप एक आईलैंड कह सकते हैं । एक तरफ गंगा नदी, दूसरी तरफ हरौहर नदी और बीच में वह प्रखंड जिसमें लगभग 50 हजार से अधिक आबादी के लिए उच्चतर शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वहां पर जिस प्रकार से आपने कई जिलों में विशेष परिस्थिति में उच्चतर शिक्षा के लिए महाविद्यालय की स्थापना की है उसी तरीके से सामौह को भी विशेष परिस्थिति मानते हुए वहां पर एक महाविद्यालय की स्थापना जरूर करें ताकि सामौह के लोग जो सदियों से वंचित रहे हैं भोगौलिक कारण की वजह से । उनको कम-से-कम शिक्षा के क्षेत्र में इस

सरकार के अंतर्गत, इस प्रगतिशील दूरदर्शी सरकार के अंतर्गत उनको और वंचित न रहना पड़े, क्योंकि वहां पर बहुत सारे जो लोग हैं, अभिभावक हैं सब कृषि पर आधारित हैं और सबकी आर्थिक स्थिति उनको यह साहस नहीं देती है कि वह अपने बच्चों को मुख्यालय में रखकर, वहां पर किराये का मकान लेकर वहां पर अध्यापन करा सकें । इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करूंगा, बार-बार कर चुका हूं, पुनः कर रहा हूं, अगर शिक्षा मंत्री जी की तरफ से आज कुछ आश्वासन मिल जायेगा, तो मुझे लगता है कि मैं आगे कुछ और बातें करूंगा, लेकिन सामौह के संबंध में मैं शिक्षा मंत्री जी से जरूर आग्रह करूंगा कि वहां पर एक महाविद्यालय की स्थापना निश्चित रूप से करवायें । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अनिल कुमार ।

श्री अनिल कुमार : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा विभाग के वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि राज्य सरकार सभी वर्गों के लिए खासकर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे-बच्चियों के लिए शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए कटिबद्ध है और इसके लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं । वर्तमान में कुल बजट का बड़ा भाग लगभग 20 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है । राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 90 हजार नियोजन शिक्षकों की कार्रवाई की जा रही है। 25 फरवरी, 2022 को चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र एक साथ देने की तिथि भी निर्धारित की गयी है । राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक हेतु 40518 पद, मध्य विद्यालय में शारीरिक शिक्षा अनुदेशक हेतु 8386 पदों का सृजन किया गया है । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से प्रारंभ किये गये डेडिकेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन से संबंधित शिक्षा के आलोक में बिहार सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एवं समग्र शिक्षा कार्यक्रमों को बिहार शिक्षा परियोजना के प्रतिशत से क्रियान्वित किया जा रहा है । समग्र शिक्षा के अन्तर्गत बाल शिक्षा से लेकर बारहवीं कक्षा तक की शिक्षा को आच्छादित किया जा रहा है । अनेक योजनाएं चल रही हैं, सब हम जानते हैं कि बिहार में प्रत्येक जिले के एक-एक उच्च विद्यालय को चिन्हित कर अनुकरणीय मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री बालक साइकिल योजना, मुख्यमंत्री पोशाक योजना, मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना । इतनी सारी योजनाएं हैं जो बिहार में चल रही हैं । महोदय,

1990 से 2005 तक आप, हम सब लोग जानते हैं कि बिहार में जो प्राथमिक विद्यालय हैं पंचायत के सातवीं, आठवीं तक, बच्चे-बच्चियां जहां पढ़ते थे, सब लोग भूल गये थे, आजादी के 75 वर्ष हो गये, उस समय 60 वर्ष हुए थे, लोग जानते भी नहीं थे कि बच्चे-बच्चियों को सातवीं, आठवीं के बाद भी पढ़ाई करनी है । माननीय नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो उस समय से ही बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के उत्क्रमण का कार्य शुरू हुआ और आज पूरे बिहार की सारी पंचायतों में एक-एक विद्यालय को उत्क्रमित किया गया जिसका नतीजा हुआ कि गांव-गांव में बच्चे-बच्चियों में उत्साह जगा पढ़ाई का और उनके मन में एक भावना बनी कि प्लस टू तक की पढ़ाई के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, पढ़ाई छोड़कर घर में नहीं बैठना पड़ेगा और समान शिक्षा बच्चे-बच्चियों दोनों इसके प्रति प्रयत्नशील हुए और प्रत्येक पंचायत में प्लस टू विद्यालय आज खुल गया और सारे बच्चे-बच्चियां आज पढ़ाई कर रहे हैं । सभी विद्यालय बंद हो गये थे । सातवीं, आठवीं के बाद कोई विद्यालय नहीं था । किसी विद्यालय में कमरा नहीं था। जिस समय 2005 में हम विधायक बनकर आये थे, मंत्री बने थे, तो क्षेत्र में गये, तो कहीं दो कमरे, हाईस्कूल में कहीं तीन कमरे, जो 12-13 विद्यालय भी थे पूरे विधान सभा क्षेत्र में, एक मखदूमपुर विद्यालय था जहां हम गये, तो मात्र दो कमरे थे, टूटे हुए कमरे, एक फीट की एक-एक खिड़की लगी हुई थी, बच्चे-बच्चियां अंधेरे में क्लास में पढ़ रहे थे । 2005 के बाद जब हमारी सरकार बनी तो पूरे बिहार में, सारे विद्यालयों में पहला काम हुआ कि नया भवन बनाया गया, भवन बना तो सब बच्चे वहां पढ़ने लगे । किसी के तन पर कपड़ा नहीं था, सब ड्रेस पहनकर घूमने लगे और पोशाक योजना के तहत, साइकिल लेकर पगडंडियों पर दिखे । न कहीं सड़क थी, न कहीं स्कूल था, न कहीं बिजली थी, न कहीं रोशनी थी सब का सब माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बना । (क्रमशः)

टर्न-19/धिरेन्द्र/29.06.2022

क्रमशः...

श्री अनिल कुमार : बिहार में जो सभी जगह यह बात थी कि अब बच्चे बिहार में आठवीं के बाद पढ़ाई तो नहीं करते थे और जो पढ़ना भी चाहते थे वह पलायन कर गए थे । कहां पलायन कर गए थे ? पूरे बिहार से लोग एक मात्र कोटा में दौड़ते थे

राजस्थान में पढ़ने के लिए कि बच्चे को जा रहे हैं पढ़ाने । हम कहें कि गरीब किसानों के बच्चे वहां कोटा, किसी भी तरह परेशानी झेल कर भी अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करते थे लेकिन आज क्या हुआ, आज कोटा में जाना पलायन बंद हो गया, आपके यहां बिहार के सारे कोचिंग संस्थान, सारे अच्छे टीचर जो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, तामिलनाडु में पढ़ाने जाते थे, वह बिहार में ही चाहे बोरिंग रोड हो, चाहे श्रीकृष्णापुरी हो, चाहे गया में हो, चाहे मुजफ्फरपुर में हो, चाहे दरभंगा में हो, आई0ए0एस0 की कोचिंग हो या किसी भी तरह का, बी0पी0एस0सी0 की कोचिंग हो, इंजीनियरिंग की कोचिंग हो, मेडिकल की कोचिंग हो, सब बच्चे यहीं 99 परसेंट बच्चे बिहार के ही पढ़ रहे हैं । पलायन बंद हो गया है, एक उत्साह हुआ, कभी ऐसा होता था कि बिहार के बच्चे बाहर जाते थे तो लगता था कि बिहार के बाहर ही पढ़ाई होती है, बिहार में पढ़ाई नहीं होती है । आज क्या है ? दो-दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ फैशन डिजाईन, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी, अन्य कई विश्वविद्यालय, आज जाकर देखें इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब बिहार के बच्चे बिरला इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब बिहार के बाहर के बच्चे जा कर देखिये, छात्रावास में जाकर, घूमकर देखिये, पूछियेगा कि बच्चे कहां के हैं तो बतायेंगे कि हम तामिलनाडु के हैं, हम केरला के हैं, हम राजस्थान के हैं । पलायन करना कोई खराब चीज नहीं है, हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई अमेरिका जा रहा है, लंदन जा रहा है, तामिलनाडु जा रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अब जो हंसी का पात्र था कि बिहार में कोई शिक्षा नहीं है, अब हमारी भी धरती पर देश और दुनिया के लोग पढ़ने के लिए आ रहे हैं इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था, नालंदा विश्वविद्यालय का जो सपना था, जो हमलोग इतिहास के पन्नों में पढ़ते थे वह भी आपके सामने खड़ा हो गया है । इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में मेधा और प्रतिभा जो बिहार की पूंजी थी, वह पूंजी वापस लौटी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में लग रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में हम चारों ओर बढ़े हैं । इसलिए आज के डेट में, महोदय, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बढ़े हैं, चारों ओर पढ़ाई भी हुई है । एक प्रॉब्लम जरूर है छोटे-मोटे क्षेत्रों का भी कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, अनुमंडल स्तर पर एक डिग्री कॉलेज खोलने का फैसला ही नहीं लिये, वह कार्यान्वित हुआ और डिग्री कॉलेज खुल गया और सारी जगहों पर पढ़ाई भी शुरू हो गई लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे कि गया जिला हमारा नक्सल क्षेत्र है और नक्सल क्षेत्र में जैसे कोंच में हमार ब्लॉक है, 18 पंचायतों में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, 25

किलोमीटर दूर टेकारी में जाना पड़ता है तो हम आग्रह करेंगे कि टेकारी हो, इमामगंज हो या बाराचट्टी हो जो नक्सल क्षेत्र हैं वैसे जगहों को भी आगे की योजना में चिन्हित कर रखा जाय कि उन जगहों पर भी डिग्री कॉलेज खोला जाय जिससे बच्चों की पढ़ाई हो सके । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो सपना है बिहार में सबको समान शिक्षा मिले । इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामविलास कामत जी ।

श्री रामविलास कामत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं सरकार के द्वारा माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो शिक्षा विभाग के लिए प्रथम अनुपूरक मांग व्यय विवरणी प्रस्तुत की गई है, उसके पक्ष में मैं कुछ बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूँ । यह जो शिक्षा के बजट की मांग है, हम समझते हैं कि वह काफी महत्वपूर्ण और आवश्यक है । हम सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जनोपयोगी विभाग है और इस पर जो काम अभी तक सरकार के द्वारा किया जा रहा है और पिछले बीते समय में जो किया गया है वह काफी सराहनीय रहा है और इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो बजट में मांग की गई है, हम समझते हैं कि वह वाजिब है और वह मांग स्वीकृत होनी चाहिए । इन्हीं बातों को कहने के लिए मैं आज आपके बीच खड़ा हुआ हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में शिक्षा की जो हालत, अगर हम चर्चा करें कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के पहले जो शिक्षा की हालत थी, जो दशा शिक्षा की थी उसको अगर हम याद करते हैं और आज तक अगर हम शिक्षा को देखते हुए यहां पहुंचते हैं तो हम समझ सकते हैं कि शिक्षा में जो परिवर्तन आज हमें दिखाई पड़ रही है वह श्री नीतीश जी के नेतृत्व का, इनकी जो सोच है उसी का करामात है । हम कह सकते हैं कि वर्ष 2005 में जब श्री नीतीश जी की सरकार बिहार में बनी थी, जब बिहार की सत्ता में परिवर्तन हुआ था तो उस समय में जो बिहार में शिक्षा की दशा थी, जो शिक्षा की दिशा थी वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा था । बिहार के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में अपने बच्चों को हम कहां ले जाकर खड़ा करें, किस विद्यालय में उसका नामांकन करायें, कहां उनकी पढ़ाई की व्यवस्था करें, सोचने में भी असहज महसूस करते थे लेकिन जब वर्ष 2005 के बाद माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में बनी तो शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन का काम शुरू किया गया । हम अगर देखते हैं तो पंचायत स्तर पर प्राथमिक शिक्षक शिक्षा के रूप में प्राथमिक जो हमारा

विद्यालय पंचायत में हुआ करता है, उसको सुधार करने की जो प्रक्रिया शुरू की गई । वहां पर जो पहले भवन नहीं हुआ करता था, विद्यालय में शिक्षक नहीं हुआ करते थे, विद्यालय में बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, उनको पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होती थी, इन सारी त्रुटियों को, इन सारी कमियों को जो प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक था, जब शुरू किया गया, वहां पर गांवों में, पंचायतों में प्राथमिक विद्यालय का जो भवन बनाने का काम शुरू किया गया, उसमें शिक्षक जो बहाल कर उसमें नये स्तर से शिक्षक को नियुक्त किया गया और बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक जो कार्यक्रम उस समय में चलाये गये विद्यालय चलो, विद्यालय चलो का जो नारा उस समय लगाया गया, उसका परिणाम हुआ कि प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ी है और आज हम कह सकते हैं कि पंचायतों में और गांव के स्तर पर जो भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो सुविधाएं आज प्रदान की गई हैं, उसका भवन बनाकर, उसको चहारदीवारी से घेर कर, उसमें स्वच्छ पीने का पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था जो की गई है तो गांव के उन तबके के बच्चों को भी जो कभी विद्यालय की तरफ जाना नहीं चाहते थे आज वह प्रोत्साहित होकर विद्यालय में जा रहे हैं और वहां पर वह अपना पढ़ाई कर आगे बढ़ रहे हैं । यह तो प्राथमिक विद्यालय के बारे में हम बात किये हैं । उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम पंचायत स्तर पर प्लस टू विद्यालय, हाई स्कूल की कल्पना जो पहले कल्पना हुआ करती थी कि पंचायतों में हाई स्कूल होगा, प्लस टू विद्यालय होगा, उस कल्पना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश जी ने साकार कर दिखाया है । आज बिहार के सभी पंचायतों में प्लस टू विद्यालय, उच्च विद्यालय का निर्माण कराया गया है, वहां पर व्यवस्था की गई है और उसमें पढ़ने के लिए गांव के जो गरीब के बच्चे हुआ करते थे, जो पहली, दूसरी, पांचवी पास करने के बाद आगे पढ़ना नहीं चाहते थे उनको दूर-दूर जाना पड़ता था, उनको पोशाक की कठिनाई होती थी, आने-जाने में दिक्कत होती थी तो वह अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते थे, इन कठिनाइयों को हमारे नेता आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने समझते हुए इन कठिनाइयों को दूर कर पंचायत में ही उच्च विद्यालय बनाकर, स्थापित कर प्लस टू तक की पढ़ाई की व्यवस्था जो किये हैं, यह व्यवस्था बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसका द्योतक है । हम कह सकते हैं कि आज जिस तरह से बच्चियों को और बच्चों को साईकिल दे कर जो प्रोत्साहित किया गया, उसमें जो आत्मबल भरा गया, वह जो साइकिल से विद्यालय जाते हैं, उनकी जो पोशाक की व्यवस्था की गई है जो पहन कर, निर्भीक हो कर विद्यालय जाते हैं, हम आज कह

सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है इसमें ये सारे काम, ये सारी बातें निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित हुआ है जो हमारे माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी की सोच है कि सभी पढ़े, सभी आगे बढ़े और जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं ।

क्रमशः....

टर्न–20/संगीता/29.06.2022

श्री रामविलास कामत (क्रमशः) : इसी कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में इन सारे प्रयासों को किया गया है वह काफी सराहनीय है । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में चाहे वह प्राथमिक शिक्षा की हो चाहे माध्यमिक शिक्षा की हो चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, अगर हम उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि आज मैट्रिक का जो एग्जाम प्रत्येक वर्ष बिहार में होता है तो उस एग्जाम में जो छात्रों की संख्या 2005 के आसपास में हुआ करता था, वह ढ़ाई लाख से 3 लाख छात्र मैट्रिक के एग्जाम में भाग लिया करते थे लेकिन आज हम अगर उसको ध्यान से देखते हैं तो आज मैट्रिक के एग्जाम में जो छात्र सम्मिलित होते हैं, भागीदार होते हैं तो आज उनकी संख्या 17 से 18 लाख के आसपास में हुआ करता है । हम आज इसी से समझ सकते हैं कि इंटर की जो परीक्षा हर साल आयोजित की जाती है बिहार में, उसमें 2005 के आसपास में अगर हम ध्यान देंगे तो उस समय में जो बच्चों की संख्या हुआ करती थी एग्जाम में शामिल होने का, वह 2 से ढ़ाई लाख हुआ करता था लेकिन आज के समय में हम प्रत्येक वर्ष 14 से 15 लाख छात्रों को इंटर में एग्जाम दिलवाते हैं और उनकी सारी व्यवस्था हमलोग करते हैं ।

हमलोग देख सकते हैं कि आज किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार आगे बढ़ रहा है, यहां के युवा आगे बढ़ रहे हैं, वह हरेक क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और अपने आप को पूरे देश में जो प्रतियोगिता होता है, उसमें वह अव्वल स्थान लाने का हमेशा प्रयत्न करता रहता है । हम आज इस शिक्षा के माध्यम से जो प्राथमिक से लेकर के माध्यमिक और उच्च शिक्षा की बात है चाहे वह इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो जो हमारी सरकार ने सभी जिलों में लगभग निर्माण कार्य करवाया है । अनुमंडल स्तर पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज सभी जिला में आज खोलने की बात हो रही है और उस पर काम भी हुआ है, बहुत सारे ऐसे काम हुए हैं, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार का

प्रयास निरंतर जारी है । आज हम देख सकते हैं कि पिछले बजट के काल में भी जो बिहार सरकार द्वारा जो कई विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया, सभी विभागों का विश्वविद्यालय का स्थापना अलग-अलग किया गया है, चाहे वह खेल का विश्वविद्यालय हो, चाहे वह विधि विश्वविद्यालय हो, मेडिकल विश्वविद्यालय हो, अन्य जो कई विश्वविद्यालय बिहार में आज नए स्तर पर खोले जा रहे हैं आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनको सतत् प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उनको जो विशेष सहायता सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जा रहा है और पिछले जो कई वर्षों से वह लागू है वह काफी सराहनीय है और उसी के बूते पर बिहार के जो हमारे युवा हैं जो आज देश के किसी भी प्रतियोगिता में अपने आप को मजबूती के साथ भागीदार बनाता है और उसमें सफल होता है, उसके पीछे हमारे शिक्षा विभाग का और बिहार सरकार की जो मंशा है, जो उनकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी के साथ जो अपने युवाओं को वे प्रोत्साहित करते हैं, उनको पढ़ने के लिए जो आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनको भी पढ़ने के लिए जो सहायता प्रदान की जा रही है, आगे बढ़ने के लिए जो उनको सरकारी सहायता दी जा रही है उसी का परिणाम है कि आज हमारे युवा आज देश स्तर पर वह सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर आगे बढ़ रहे हैं । कहने का मतलब उपाध्यक्ष महोदय कि शिक्षा के विभाग में शिक्षा के क्षेत्र मे बिहार में जो काम किया जा रहा है पिछले 15 वर्षों से जो काम हुआ है, वह काफी सराहनीय है और निश्चित रूप से उसमें जो भी गुंजाइश है सुधार की, हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी हमारे शिक्षा मंत्री जी उन सभी बिंदुओं पर विमर्श करके और बिहार के युवाओं को आगे बढ़ने के लिए जो भी आवश्यकता है उनको पूरा करने के लिए काम कर रही है और हम देख रहे हैं कि अनुमंडल स्तर पर चाहे जिला स्तर पर हो, कई ऐसे विद्यालय का स्थापना चाहे वह कस्तूरबा विद्यालय के माध्यम से हो, जो एस0सी0,एस0टी0 की छात्राएं होती हैं जो पढ़ने में अपने आप को अलग रखती थी, उनको आगे बढ़ाने के लिए कस्तूरबा विद्यालय की स्थापना करके उनको आगे पढ़ने की व्यवस्था की जा रही है ।

इसी प्रकार के कई कार्यक्रम बिहार में हमारी सरकार के द्वारा आयोजित करके युवाओं को आगे बढ़ने के लिए लाया जा रहा है, उसमें चाहे किसी भी वर्ग के छात्र हों, कमजोर हों, गरीब हों, बड़े पैसे वाले हों सबों को आगे बढ़ने के लिए, सबों को पढ़ने के लिए जो व्यवस्था शिक्षा विभाग के माध्यम से किया जा रहा है

बिहार में उसकी मैं सराहना करता हूं और निश्चित रूप से इसमें जो मांग आज शिक्षा विभाग के द्वारा लाया गया है उसके समर्थन में मैं आपसे आग्रह करता हूं सदन से कि उन मांग को स्वीकृत करके शिक्षा विभाग को आगे बढ़ने में सहयोग करें और मैं शिक्षा मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो 2017-18 के वर्ष में पंचायतों में गांवों में जो नवसृजित विद्यालय खोला गया था और जिन विद्यालयों को उस समय में जमीन और भवन नहीं हो सका था, उन विद्यालयों को दूसरे अगल-बगल के विद्यालयों में जोड़ दिया गया था लेकिन उसके बाद हमने भी देखा है आप सबों ने भी महसूस किया होगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आम लोगों का जब इसपर ध्यान गया है तो सभी लोग अपने-अपने गांव में अपने-अपने टोले मोहल्ले में प्राथमिक विद्यालय खोलवाना चाहते हैं, जो नवसृजित विद्यालय पहले चल रहा था और जमीन और मकान के अभाव में उसे दूसरे विद्यालय में टैग कर दिया गया है, हम आग्रह करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से कि एक बार फिर से उन विद्यालयों को मौका दिया जाय और एक समय निर्धारित करके जो नवसृजित विद्यालय दूसरे विद्यालय में टैग हो गया है वह अपने स्थान पर फिर से अगर जमीन उपलब्ध हो भवन उपलब्ध हो तो वहां पर उसको ले जाने का एक आदेश यहां से निर्गत हो । यह मैं आग्रह करना चाहता हूं निवेदन करना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से, यह आवश्यक है आज के समय में सभी गांवों में प्राथमिक विद्यालय का होना आवश्यक है, छोटे-छोटे बच्चों को दूर जाने में कठिनाई होती है, उनकी पढ़ाई में दिक्कत होती है, उनको पढ़ने में कठिनाई होती है तो इन बातों को मैं रखते हुए कि सभी नवसृजित विद्यालय जो चल रहे थे उनको पुनः अपने स्थान पर पहुंचाने का, वहां पर चलवाने के लिए एक आदेश सरकार के द्वारा पारित हो, इन्हीं आशा के साथ आप लोगों के प्रति आभार प्रकट करते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर जी ।

श्री राणा रणधीर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और अपने मुख्य सचेतक महोदय, माननीय उपमुख्यमंत्री तारकिशोर जी, रेणु देवी जी सबके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि शिक्षा के विषय पर जो आज प्रस्ताव आया है उसपर मुझे बोलने का अवसर मिला इसके लिए मैं अपने उप मुख्य सचेतक जनक जी के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं और अपनी बात चंद पंक्तियों के माध्यम से शुरू करना चाहता हूं जो शिक्षा के ऊपर मानव के ऊपर, जहां शिक्षा है क्योंकि ये चीज हम सब मानते और समझते भी हैं कि संसार का एक बड़ा अघोषित नियम

सा है कि जहां प्रगति नहीं होती है वहां दुर्गति होती है, जहां उन्नति नहीं होती वहां अवनति होती है, जहां विकास नहीं होता वहां विनाश होता है, जहां चलना नहीं होता है वहां रूकना होता है और जहां रूकना होता है वहीं पर अंत होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हवा चलती है इसलिए जीवन देती है, खून, सांस, धड़कन जब तक चलती है तभी तक जीवन देती है इसलिए हमारे वेद में, पुराण में सब जगह कहा गया ''चरै वेती, चरै वेती'' अर्थात् जो चलता रहता है, चलायमान रहता है उसका भाग्य भी चलायमान रहता है और जो बैठ जाता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है इसलिए हम सब मानते हैं इस बात को कि गति में प्रगति है और प्रगतिशील जीवन ही सर्वश्रेष्ठ जीवन है ।

उपाध्यक्ष महोदय, कई मित्रों ने चर्चा की शिक्षा के ऊपर और शिक्षा में जो निरंतर विकास हुआ है उसके ऊपर लगातार चर्चा हुई अच्छी चर्चा हुई, और अध्यक्ष महोदय ने यह अवसर हम सब लोगों को दिया, अचानक ही सही लेकिन हम सब को बोलने का अवसर मिला शिक्षा के ऊपर । बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी एक लंबी यात्रा तय की ।

...क्रमशः...

टर्न–21/सुरज/29.06.22

श्री राणा रणधीर (क्रमशः) : हमलोगों ने सर्व शिक्षा अभियान से लेकर हमारी बेटियों की जो संख्या विद्यालयों में बढ़ी है । आज चाहे वह मैट्रिक लेवल का एग्जाम हो, प्लस टू लेवल का एग्जाम हो या आज जो हमलोगों ने यू0पी0एस0सी0 के एग्जाम में देखा कि हमारी बेटियों ने इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी सफलता अर्जित की है । यह एक ऐसा समाज और एक ऐसा राज्य जिसकी कल्पना हम सबके जेहन में बहुत पहले से रही है क्योंकि हमारी जो संस्कृति है वह पांच हजार वर्ष पुरानी संस्कृति व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली संस्कृति, समाज को आत्मनिर्भर बनाने वाली संस्कृति और उस संस्कृति पर पहला जो शिक्षा का उद्देश्य रहा है, आज हम सब इस बात को मानते भी हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है, बिहार सरकार की जो योजना है स्कील डेवलपमेंट की हम सब इस बात को जानते हैं कि हमारी जो नई पीढ़ी होती है अगर वह शिक्षित है, उसके अंदर स्कील है तो उसका आत्मविश्वास बना रहता है और ये हमारी आधी आबादी के साथ हमारी बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ हम इसमें बहुत ही गुणात्मक सुधार देखते हैं और ये गुणात्मक जिसको फिजिक्स में क्वांटम जम्प हमलोग कहते हैं उस तरह का एक

क्वांटम जम्प और एक अच्छी छलांग हमारी आधी आबादी ने लगाई है और जो आत्मविश्वास दिखाया है और नारी सशक्तिकरण के लिये लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी का जो सपना रहा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के जो निर्णय रहते हैं और अभी हमलोगों को जो यह सौभाग्य मिलेगा आने वाले 18 जुलाई को वह भी नारी सशक्तिकरण का एक अनुपम और अदभुत उदाहरण इस देश में और इस देश में ऐसी बेटी के लिये जो किसी जमाने में तमाम मुश्किल हलातों को फेस करके आज भारत के संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी कुर्सी पर जिनका आरोहन होना है वह भी मैं समझता हूं कि यह सतत प्रक्रिया जो चली है उसी का प्रकटीकरण है और उसी के प्रकटीकरण में आज हम सबको भी अभी राजकुमार भाई ने एक बड़ी अच्छी चर्चा की और दिनकर जी की चंद पंक्तियों के माध्यम से चर्चा की तो मानव के ऊपर और मानव के अंदर जो तमाम संभावनाएं हैं उसके ऊपर दिनकर जी ने बड़ी खूबसूरत पंक्तियां लिखी है जो इस प्रकार हैं कि:

''गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर

मेंहदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली है

बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है ।''

बिहार के शिक्षा मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एन0डी0ए0 की सरकार को कि जिस तरह से, जिस संवेदनशीलता के साथ तमाम विषयों को ग्रहण करते हैं और उसमें कैसे गुणात्मक सुधार लाया जाय, जो व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है, उसमें किस तरह से बेहतर किया जाय इसके प्रति बहुत ही संवेदनशील रवैया रहता है और बिहार के लिये बहुत अच्छा संयोग मैं मानता हूं कि बिहार को एक बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही प्रतिभाशाली शिक्षा मंत्री हम सब लोगों के बीच हैं जो अभिभावक के रूप में हैं और हम सबों का मार्गदर्शन भी करते हैं और मैं समझता हूं कि बिहार चाहे उच्च शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो या जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है क्योंकि कलाम साहब ने कहा था बहुत पहले जो हमारे भारत रत्न भी रहें और देश के लिये बड़े धरोहर रहें । उन्होंने एक बार बच्चों के कार्यक्रम में और शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में एक बड़ी बात उन्होंने कही आज सदन के सामने उस बात को रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि आप इस देश में कितने सारे कानून बना लीजिये लेकिन इस देश में जो आमूल चूल परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस देश में 21वीं सदी का जो नया भारत आप बनाना चाहते हैं, उसमें तीन लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है

और जब बच्चों ने यह प्रश्न किया कि किन तीन लोगों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है तो कलाम साहब ने बड़े सहज भाव से कहा था कि माता, पिता और प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ये तीन लोग हैं और जिसको हम सब फॉर्मेटिव ईयर्स कहते हैं, मानते हैं जिसको सेक्सपियर ने भी बहुत अच्छे तरीके से लिखा और कहा कि Give me the five years of a child and I will give you a complete man तो हम पूरब के लोग हैं और चीजों को समझते हैं। हमारे शरीर में सात चक्र हैं हमारे फॉर्मेटिव ईयर्स भी सात साल के होते हैं और इस फॉर्मेटिव ईयर्स में हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा है जिसको गांधी बाबा ने बुनियादी शिक्षा की चर्चा की है, हमारी बुनियाद की शिक्षा क्योंकि ये कहा जाता है कि:

''लगा अगर गेहूं में कीड़ा बाहर से मंगवाओगे

घुना हुआ चरित्र क्या बाजार से ले आओगे ।''

तो फॉर्मेटिव ईयर्स में एक बहुत बढ़िया सर्वे आया कि एक बच्चा आने वाले समय में कैसा बनेगा यह शुरू के सात वर्षों में तय हो जाता है और मानव के जीवन में हर 7 साल में परिवर्तन है 7 में है, 14 में है, 21 में है, 28 में है, 35 में है । मानव शरीर भी 35 के बाद डिक्लाइन होने लगता है । तो जिस तरह से हमारे बिहार के विद्यालयों में जो हमारे गरीब बच्चे थे, वंचित बच्चे थे, अनुसूचित जाति के बच्चे थे, दलित समाज के बच्चे थे, उनका जो इनक्लूजन इतनी बड़ी मात्रा में स्कूल में आने का जो काम शुरू हुआ है । यह नये बिहार के निर्माण में, नये भारत के निर्माण में मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी एन0डी0ए0 सरकार के नेतृत्व में, शिक्षा मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यह और नई उंचाईयों को छूयेगा । कई मित्रों ने बहुत अच्छी चर्चा कि की कई हमारे यहां आई0आई0टी0 बने, चाणक्या लॉ यूनिवर्सिटी बने, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय बने हैं । हमारे सभी पंचायतों में कामत भाई चर्चा कर रहे थे कि किस तरह की सोच की हर पंचायतों में हमारे यहां प्लस टू विद्यालय बनाने की योजना है, दसवीं तक के विद्यालय बन गये हैं लेकिन जो व्यक्ति काम करता है, जो सरकार काम करती है उससे संभावनाएं भी और अपेक्षाएं भी काफी बढ़ती है और इसलिये कहा गया है कि:

''मैं बताऊं शक्ति है कितनी पगों में

मैं बताऊं माप क्या सकते डगों में

पथ में अपने ध्येय कुछ तुम धरो तो

आज आंखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो

चिर वंदन भेद मर्म जलहीन आऊं

सात सागर सामने हो तैर जाऊं

तुम तनिक संकेत नैनो से करो तो

आज आंखों में प्रतीक्षा फिर भरो तो ।''

तो इस भाव के साथ इस संवेदनशीलता के साथ शिक्षा मंत्री जी की जो जिद्द है कि:

''वतन के रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे

मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा ।''

तो इसी व्यवस्था के तहत माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो आज अनुपूरक बजट लाया है और जो मांग की है उसके समर्थन में हूं और मुझे जो बोलने का अवसर दिया अचानक से दिया अपने उप मुख्य सचेतक महोदय जनक सिंह जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करता हूं । बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा बजट के फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ी हुई हूं । मैं धन्यवाद देती हूं हमारे माननीय मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी का जिन्होंने आदेश किया बहुत ही शार्ट नोटिस पर शिक्षा बजट पर बोलें और मैं धन्यवाद देती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का, आपका एवं माननीय शिक्षा मंत्री जी का जिनके मार्गदर्शन में हमलोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं शिक्षा के प्रति । बहुत सारे आंकड़े मेरे पास भी नहीं हैं फिर भी कुछ चीजें हैं, अनुभव है अपने जो मैं शेयर करूंगी । शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें बिल्डिंग चाहिये, लाइब्रेरी चाहिये, लेबोरेटरी चाहिये, शौचालय चाहिये । ये सब मैं गर्व से कह सकती हूं कि हमारी बिहार सरकार ने पिछले 16 वर्षों में जो किया है शिक्षा के क्षेत्र में, इन्फ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ाया है यह काबिले-तारीफ है । इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को और पूरे बिहार सरकार को साधूवाद देती हूं, धन्यवाद देती हूं । पहले जो कालिख

से पूता कालखंड था जिससे अब बाहर लेकर बिहार सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी आये हैं, उसके लिये धन्यवाद देती हूं । महोदय, सबसे पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को कन्या उत्थान योजना के तहत वोकेशनल कोर्सेज में भी छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देने के लिये जो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देती हूं । एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है और कन्याओं में जो आत्मविश्वास भरा है और आगे जो भरेगा इस वोकेशनल कोर्स से ग्रेजुएशन में 50 हजार वोकेशनल कोर्स करने पर 50 हजार जो बिहार सरकार दे रही है उससे जो आत्मविश्वास भर रहा है और भरेगा यह पूरा बिहार ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि बिहार की बेटियां कहां से कहां जाएंगी और कहां से कहां आज जा रही हैं ।

टर्न–22/राहुल/29.06.2022

श्रीमती शालिनी मिश्रा (क्रमशः) : महोदय, कहा जाता है कि एक शिक्षित पुरूष एक परिवार को बनाता है लेकिन एक शिक्षित महिला पूरी पीढ़ी को बनाती है, पूरी पीढ़ी को आगे बढ़ाती है । इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को साधुवाद देती हूं, धन्यवाद देती हूं कि शिक्षा के प्रति जो आपकी संवेदनशीलता है, जो जागरुकता है और दिन–रात शिक्षा की ओर जो काम चल रहा है उसमें यह नहीं कहा जा सकता है कि कहीं भी कोई कमी रखी जा रही है । इसका यह उदाहरण है कि बिहार सरकार के माननीय वित्तमंत्री जी ने जो पांच प्राथमिकताएं वर्ष 2022 के बजट में रखी हैं उसमें शिक्षा भी एक प्राथमिकता है बल्कि अव्वल प्राथमिकता है और पिछले कई वर्षों से शिक्षा का बजट सबसे ज्यादा रहा है । अब अनुपूरक बजट की बात करें तो अनुपूरक बजट की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों की बहाली हो रही है, जिस तरह से फिजिकल टीचर्स की बहाली हो रही है, जिस तरह से लाईब्रेरियन्स की बहाली हो रही है, जिस तरह से हम इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम कॉलेजों की बात कर रहे हैं, युनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, सेन्ट्रल यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटियों की बात कर रहे हैं, इन सबके लिए हमें बजट की जरूरत पड़ती है और यही कारण है कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षा बजट का पहला सप्लीमेंट्री आया है । मैं सदन की ओर से आग्रह करती हूं सभी माननीय सदस्यों से कि इस बजट को हम पास करें । बिहार सरकार ने अभी एम0डी0एम0 मील में काफी

गुणवत्तापूर्ण खाने के लिए जो दिया है उसमें अण्डा और फल की भी उपलब्धता कराई जा रही है उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं । महोदय, हमने देखा है कि पहले हमारा बिहार कहां पर था । बिहार में पहले स्कूलों में यह स्थिति थी कि वहां पर बैल, भैंस, बकरे सब पढ़ने जाते थे, छात्रों के अलावा सब वहां होते थे । चरवाहा विद्यालय का जमाना था, उस समय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री जी छात्रों को और लोगों को बहुत मोटिवेट करते थे कि अपने बच्चों को चरवाहा विद्यालय में भेजें उसी समय में वे अपने पुत्र जो हमारे नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उनको डी0पी0एस0, आर0के0 पुरम में पढ़ाते थे यह दोहरा मापदंड था हालांकि उनको डी0पी0एस0 की पढ़ाई रास नहीं आई और वे बैरंग लोट आए तो उस चरवाहा विद्यालय से आज हम चमचमाते विद्यालय पर आए हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ा है । शिक्षा की बात जब होती है, पहले जब मैं दिल्ली में पढ़ा करती थी उस जमाने में जब लोग कहते थे कहां से हो तो कहने में थोड़ी शर्म महसूस होती थी, मैं मना नहीं करूंगी उस समय बहुत बुरा लगता था यह कहने में कि हम बिहार से हैं । महोदय, आज यह हालात है कि हमारा बेटा जो दिल्ली में पढ़ता है वह भी कहता है कि हमारी मां बिहार से हैं और हमारा ननिहाल बिहार में है तो यह गर्व की बात है । यह शिक्षा से ही हुआ है और यह शिक्षा के स्तर से ही हुआ है । महोदय, पहले के जमाने में शिक्षा के क्षेत्र में ही क्या हर क्षेत्र में बिहार को छला गया, हर क्षेत्र में बिहार की जनता को छला गया । वहां से हम नए दौर में आ गए हैं । महोदय, स्कूलों में लड़कियों की संख्या भी बढ़ गई और छात्रों की संख्या भी बढ़ गई है और मैं देखती हूं कि बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय हर जगह पर जागरूकता अभियान चला रहा है, हर पंचायत में, हर जगह पर जागरुकता अभियान चलाकर सरकार बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रही है, हम सभी भी अपने स्तर से करते रहते हैं । ई-लर्निंग क्लासेज, ऑनलाईन क्लासेज ये सब होती रहती हैं । महोदय, कुछ चीजें हैं जो मैं कहना चाहती हूं चूंकि काफी कम समय में तैयारी करने का मौका मिला है तो कुछ प्वाइंट्स हैं हमारे केसरिया विधान सभा के जो मैं कहना चाहती हूं । हमारे केसरिया विधान सभा में एक भी स्नातक महाविद्यालय नहीं है, बच्चियों के लिए कोएड स्नातक महाविद्यालय की स्थापना भी अगर हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा । कई विद्यालय हैं हमारे बिहार में जो उत्क्रमित हुए हैं और उसी पंचायत में पहले से कई विद्यालय थे जो हाईस्कूल थे जो अनुदान पर रहते थे वे उत्क्रमित नहीं हुए हैं, उत्क्रमित विद्यालय हाईस्कूल में गये हैं तो हजारों एकड़ जमीन पूरे बिहार स्तर पर है जो खाली पड़ी है । जैसे कि मेरी ही पंचायत में मेरे ही परिवार द्वारा दी गई पांच एकड़ की जमीन है, सरकारी

नहीं हुआ अनुदान पर चल रहा है लेकिन वह खाली जा रही है । मेरा आग्रह है कि बिहार सरकार, शिक्षा मंत्रालय इस बात पर सोचे । उसको या तो हम ट्रेनिंग कॉलेज या किसी स्नातक कॉलेज या कुछ शिक्षा विभाग जो कर सकता है उसको उपयोग में लाकर समाज में उत्थान का काम हो सकता है । भोजपुरी और संस्कृत दोनों भाषाओं को बिहार सरकार में सरकारी भाषा के रूप में अगर हम लाते हैं, संस्कृत में भी शिक्षा होती है, भोजपुरी में भी होती है तो बहुत अच्छा रहेगा । स्कूलों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कई चीजें शुरू हुई हैं । धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी को उनके नेतृत्व में कई चीजें शुरू हुई हैं ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफी चीजों को अभी भी करने की जरूरत है । उदाहरणस्वरूप जब मैं स्कूल में थी तो मैं देखा करती थी कि हमारे स्कूल में सरस्वती जयंती, तुलसीदास जयंती, गांधी जयंती, कई लेखकों की जयंती और उनके ऊपर डिबेट हुआ करती थी, खेल-कूद प्रतियोगिता हुआ करती थी । इन सबसे ओवरऑल छात्र-छात्राओं की पर्सनालिटी में काफी डेवलपमेंट होता है । मेरा यह भी आग्रह है कि इन सब पर भी हम ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा । अंत में मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारे विद्वान शिक्षा मंत्री जी जिनके लिए एक लाईन बहुत ही चरितार्थ करती है वह है 'विद्या ददाति विनयम ।' जिस शालीनता से वे इस विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से हर काम करते जा रहे हैं उसी तरह से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले भविष्य में बिहार पूरे विश्व में अपना परचम फहरायेगा । बिहारी छात्र हमेशा से आगे रहे हैं और आने वाले समय में और भी आगे बढ़ेंगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री ललन कुमार ।

श्री ललन कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मैं सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा लाये गये अनुपूरक बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं सर्वप्रथम अपनी सरकार, अपने यशस्वी माननीय शिक्षा मंत्री जी, आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सचेतक जनक बाबू, श्रवण बाबू और यहां पर उपस्थित तमाम सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे यहां बोलने का मौका मिला है । चूंकि विषय शिक्षा का है तो आज मैं आभार व्यक्त करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं अपने शिक्षक और मानस पिता स्वर्गीय सुरेश लाल यादव जी को जिन्होंने मुझे अपने बेटे की तरह अपने घर में रखकर पढ़ा-लिखाकर इंजीनियर बनाया और पीरपैंती विधान सभा का नेतृत्व

करते हुए आज आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूं । सबसे पहले मैं इसकी शुरूआत एक शायरी से करना चाहूंगा कि :

''कर्तव्यों को बोध कराती, अधिकारों का ज्ञान ।

शिक्षा से ही मिल सकता है, सर्वोपरि सम्मान ।।''

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जो दो मशीहा हुए आजादी के पहले से बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी । बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि 'शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पियेगा वह दहाड़ेगा ।' और महात्मा गांधी जी कहते हैं कि 'जो पढ़ना-लिखना नहीं जानता, वह पशु के समान है ।' पशु और मनुष्य में अगर विभेद कोई करता है तो वह शिक्षा है और मैं पुनः सरकार का आभार व्यक्त करता हूं कि आज मुझे इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका मिला और मैं यह भी कहता हूं कि सरकार काम कर रही है कि इन दोनों महान आत्माओं के अनुरूप सरकार का काम हो रहा है ।

क्रमशः

टर्न-23/मुकुल/29.06.2022

...क्रमशः...

श्री ललन कुमार : जब आज मुझे लगा कि शिक्षा बजट पर बोलना है और पिछले बजट सत्र में भी माननीय मंत्री जी को लग रहा था कि ये बार-बार शिक्षा का प्रश्न बिहार से ही उठाकर ला रहे हैं, चाहे ध्यानाकर्षण का हो, चाहे गैर सरकारी संकल्प का हो । जब मैंने इनकी शिक्षा नीतियों को पढ़ा तो मुझे लगता है कि अगर किसी ने देश और दुनिया की शिक्षा व्यवस्था को देखा होगा तो लगेगा कि बिहार सरकार की जो शिक्षा व्यवस्था है, माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो शिक्षा में इन्होंने जो पिरोया है उसमें महात्मा गांधी हैं, डॉ0 अम्बेडकर हैं, अमेरीका की एजुकेशन सिस्टम है, भूटान की एजुकेशन सिस्टम है और अभी जो पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रखा है एलोन मस्क का जो एजुकेशन थ्योरी आया है, उस एलोन मस्क के एजुकेशन थ्योरी का भी समावेश इसमें किया गया है उपाध्यक्ष महोदय । आज महात्मा गांधी जी को मैं स्मरण करता हूं, उन्होंने कहा कि जो पढ़ना-लिखना नहीं जानता वह पशु के समान है, लेकिन आज अगर महात्मा गांधी जी जिंदा होते तो वे

कहते कि जो व्यक्ति ऑनलाइन नहीं है, जो व्यक्ति डिजिटल नहीं, जो व्यक्ति फेसबुक, वाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम नहीं जानता वह पशु के समान है । जिस तरह से डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में सरकार काम कर रही है, जिस तरह से सुदूर देहातों, गांवों में स्मार्ट टी0वी0 और स्मार्ट टीचर वहां पर पढ़ा रहे हैं तो महात्मा गांधी जी की आत्मा को शांति मिल रही होगी और वहां से भी आशीर्वाद, दुआ प्रदान शिक्षा मंत्री जी को कर रहे होंगे । बाबा साहब अम्बेडकर का क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो । आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की भी आत्मा को संतुष्टि मिल रही होगी कि आज बिहार के शिक्षा मंत्री जो शिक्षा पर इतना जोड़ दे रहे हैं, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि हमारे बिहार का शिक्षा बजट टोटल बजट का 20 परसेंट है महोदय । अपने आप में यह काबिलेतारीफ है । आज इन महान आत्माओं का इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा होगा । उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मैं यहां पर उल्लेख करना चाहूंगा कि महात्मा गांधी जी और डॉ0 अम्बेडकर जी भिड़ंत होती थी सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस में और दूसरे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी खुद जाकर अपने प्रतिनिधि के तौर पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी को भेजा था और जब शिक्षा का सवाल उठा था कि आखिर देश के पिछड़े/दलित जो शिक्षा के क्षेत्र में नगण्य हैं, शून्य हैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कहा था कि इन सबके लिए जिम्मेवार ब्रिटिश गवर्नमेंट है । अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतवासियों को, वहां के दलितों को, वहां के पिछड़ों को प्रारंभिक, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था कर देती तो ये छुआछूत, भेदभाव, जाति-पाति यह इतिहास बनकर रह जाता, इतिहास के पन्नों में सिमट जाता और आज मुझे लगता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के उस मार्मिक विचार को शिक्षा विभाग ने अपने नीति में पिरोया है, उसी का परिणाम है महोदय कि आज टोलावार, मोहल्लावार बिहार का कोई टोला नहीं, कोई मोहल्ला नहीं जहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है । बिहार का कोई गांव नहीं है, जहां मध्य विद्यालय नहीं है और बिहार का कोई पंचायत नहीं है जहां पर +2 उच्च विद्यालय नहीं है, यह घर-घर तक शिक्षा को पहुंचाने का काम जो बिहार सरकार ने किया है और अनुमंडल स्तर पर जो डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई है, आज हम और इसकी पूर्ति के बाद जो सरकार की मंशा है कि इसको प्रखंड स्तर पर भी विस्तार किया जायेगा । आज हम देख रहे हैं कि सुदूर गांव, दियरा क्षेत्र, आज खवासपुर मौजा में 720 सय्यायुक्त जो है कि अम्बेडकर राजकीय अनुसूचित जाति, जनजाति सह शिक्षा आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है लगभग 42 करोड़ की राशि से । पिछले भी बजट में हमारे खुद पीरपैंती के, कोई ऐसा विधान सभा नहीं जहां दो-दो

आवासीय विद्यालयों का सरकार ने बनाने का संकल्प नहीं लिया हो । आज हर जगह जाकर देखें कस्तूरबा विद्यालय के रूप में जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से बच्चियां वहां पर पढ़कर शिक्षित हो रही हैं । आज जो सरकार ने जागरूकता लाने का काम किया है, आज हम कहते हैं कि समाज में जो विषमताएं हैं वह जागरूकता से खत्म होंगी, सिर्फ सरकार के प्रयास से नहीं होगा, सरकार ने घर-घर तक पहुंचा दिया है शिक्षा की सारी व्यवस्था को । आज जो बेटियां, आज जो बहनें, आज जो माताएं घरों में पड़ी रहती थीं, दहलीज से बाहर नहीं निकलती थीं, जिनको शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था आज शिक्षिका बनकर शिक्षा का दान दे रही हैं, बिहार का नाम, देश का नाम रौशन कर रही हैं, यह सरकार की दूरदर्शी दृष्टि का परिणाम है महोदय । आज शिक्षा के जगत में जिस जागरूकता की जरूरत है, उसपर सरकार लगातार काम कर रही है । आज अमेरिकन सिस्टम को जो सरकार ने पिरोया है, अमेरिकन सिस्टम क्या था । अमेरिका में क्या है कि जो सारे पैरेंट्स, सारे अभिभावक अपने बच्चों को अपने आवास के नजदीक जो निकटतम विद्यालय हैं, उनमें पढ़ाने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

सरकार के प्रयास के कारण वहां पर हर घर के आस-पास, हर मोहल्ले में विद्यालय बन चुका है । आज बस जागरूकता की जरूरत है । आज शिक्षा के व्यवसायीकरण ने जिस तरह से समाज में ये प्रचार कर दिया है कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है लेकिन नहीं, आज प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छे काबिल-काबिल टीचर हमारे सरकारी स्कूलों में हैं । जिस तरह से आज यह कहा गया, पूर्ववर्ती सरकारों ने एग्जाम लिया, हमलोग वर्ष 1989 में मैट्रिक पास किये हैं, पूर्ववर्ती सरकार की यह अदूरदर्शिता और शिक्षा के प्रति उदासीनता का परिणाम है कि आज हमलोग चाहे मजदूर का बच्चा हो, चाहे किसान का बच्चा हो, चाहे सेठ/साहूकार का बच्चा हो, चाहे नौकर का बच्चा हो, चाहे अधिकारी का बच्चा हो, चाहे कर्मचारी का बच्चा हो, चाहे नेता का बच्चा हो, चाहे कार्यकर्ता का बच्चा हो, हम सब लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे । हमलोग 1989 में मैट्रिक पास किये, हमारे क्लास फ्रेंड, हमारे मित्र होते थे सी0ओ0 साहब के बेटे, बी0डी0ओ0 साहब के बेटे, दरोगा के बेटे, इंस्पेक्टर के बेटे होते थे, लेकिन जिस तरह से पूर्ववर्ती सरकार ने शिक्षा पर प्रहार किया । महोदय, अब आप कोटा का उदाहरण लें, आज कोटा में । हमलोग पटना से ही इंजीनियरिंग किये हैं ब्रिलियंट कोचिंग इंस्टीच्युट, पटना से वर्ष 1993 में । उस समय पटना को इंजीनियरिंग और मेडिकल का हब

कहा जाता था, आज हब हो गया है कोटा । लेकिन महोदय, जब आप कोटा जायेंगे तो देखेंगे कि कोटा में पढ़ने वाले बच्चे बिहार के हैं, पढ़ाने वाले 90 परसेंट टीचर बिहार के हैं, इतना ही नहीं वहां पर स्टेशनरी और किताब/कॉपी बेचने वाले जो व्यवसायी हैं वह भी बिहार के हैं । क्यों कोटा चले गये, क्योंकि यहां के टीचरों को जो लेटर जाने लगा, उनसे फिरौती मांगी जानी लगी, उनके चेहरे पर कालिख पोता जाने लगा इसका दुष्परिणाम हुआ कि वे यहां से पलायन करने के लिए विवश हो गये महोदय । महोदय, हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री भी सुन रहे हैं, काफी अच्छा काम हुआ है लेकिन हमारे पीरपैंती विधान सभा क्षेत्र का जो रौशन रहा है, उच्च विद्यालय केरिया, ईशीपुर, शेरमारी, मलिकपुर, ख्वासपुर, मथुरापुर, अकबरपुर, दुबौली, लेकिन जिस तरह से आप शिक्षा का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से डिजिटल इंडिया में बिहार का शिक्षा विभाग बढ़-चढ़कर भाग ले रहा है तो इन विद्यालयों के जर्जर भवनों का निर्माण करायें । आज जरूरत के हिसाब से उनको बनाने की जरूरत है महोदय । अभी जो आप अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे-मिडिल विद्यालय को आपने अपग्रेड किया है बसकोला, बसंतपुर, सिमानपुर, बाखरपुर, इन अपग्रेडेड विद्यालयों को भी सभी सुविधाओं से वहां पर उसको लेस करने की जरूरत है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि पीरपैंती भागलपुर का सबसे सुदूर इलाका है, हमारा 29 पंचायत का इलाका है और बिहार का सबसे व्यस्ततम रोड है, जाम है वहां पर और बच्चे/बच्चियां सिर्फ बी0ए0 की डिग्री लेने के लिए एकदम सामान की तरह, जानवर की तरह लोकल ट्रेनों में लदकर आते हैं, इसलिए हम यह चाहेंगे कि जल्द आप कुछ नीति बनायें और पीरपैंती में एक डिग्री कॉलेज की बहुत ज्यादा आवश्यकता है तो आप वहां पर एक डिग्री कॉलेज देने की कृपा करें । हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय मंत्री जी, जिस तरह से विक्रमशिला विश्वविद्यालय, लग रहा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय वहां नहीं बनेगा, लेकिन आपने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के भी काम को आगे बढ़ाने का काम किया । आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय का सर्वे करा रहे हैं, जमीन उपयुक्त जगह पर नहीं थी, जमीन खोजी जा रही है, आप उसमें संवेदनशील हैं और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में स्थान रखता है उससे बड़ा विश्वविद्यालय अभी तक कोई नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हम माननीय मंत्री जी को एक सुझाव भी देना चाहेंगे कि जिस तरह से हमारी सरकार अग्निपथ और अग्निवीर पर अटल है, उसके लिए यह जरूरी है कि जिस तरह से आपने हर पंचायत में +2 उच्च विद्यालय दिया है उसी तरह से हर पंचायत में उस स्कूल में प्ले ग्राउंड दीजिए, खेल मैदान दीजिए ताकि

बच्चा मैट्रिक और इंटर करने के बाद दौड़ कर सके, व्यायाम कर सके और योग्य सैनिक बनकर भारत मां की सेवा कर सके और सैनिक बन सके । अध्यक्ष महोदय, पूरे बिहार के हर +2 उच्च विद्यालय को एक पर्याप्त खेल मैदान देने की जरूरत है।

...क्रमशः...

टर्न–24/यानपति/29.06.2022

...क्रमशः...

श्री ललन कुमारः अध्यक्ष महोदय, बस हमारा कुछ सुझाव है, अगर हमारा समय बचा हो तो सुझाव है कि जरूरत है हमलोग आज गांव–गांव तक...

अध्यक्षः उद्योग मंत्री जी, विक्रमशिला पर जोर दे रहे हैं, आप भी ध्यान दें उसको ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्रीः महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जब सांसद रहते हुए वहां पर विक्रमशिला के लिए काम किया और महामहिम राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी वहां गए थे तो इतना बड़ा काम हुआ उसके बाद थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो जरूर मदद मिलेगी । प्रयास कर रहे हैं इसलिए शुक्रिया भी अदा करते हैं सर ।

श्री ललन कुमारः अध्यक्ष महोदय, हमने निवेदन किया था अपने अभिभावक और हमारे प्रेरणास्रोत गुरू और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी से कि आज मुझे शिक्षा पर बोलना है और भैया आप हाउस में रहेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा तो आप आज हाउस में आए हैं और आपकी बदौलत हम यहां विधान सभा पहुंचे हैं इसके लिए मैं आपका भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और बस कुछ मेरा सुझाव है कि अब जरूरत है समान शिक्षा की, जरूरत है कि सबको ऐसा कुछ सरकार विचार करे, ऐसा कुछ कानून बनाए कि सबों को हम समान शिक्षा दे पाएं और जरूरत है एक सबसे बड़ी खाई जो पैदा हो रही है कि वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में कि जैसे हमलोग सभी लोग बड़े–छोटे, गरीब–अमीर के बच्चे स्कूल में पढ़ते थे एक उसका नतीजा था महोदय कि आज मैं विधायक हूं, इंजीनियर हूं लेकिन हमारा एक दोस्त है...

अध्यक्षः अब संक्षिप्त कर लीजिए न, और लोग हैं ।

श्री ललन कुमार: दो मिनट अध्यक्ष महोदय, हो गया है ।

अध्यक्ष: एक मिनट में खत्म करिए ।

श्री ललन कुमार: जी । अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि जिस तरह से आज ऐसी कुछ व्यवस्था हो कि सबलोग एक साथ पढ़ें-लिखें और जैसे मैं आज इंजीनियर हूं, विधायक हूं लेकिन हमारा भी क्लास फ्रेंड पाझर जादव है और वह ठेला चलाता है लेकिन हम दोनों दोस्त जिस तरह से उतर कर मिलते हैं, बीच चौराहे पर, बीच बाजार में गले मिलते हैं लगता है हम क्लास फ्रेंड हैं लेकिन आनेवाले समय में जिस तरह से लोगों का स्कूल बंट रहा है यह सब दिन आनेवाला भविष्य हमारा नहीं देख पाएगा । हम बस अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि शिक्षा के संबंध में बस एक बात कहकर खत्म करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष: बोलिये कोई शेर बोल रहे हैं ।

श्री ललन कुमार: ''अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान,

शिक्षा से ही बन सकता है भारत देश महान'' ।

बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद ।

अध्यक्ष: दो-दो मिनट में आपलोग बोलें ।

श्री संजय कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के इस बजट पर हमको बोलने का अवसर हमारे जनक जी ने प्रदान किया इसके लिए उनका आभार है और आभार है उस महान जनता का जिसने लालगंज की धरती से हमको विजयी बनाकर इस सदन में पहुंचाया है अपनी बात रखने के लिए । मैं शिक्षा पर बोलने से पहले विचार कर रहा हूं कि कहां से प्रारंभ करूं, मैं कहां से प्रारंभ करूं । मुझे दिखाई नहीं पड़ता, उस बख्तियार खिलजी से प्रारंभ करूं जिसने बिहार के समृद्धशाली इतिहास को, बिहार के समृद्धशाली ज्ञान भंडार को समाप्त करने का कुत्सित प्रयास किया या वहां से प्रारंभ करूं जहां बिहार प्रदेश के एक राजा ने बिहार के बच्चों के भविष्य को समाप्त करने के लिए बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना नहीं की बल्कि उसकी जगह पर चरवाहा विद्यालय स्थापित किया, वहां से प्रारंभ करूं या वहां से प्रारंभ करूं जहां उदयपुर के अंदर एक जाहिल और अज्ञानी ने एक व्यक्ति की गला काटकर के निर्मम हत्या की है मैं वहां से प्रारंभ करूं । शिक्षा सबको चाहिए, न्याय सबको चाहिए और इस बिहार की धरती में हम सबलोग जानते हैं

कि जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने उसके पहले बिहार के हालात कैसे थे, बिहार की शिक्षा के हालात कैसे थे । बिहार के अंदर न शिक्षकों को वेतन मिलता था समय पर, न बिहार के छात्रों को पढ़ने के लिए डेस्क और बेंच रहता था, न बिहार के छात्रों के पढ़ने के लिए कोई विद्यालय के भवन रहते थे परंतु उस गर्दिश से निकालकर के बिहार की सरकार ने, और हम धन्यवाद करना चाहेंगे आज की तिथि में हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जिन्होंने पूरा का पूरा धन इस बिहार को दिया है । हम उस छात्र आंदोलन की उपज हैं जो विद्यार्थी परिषद् के जमाने में हम सबलोग नारा लगाते थे कि पूरे बजट का कम से कम 10 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय हो, आज हमको इस बात को कहने में गर्व महसूस होता है कि बिहार की सरकार ने 20 प्रतिशत शिक्षा का बजट किया है और उसके कारण बिहार के अंदर छात्रों के विकास के लिए काम हो रहा है । आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और आज उसके कारण हमने तय किया कि हम अपने बिहार की बेटियों को 25 हजार और 50 हजार की राशि वजीफा के रूप में देंगे, अनुदान के रूप में देंगे और आज हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं और आसमान को छूने के लिए लालायित हैं, यह हमारा आज का बिहार है । आज का बिहार कैसा है, जब पगडंडियों पर हमारी बच्चियां चलती हैं, जब पगडंडियों पर एक वेष, एक दिशा और एक ध्येय के साथ हमारी बेटियां जब बढ़ती हैं तो हमको लगता है आज चलता बिहार, बढ़ता बिहार और आसमान को छूनेवाला बिहार तैयार हो रहा है । आज जहां चरवाहा विद्यालय बनाकर के बिहार के बच्चों के भविष्य को खतरे में डाला जा रहा था वहां बिहार की सरकार आज तकनीकी विश्वविद्यालय स्थापित कर रही है, आज विधि विश्वविद्यालय स्थापित करके बिहार के छात्रों को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है । हम चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा ज्ञानोपर्जन का साधन तो बने ही बने साथ ही साथ रोजगारपरक भी बने, रोजगार मुहैया करानेवाला भी बने और इसीलिए आज तकनीकी शिक्षा पर हमलोग जोर दे रहे हैं, आज यही कारण है कि आज प्रत्येक जिले में हमने तय किया है कि इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना करेंगे, यही कारण है कि हम आज प्रत्येक पंचायत में आज हाईस्कूल की स्थापना करके छात्रों को, वहां के नौजवानों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, बत्ती जल गई है लगता है आपका इशारा बंद करने की ओर है परंतु हम मांग करेंगे कुछ विषय केवल लालगंज...

अध्यक्ष: चलिये हो गया ।

श्री संजय कुमार सिंहः हमारा नगर परिषद् है, वह बिहार के सबसे पुरातन नगर परिषदों में से है, हम मांग करेंगे अपने आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय से एक डिग्री कॉलेज वहां पर दिला दीजिए...

अध्यक्षः श्री विनय कुमार चौधरी जी ।

श्री संजय कुमार सिंहः ताकि वहां के नौजवानों को डिग्री की शिक्षा प्राप्त हो । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

श्री विनय कुमार चौधरीः अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हम अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं...

अध्यक्षः गागर में सागर भर दीजिए ।

श्री विनय कुमार चौधरीः सर, आपने कहा था मैथिली में बोलने के लिए तो मैथिली में बोल रहा हूं तो हमको थोड़ा समय दे दीजिएगा ।

अध्यक्षः आप की बात सुनने में बड़ा आनंद आता है ।

श्री विनय कुमार चौधरीः उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं । आपलोगों के प्रति साधुवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इस विपरीत परिस्थिति में, उस समय तो बहुत समय था लेकिन अब तो समय का अभाव हो गया है फिर भी आपने समय दिया इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं । हम दरभंगा की तरफ से हम अपने बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि दरभंगा में बहेरी में एक कॉलेज था जहां 52 साल से मात्र एक संकाय की वहां पढ़ाई होती थी और इन्होंने स्वीकृति दी थी साइंस की पढ़ाई प्रारंभ करने के लिए तो इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं । हम आभार प्रकट करना चाहते हैं कि बहेरा में जो एक सरकारी कॉलेज है अनमंडल स्तरीय तो उसमें साइंस के प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराये थे इससे एक नया जेनरेशन बनेगा । जो परंपरा समाप्त हो गई थी कि प्रयोगशाला की तरफ ध्यान नहीं जाता था लेकिन अब ध्यान जाएगा उसके लिए हम इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं । डब्लू0आई0टी0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम, उत्तर भारत का एकमात्र महिला प्रौद्योगिकी संस्थान है जहां छात्रा को कन्या उत्थान का लाभ नहीं मिलता था वह यहां कन्या उत्थान योजना का लाभ दिए इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं । साथ ही हम मांग करना चाहते हैं कि राज्य के ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था डिस्टेंस

मोड लेकिन अभी वर्तमान में डिस्टेंस मोड राज्य में सब जगह बंद हो गया है । एक ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में डिस्टेंस मोड की पढ़ाई होती थी जो अभी बंद है । जिसके पास अपनी अर्जित राशि लगभग 1 अरब 60 करोड़ रुपया है, अगर राज्य सरकार उसका अधिग्रहण करके उसको खुले विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर देती है तो एक उपलब्धि भी होगी साथ ही ग्रॉस एनरॉलमेंट रेशियो को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी ।

(क्रमशः)

टर्न-25/अंजली/29.06.2022

श्री विनय कुमार चौधरी (क्रमशः) : साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं जिनको पढ़ाई-लिखाई करने के लिए महाविद्यालय आने में दिक्कत होती है उनके लिए सुविधा हो जाएगी, हम यही आग्रह करते हैं साथ ही हमारे विपक्ष के नेता सब बराबर आग्रह करते रहते हैं कि शिक्षा की खराब स्थिति को लेकर, हम अपना अनुभव बताते हैं कि हमारे गांव में जो स्कूल था तो उसमें झोपड़ी टाइप के एक-दो रुम था , अभी वहां हाईस्कूल के साथ-साथ 24 कमरा का कमरा था । हमारे हेल्थ मिनिस्टर नहीं हैं नहीं तो हम उनसे आग्रह करते कि उन सबके आंख का, एक मिनट और सर, उनकी आंख का इलाज कराना आवश्यक है । साथ ही हम एक आग्रह करते हैं प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक शिक्षक की पाठ्य योजना अनिवार्य कराना चाहिए । अगर पाठ्य योजना का निर्माण कार्य अनिवार्य होगा तो शिक्षा की गुणवत्ता में विकास होगा । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : धन्यवाद । माननीय सदस्य, श्री विद्या सागर केशरी जी, दो मिनट में ।

श्री विद्या सागर केशरी : महोदय, आज अनुपूरक बजट शिक्षा के क्षेत्र को लेकर के बोलने का मौका दिया गया है । मैं अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और अभिभावक तुल्य शिक्षामंत्री जी को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने आज सदन में बोलने का मौका दिया है । मैं अध्यक्ष महोदय का भी आभार प्रकट करता हूं और जनक जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के संदर्भ में सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी जो बात सदन में रखी लेकिन शिक्षा के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि संस्कृत महाविद्यालय, अभी तक किसी ने उस पर चर्चा नहीं की । मैं संस्कृत भाषा देवनागरी के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि पूरे बिहार में संस्कृत महाविद्यालय और उच्च विद्यालय का नामोनिशान जो है वह मिट गया है और जिस भाषा के चलते

पूरे विश्व की भाषा की रचनाएं की गई उस भाषा का विलोपन होना एक अच्छा संदेश नहीं जा रहा है । हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से करवद आग्रह करेंगे कि शिक्षा जगत में संस्कृत का कहीं भी जो है एक स्थान जरूर मिले और बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो टोला सेवक और विकास मित्र को जिस उद्देश्य के लिए लगाया गया था, बुनियादी शिक्षा के लिए, अनुसूची जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, वहां काम की जो गति है वह काम की गति सही ढंग से नहीं हो पा रही है चूंकि बहुत सारे माननीय सदस्यों ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे पीकर के लोग जीवन भर दहाड़ते हैं, किसी ने यहां तक कहा कि विद्या ददाति विनयं, विनयाद्याति पात्रताम्, विद्या विनय को प्रदान करती है, सरल जीवन मनुष्य को बहुत आगे ले जाती है किसी ने यह भी कहा कि...

अध्यक्ष : अब समाप्त कर लीजिए ।

श्री विद्या सागर केशरी : ''स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते'' तो बहुत सारी बातें यहां शिक्षा के संदर्भ में आई लेकिन मैं शिक्षा के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि शिक्षा सौंदर्य और यौवन को परास्त कर देती है । गीता के अनुसार ''सा विद्या या विमुक्तये'' अर्थात् शिक्षा या विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्त करे और हमारा हर पहलू पर विस्तार करे । शिक्षा का कोई अपना धर्म नहीं है अध्यक्ष महोदय, बल्कि शिक्षा ही अपने...

अध्यक्ष : क्या चाहते हैं कि गीता का ज्ञान विद्यालय में हो ? आप क्या चाहते हैं ?

श्री विद्या सागर केशरी : हमलोग यही चाहते हैं कि बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया जाय और संस्कृत महाविद्यालय जो है कम से कम बिहार में संस्कृत महाविद्यालय का जो है ज्यादा से ज्यादा स्थापना की जाय ।

अध्यक्ष : बैठ जाइए, बैठ जाइए ।

श्री विद्या सागर केशरी : और हम अपने एक क्षेत्र की एक-दो समस्या को कहना चाहते हैं ।

अध्यक्ष : अब इतना बोल दिए, अब कोई समस्या नहीं, बैठ जाइए आप ।

श्री विद्या सागर केशरी : जीरा देवी शीतल साह महिला महाविद्यालय है उसको अंगीभूत कर लिया जाय और जो एकेडमी हाई स्कूल है उसको मॉडल विद्यालय की संज्ञा प्रदान कर दी जाय । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : रोने वाले महलों में भी रोते रहते हैं और किस्मत अच्छी रहती है तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है, पीपल के पेड़ के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करते हैं और पूरे विश्व को ज्ञान प्रदान करते रहते हैं, यही बिहार की धरती है । लेकिन आज शिक्षा पर इतनी गंभीर चर्चा हुई और शिक्षा के प्रति सजगता भी इस सदन में दिखाई पड़ रही है और जो माननीय विधायक इसमें भागीदारी कर रहे हैं उनको तो धन्यवाद देते हैं लेकिन जो भविष्य के प्रति बहुत सजग हैं, लोगों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं उनकी ही सजगता दिखाई पड़ रही है ।

(व्यवधान)

क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप उप मुख्यमंत्री जी । कुछ नहीं ।

(व्यवधान)

नहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे, इधर देख रहे थे बार-बार ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरा बिहार जानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितनी तेजी से तरक्की हुई है और आज इतनी महत्वपूर्ण चर्चा शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ने कितनी तरक्की की है क्योंकि हमारे यहां नालंदा है, हमारे यहां विक्रमशिला है, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले हमने विश्वविद्यालय स्थापित किया और हमारे यहां तो पेड़ के नीचे ज्ञान मिला तो गौतम बुद्ध बने लेकिन इतने जब ज्ञान की बात हो तो जो लोग बहुत ज्ञान देते हैं आज सामने के बेंच पर जो लोग नहीं देख रहे हैं पूरे बिहार के अंदर लगता है कि शिक्षा के प्रति जो उनका लगाव है आज वह पूरी तरह प्रमाणित हो गया है ।

अध्यक्ष : अब इनका समय हो रहा है ।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन, मंत्री : जिस विद्यालय जाएं, लेकिन अध्यक्ष जी, यह मौका वे चूक गए हैं जो नहीं थे, जो नहीं आए हैं उनको इतिहास याद रखेगा, इतनी महत्वपूर्ण चर्चा और आपकी शायरी से भी वे महरूम हो गए हैं ।

अध्यक्ष : सरकार का उत्तर । माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

<u>सरकार का उत्तर</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ही इस सदन में हमने शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग 120 रुपए से अधिक राशि की अनुपूरक मांग पेश की

थी । मुझे प्रसन्नता है कि सदन लगभग पिछले ढाई घंटे से इस मांग पर जैसा कि आपने कहा कि बड़ी ही गंभीरता से विमर्श कर रहा है । सबसे पहले तो मैं लगभग देख रहा हूं कि तेरह-चौदह से अधिक सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है । इन सभी सदस्यों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने इस विमर्श में हिस्सा लिया है और विनय चौधरी जी को हम उनको अलग से धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने मैथिली में कुछ बोला, इस खातिर बाकी लोगों को अध्यक्ष महोदय, हम उनके प्रति शुक्रिया अदा करते हैं और विनय जी को हम धन्यवाद देते हैं जो भी मैथिली में वे बोले । आखिर हमलोग भी महोदय मिथिला के ही टेल एंड पर हैं वैसे खाटी मिथिलावासी हमलोगों को मिथिलावासी मानने में उतनी रुचि नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी हमलोग भी मिथिलावासी ही हैं महोदय ।

अध्यक्ष : मैथिली में ही बोलिए ।

श्री विनोद नारायण झा: (व्यवधान) पहले दरभंगा जिले में रहे समस्तीपुर...

अध्यक्ष : आपलोग क्या चाहते हैं कि मैथिली में ही बोलें ।

श्री विनोद नारायण झा: आप टेल एंड पर नहीं हैं, आप सेंट्रल मिथिला के हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सदन की भावना है ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, आज जो आप ऑडर पेपर वितरित करते हैं क्रम पत्रक, मैं उसको सुबह-सुबह देख रहा था और मुझे आज शिक्षा विभाग की मांग प्रस्तुत करनी थी । हमने उस क्रम पत्रक में देखा कि इस सदन के दो-तीन वरीय माननीय सदस्यों के द्वारा उसमें कटौती प्रस्ताव पेश करने की सूचना आपको दी गई थी और वह सूचना आपने हमलोगों को दी थी । सच पूछते हैं अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी उम्मीद से इस सदन में आया था कि इतने वरिष्ठ सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है आखिर उनकी रुचि है शिक्षा में तभी कटौती प्रस्ताव की सूचना दी है और कटौती प्रस्ताव की सूचना देने का मकसद भी यही होता है कि शिक्षा विभाग की नीतियों पर चर्चा हो और विशेष रूप से जो माननीय सदस्यों ने हमारे अनुपूरक मांग या शिक्षा विभाग के बजट या शिक्षा विभाग के नीतियों कार्यक्रमों को देखा होगा, जाना होगा, उसमें उनको कुछ कमियां नजर आई होंगी...

(क्रमश:)

टर्न-26/सत्येन्द्र/29-06-22

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री(क्रमशः) कुछ उनको कमी लग रही होगी, कुछ उनको दिक्कत महसूस हुई होगी, चाहे नीतियों में हो या उसके क्रियान्वयन में हो इसीलिए उन्होंने कटौती प्रस्ताव दिया है तो मैं बड़ी ही उम्मीद लेकर यहां आया था महोदय कि जब वे हमारी कमियां गिनायेंगे कि हमसे क्या छूट जा रहा है, हमें कहां अपने को सुधारना है, ये हम समझने की उम्मीद और आस लगाये इस सदन में आये थे लकिन महोदय, यहां का तो नाजारा ही कुछ और है । आपने भी देखा है सुबह में, आपने कहा भी, आपने आसन की तरफ से उनसे अनुरोध भी किया और आपने जो अनुरोध किया, सरकार की तरफ से हमने भी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी अपने साथी विधायकों से अनुरोध किया कि वे सदन में आयें और चर्चा करें क्योंकि विपक्ष के जब माननीय सदस्य नहीं होते हैं तो न सिर्फ सदन अधूरा लगता है बल्कि सरकार भी एक तरह से असहज महसूस करती है क्योंकि वे जब हमारी निन्दा करते हैं आलोचना करते हैं, हम तो महोदय उसमें रास्ता खोजते हैं, हमें तो उससे आगे बढ़ने की सलाह ही मिलती है, वे जब हमारी कमियां निकालते हैं तो हमको उसमें अपने को सुधार करने का अवसर दिखता है । हम उनको चुनौती के रूप में उनके सुझावों को लेकर हम अमलीजामा पहनाने की कोशिश करते हैं लेकिन महोदय यहां आने पर जो दृश्य है, आप ही देखिये, ये सुनापन ये विरापन, वह भी शिक्षा विभाग के बजट के दिन में, आखिर महोदय अगर संवेदनशीलता है तो शिक्षा से है, कोई दूसरे विभाग से विकास के अनेक आयाम होते हैं, सड़क, बिजली, पानी कई तरह के विकासत्मक कार्य होते हैं, किसी से आप दूरी भले बना लीजिये लेकिन आज हमारे साथी सदस्यों ने महोदय जो शिक्षा से दूरी बनायी है, इसका जिक्र हमारे शाहनवाज जी भी कर रहे थे कि आखिर शिक्षा से कोई दूरी क्यों बनायेगा, आखिर किसी चीज से आप दूरी बना लीजिये तो आप निकल सकते हैं लेकिन महोदय, यह स्थापित बात है हर दृष्टिकोण से कि जिसने भी शिक्षा से दूरी बनायी है वह कभी सफल नहीं हो सका है । यह सब के सामने प्रमाणित बात है महोदय, हम आपके माध्यम से सदन को भी इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं कि हमलोग जो मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ काम करने वाले लोग हैं, चाहे हम मंत्रीगण हैं या हमारे साथी विधायकगण हैं, हमलोग थोड़ा दूसरे किस्म के मिजाज वाले हैं, हम कभी आलोचना से घबराते नहीं है, हम कभी अपनी निन्दा को नाकारात्मक रूप में महोदय नहीं देखते हैं और हमको तो महोदय आज यहां आपने इतनी कबिता, शेरों शायरी का माहौल बना

दिया कि आज जब हम इधर सुनापन देखते हैं तो बड़ा दिल में कश महसूस होता है कि अगर वे होतें तो कितना अच्छा होता । अरे हम तो उनको नजदीक रखना चाहते हैं, महोदय आपको भी शायद याद होगा जब हमलोग स्कूल में पढ़ते थे तो हिन्दी साहित्य की पुस्तक में एक छोटी किताब पद्य संग्रह आती थी और उसमें दोहे और कबिताएं हुआ करती थीं, उसमें एक था कबीरदास के दोहे और कबीरदास के जो दोहे होते थे बड़े नीति परक और प्रेरणादायी दोहे उसमें हुआ करते थे, हमने तो उसी में पढ़ा था और वही जो नीतीश कुमार जी के साथ काम करने वाले हमलोग हैं, हमलोग आज भी कबीर के उन्हीं बचनों में विश्वास करते हैं कि ''निन्दक नियरे राखिये, आंगन कुटी छबाये, बिन पानी साबुन बिना निर्बल करे सुहाय ।'' महोदय, हम तो उम्मीद में सदन में आये थे कि आज हमारे निन्दक हमारी आलोचना करने वाले हैं । अगर आज वे हमारे नजदीक होते, हमारी आलोचना करते तो आखिर हमें भी अपने को निर्मल बनाने का, अपने को सुधारने का, अपने को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता लेकिन पता नहीं हमारे साथियों ने हम सबों को एक बड़ा मलाल दिया है कि वे अपने सारे सुझावों को अपने साथ लेकर, सदन से बाहर जाकर जो शिक्षा से उन्होंने दूरी बना ली है हम नहीं समझते हैं कि इससे प्रदेश की शिक्षा का भला होने वाला है और न जिन्होंने शिक्षा से दूरी बनायी है उनका भला होने वाला है । महोदय, आज जहां तक शिक्षा की बात है इससे जुड़ा कि मैं सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करूं, हमारे बहुत सारे साथियों ने सच पूछिये तो इतनी सारी उपलब्धियों की चर्चा कर दी है कि दोहराने की मैं आवश्यकता भी नहीं महसूस करता हूँ । आप सबने देखा है महोदय कि सबसे अधिक बजट शिक्षा का है और आपने देखा होगा, अभी मार्च महीने में हमने जब मूल बजट पेश किया था तो वह लगभग 391 अरब रू0 का था और आज हमने प्रथम अनुपूरक लगभग 120 अरब रू0 का दिया है । आज शिक्षा का बजट इतना बढ़ा हुआ है, 20 प्रतिशत या उससे भी अधिक बजट है तो ये साबित करता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वह शिक्षा के प्रति कितना समर्पित है और यह सरकार बिहार के लोगों को कितना शिक्षित बनाने में यकीन रखती है । महोदय, एक चीज और विचार करने की है कि आज शिक्षा का मकसद या शिक्षा का प्रभावक्षेत्र या शिक्षा के महत्व का आकलन बदल गया है क्योंकि आज से चार पांच दशक पहले शिक्षा एक अनुत्पादक क्रिया मानी जाती थी तथा उत्पादक क्रियाओं में जो विकास योजनाएं होती है जो आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, वह मुख्य रूप में आर्थिक योजनाओं में मानी जाती थी इसे तो सामाजिक क्षेत्र की कल्याणकारी योजनाओं के श्रेणी में रखा गया था और शिक्षा का

जो बजट आता था उसमें था कि समाज का कल्याण करना है इसलिए शिक्षा देनी है और असली विकास तो कोई दूसरी चीज है । महोदय, हमको लगता है आज आखिर शिक्षा में जो आकर्षण है, शिक्षा में जो खिंचाव है वह हमारे साथी अखतरूल इस्लाम जी को सदन में ले आया, इनका हम स्वागत हैं और महोदय आज शिक्षा में चाहे कितनी बड़ी समस्या हो, इस देश की या विश्व की सारी समस्याओं का निदान शिक्षा में देखा जाता है, चाहे वह आर्थिक विकास हो, सामाजिक सदभाव हो, चाहे ऊर्जा का संकट हो, चाहे जलवायु परिवर्तन का संकट हो, जो भी हो पर्यावरणीय सुरक्षा हो, सभी समस्याओं का समाधान महोदय, आज शिक्षा में ही देखा जाने लगा है इसलिए शिक्षा के बजट का इतना बड़ा आकार है और आज शिक्षा में जो खर्च होता है महोदय, उसे आर्थिक भाषा में निवेश कहा जाता है और निवेश का अर्थ सारा सदन समझता है कि ये खर्च सिर्फ सीधे खर्च नहीं होता है बल्कि इससे कुछ फायदा होता है (क्रमशः)

टर्न–27/मधुप/29.06.2022

...क्रमशः..

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : जो पूँजीगत संसाधन किसी लाभ के लिए अगर 5 रूपया लगाते हैं और उससे 7 रूपया आता है तो वह निवेश कहलाता है । आज शिक्षा में जो हम बजट डालते हैं वह खर्च नहीं निवेश होता है । आज दुनिया भर के अर्थशास्त्री इसी शोध में लगे हैं और इसी का क्या परिणाम निकलता है इसके बारे में पूरी पड़ताल कर रहे हैं ।

महोदय, हम सभी बिहारवासी इस मायने में भाग्यशाली हैं कि हमलोगों की सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमने बताया कि बजट का सबसे अधिक प्रतिशत शिक्षा में लगाकर आज हम बिहारवासियों को शिक्षित बनाकर अपने शिक्षा के क्षेत्र में पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हैं । हम यह बिहार के लोगों को बताना चाहते हैं ।

महोदय, अलग–अलग क्षेत्र की बात करें, शिक्षा की उपलब्धियों की चर्चा हमारे बहुत सारे साथियों ने की है, अगर प्रारंभिक शिक्षा से ही शुरू करें । हमारे साथियों ने कहा है, अगर हमारे विद्यालयों में, हमारे शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं इसलिये हमलोगों की

सरकार ने प्राथमिकता से एक अभियान चलाकर कि जितनी भी रिक्तियॉं हैं, वह रिक्तियॉं भरने का हम अभियान चला रहे हैं । महोदय, कहीं-कहीं जिस गति से हम चलना चाहते हैं या जिस गति से चलने की मुख्यमंत्री जी की इच्छा रहती है कि जल्दी चलिये, जल्दी करिये, बहाली करिये, उस गति से हम नहीं चल पाते हैं। कभी न्यायालयीय हस्तक्षेप होता है, कभी अन्य कारण होते हैं, पिछले दो वर्ष से खास तौर से यह सरकार जब से बनी है हमलोग कोरोना से ही आक्रांत रहे हैं, हमारे शिक्षण संस्थान बंद रहे हैं । लेकिन आज इसके बावजूद हमें खुशी है कि जो छठे चरण की नियुक्तियॉं चल रही हैं उसमें लगभग 42 हजार से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हम कर चुके और उनको हम नियुक्ति पत्र दे चुके और इसी चरण का जो शेष अभी चल रहा है उसमें लगभग 2.5-3 हजार और हम नियुक्ति कर लेंगे, एक सप्ताह से 10-15 दिनों के अंदर वह क्रिया हम पूरी करने वाले हैं ।

इसी तरीके से जो शिक्षा की गुणवत्ता में हमलोगों ने बढ़ोतरी करने का अपनी योजना बनायी है उसके तहत राज्य में पहली बार, चाहे हमारा प्रारंभिक विद्यालय हो या हमारे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय हों, अब तो लगभग सभी माध्यमिक विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय बन गये हैं । महोदय, पहली बार प्रारंभिक विद्यालयों में 40 हजार से अधिक, जो प्रधान शिक्षक होते हैं यानी हेडमास्टर होते हैं उनके पदों का सृजन किया जा चुका है और इन पदों पर नियुक्तियॉं हम बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से करने जा रहे हैं । पहली दफा योग्य और क्षमतावान शिक्षकों की नियुक्ति की हम व्यवस्था कर रहे हैं ।

महोदय, इसी तरह जो हमारे +2 इंटर विद्यालय हैं उसमें करीब 5300 से अधिक जो प्रधानाध्यापक होते हैं, उनके पद का हमलोगों ने सृजन किया है और उन पदों पर भी सीधी भर्त्ती के लिए हमलोगों ने बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा है, वह सम्पन्न हो चुकी है और कुछ ही दिनों बाद बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त जो प्रधानाध्यापक होंगे वे हमारे सभी पंचायत के +2 विद्यालय में जायेंगे । वह तो बात अब पुरानी हो चुकी, हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने चर्चा की है कि कितनी बड़ी क्रांतिकारी योजना है शिक्षा विभाग की जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोग उसको मंजिल तक पहुँचा रहे हैं । हर पंचायत में एक +2 उच्च विद्यालय । मैं जहॉं कहीं भी दूसरे प्रदेश के लोगों से बात करता हूँ सभी अचंभित होते हैं और महोदय, यह

ऐतिहासिक कदम था जब 5 हजार से अधिक मध्य विद्यालयों का हमलोगों ने उच्च माध्यमिक विद्यालय में सीधे उत्क्रमण कर दिया, यह एक ऐतिहासिक कदम था और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आज बिहार प्रदेश के हर पंचायत में एक +2 विद्यालय कार्यरत है और गॉव में, सुदूर देहात में रहने वाले गरीब घर के भी बच्चे-बच्चियॉ उन +2 विद्यालयों में पढ़ रहे हैं । महोदय, प्रश्न भी आते हैं, हमसे माननीय सदस्यगण मिलते भी रहते हैं और इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि जितने भी ये 5.5 हजार से अधिक जो +2 विद्यालयों का हमलोगों ने उत्क्रमण किया है, वहॉ अभी भवन का अभाव है, वहॉ अभी शिक्षकों की कमी है, यह हम स्वीकारते हैं लेकिन हमने मुकम्मल कार्य योजना बना ली है और आने वाले समय में हम बहुत जल्द पूरा करना चाहते हैं ।

महोदय, जैसा कि अभी हमने कहा कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया हमलोग पूरी कर चुके हैं । 4-5 दिनों में हमलोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे थे, इसी बीच न्यायालय का हस्तक्षेप आया, एक 17/19 बैच के लोगों को उसमें शामिल कराने का मामला था, हमने कहा कि हम उनको शामिल करा लेंगे अगली बार में, अगले चरण में, अगर किन्हीं की उम्रसीमा पार हो रही होगी तो उनको वह भी हम क्षांत कर देंगे लेकिन हमें नियुक्तियॉ करने दीजिए क्योंकि हमारे विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई बाधित हो रही है, इधर हमारे योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार घूम रहे हैं । यह स्थिति सरकार के लिए बहुत दुखदायी स्थिति है । हमने न्यायालय से प्रार्थना की, हमने कहा कि हमको आप इजाजत दीजिये हम नियुक्ति कर लेते हैं, आगे जिनको आप कहियेगा हमलोग इजाजत देंगे लेकिन महोदय, इजाजत नहीं मिली तो हमलोगों को शेड्युल रिवाइज करना पड़ा, उसको आगे बढ़ाना पड़ा । लेकिन महोदय, हमलोगों ने भी तुरंत तत्क्षण उसको फिर से पुनरीक्षित करके अभी नया शेड्युल जारी कर दिया है और जुलाई माह के खतम होते-होते हमलोग 30 हजार शिक्षकों की नियुक्ति, सोच लीजिये 5 हजार विद्यालय हैं 30 हजार हम नियुक्तियॉ करेंगे जिसमें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों के हैं, लगभग 19 हजार और 11 हजार, लगभग 5-6 औसतन शिक्षक हम सभी विद्यालयों में उपलब्ध करायेंगे । महोदय, जहॉ तक भवनों की कमी है, हमें बताते हुए अपार प्रसन्नता हो रही है कि यह मुख्यमंत्री जी का जिसको कहते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हर पंचायत में +2 विद्यालय हो, इसमें भवनों की दिक्कत नहीं हो इसलिये मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निदेश आया कि चाहे इसमें जो राशि लगे इसको प्राथमिकता से कराइये और मुझे आज बताते हुये प्रसन्नता हो

रही है कि लगभग 7.5 हजार करोड़ की योजना सिर्फ उत्क्रमित उच्च विद्यालय में जहॉ पर भवनों की कमी है, दो साल के अन्दर हमलोग सभी विद्यालयों में जो भवन की कमी हो रही है, वह हम पूरा करा देंगे ।

अब बताइये कि हम शिक्षक उपलब्ध करा देंगे, भवन बना देंगे, अब सोचिये जब हमारे गॉव की बेटियों को पढ़ने के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, अब अपने ही गॉव में, अपने ही पंचायत में वह +2 तक पढ़ेगी । महोदय, याद होगा जब हम-आप पढ़ते थे तो उसको प्री-यूनिवर्सिटी कहते थे जो एक तरह से वह यूनिवर्सिटी का पार्ट होता था जो आजकल 12 कहते हैं तो मतलब आधे शुरूआती कॉलेज स्तर की पढ़ाई अब गॉव में होने जा रही है, हर पंचायत में होने जा रही है, यह कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात है । ..

क्रमशः...

टर्न-28/आजाद/29.06.2022

..... क्रमशः .....

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : इसी तरीके से जो हमारे शारीरिक शिक्षक थे, वो भी बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे । हमने उनकी पात्रता परीक्षा काफी पहले ले ली थी और वे उसमें उत्तीर्ण होकर बैठे थे । उसमें भी कुछ न्यायालय के तरफ से बाधायें आ गई थी लेकिन उसको हमलोगों ने दूर कर दिया है । 8386 मतलब 8386 पद शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का हमलोगों ने स्वीकृत कर दिया है और हरेक मध्य विद्यालयों में एक-एक शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नियुक्त करने जा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है और लगभग 1500 से अधिक नियुक्त भी हो गये हैं, बाकी की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है । महोदय, बहुत सारे लोग हमसे भी मिलते रहते हैं । उनको भी हमने कहा है कि भाई जो अगर कम पड़ता है क्योंकि अभी लगभग 8000 से अधिक रिक्तियां हैं और जो इन लोगों की पात्रता परीक्षा हुई थी, उसमें ये लोग लगभग 3500 ही उत्तीर्ण हो पाये थे तो 5000 से अधिक वैकेंसी रहेगी । हमने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से बात की है क्योंकि हमारे पद सृजित हैं और हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं होंगे तो हमलोग जल्द ही उनके लिए जो हमारे छात्र प्रतीक्षारत हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि हम उनके लिए शीघ्र ही पात्रता परीक्षा भी आयोजित करेंगे और लगभग 5000 वैकेंसी है, हम समझते हैं कि हमारे प्रदेश में शारीरिक शिक्षा के प्रशिक्षण प्राप्त किये योग्य अभ्यर्थी होंगे,

उनके लिए हमलोग तुरंत व्यवस्था करने जा रहे हैं । महोदय, इसके अलावा हमलोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है विश्वविद्यालय में भी । आज महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस प्रदेश के हर प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय है, हर जिले में पी0जी0 की पढ़ाई प्रारंभ करने की योजना बन चुकी है और हर अनुमंडल में कम से कम एक डिग्री महाविद्यालय है, जो हमारे बहुत सारे साथी यहां पर प्रश्न करते रहते हैं, यह हमलोगों ने हरेक अनुमंडल में जो 101 अनुमंडल है, उन सबमें हम कम से कम एक डिग्री महाविद्यालय खोलेंगे, जहां नहीं हैं, लगभग 18 चिन्हित हुए थे, उसमें 7-8-9 में तो हो गया है, कुछ जगह भूमि चिन्हित हो गई है । हमलोग उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं । महोदय, हमलोगों की जो एच0एस0ई0सी0 है, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद् । कभी-कभी हमलोग देख रहे थे कि अपने मुस्तैदी नहीं होने के कारण हमलोग नैक के एक्रेडिटेशन में हमारे शिक्षण संस्थान पिछड़ जाते थे, उनकी अलग से मॉनिटरिंग के लिए अनुश्रवण के लिए हमलोगों ने व्यवस्था की है और हमलोगों ने जो किया है, इसका परिणाम भी महोदय सामने आने लगा है । जी0आर0 सकल नामांकन अनुपात जो हमारा 13-14 प्रतिशत हुआ करता था, इसके बारे में मुख्यमंत्री जी बराबर कहा करते थे कि हमको इसको और आगे बढ़ाना है । मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वह लगभग 20 से अधिक पहुँच चुका है और इसको आगे ले जाना चाहते हैं ।

महोदय, मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमने मदरसों के संबंध में जो मदरसा एक्ट 1981 में बना लेकिन उस एक्ट में जो प्रावधान था कि इसके क्रियान्वयन के लिए नियमावली बनायी जायेगी, वह आज तक नहीं बना था । 41 वर्षों के बाद यह श्रेय श्री नीतीश कुमार की सरकार को जाता है कि हमलोगों ने उस संदर्भ में तीन नियमावली बनायी है, जिसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है । महोदय, आज ही आपके इजाजत से आपने तीनों नियमावलियों की प्रति हमारे माध्यम से सदन के मेज पर यहां रखवाया है, वो सारे सदस्यों को मिल जायेगा, उसको देख लीजिए । महोदय, इस संबंध में एक बात और हम स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि इन नियमावलियों के बारे में लोगों में बहुत तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं । हमने सार्वजनिक रूप से सभी मदरसों से जुड़े संगठनों एवं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को खुला आमंत्रण दिया है कि इसमें जहां कोई आपको दिक्कत महसूस हो क्योंकि हमने किसी का अधिकार लिया नहीं है, हमने उनके अधिकार को केवल पूरी तरीके से सुव्यवस्थित कर दिया है, जिससे कि उन मदरसों का

संचालन सुव्यवस्थित हो और उसमें अधिक से अधिक योग्य शिक्षक नियुक्त हो सकें, हमलोगों ने सिर्फ ऐसी व्यवस्था की है । मैं बिहार के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो भी मदरसा से जुड़े हैं, जो भी मदरसा के बारे में जानते हैं कि अगर कहीं कोई आपको दिक्कत नजर आये, आप आइए, हम सरकार की तरफ से खुले मन से स्वागत करते हैं और जहां कहीं भी सही कठिनाई होगी, उसको दूर करने के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और न हमारे लिए कोई .....

अध्यक्ष : अब संक्षिप्त कर दीजिए ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, अब हम यही कहेंगे कि अब हमारे बाकी बातें जो है, इसमें ले ली जाय

अध्यक्ष : प्रोसीडिंग का पार्ट बन जायेगा ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हम पूरे सदन से आग्रह करेंगे कि जो आज हमने मांग प्रस्तुत की है, जिसपर सारे सदस्यों ने इतने देर विमर्श किया है, उसको सारा सदन सर्वसम्मति से स्वीकृति दे दे, इसी अनुरोध के साथ बहुत धन्यवाद ।

(माननीय मंत्री का शेष वक्तव्य -परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''शिक्षा विभाग'' के संबंध में प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 के उपबन्ध के अतिरिक्त 12013,86,33,000/- (बारह हजार तेरह करोड़ छियासी लाख तैंतीस हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय । ''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

माननीय सदस्यगण, अब शेष अनुदानों की मांग गिलोटिन के माध्यम से ली जायेगी ।

टर्न-29/शंभु/29.06.22

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की माँगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए बिहार विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2022 द्वारा स्वीकृत राशि के अतिरिक्त :-

माँग संख्या-01 कृषि विभाग के संबंध में 425,30,00,000/-
(चार सौ पच्चीस करोड़ तीस लाख) रूपये

माँग संख्या-02 पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के संबंध में 161,76,11,000/-
(एक सौ इकसठ करोड़ छिहत्तर लाख ग्यारह हजार) रूपये

माँग संख्या-03 भवन निर्माण विभाग के संबंध में 137,09,38,000/-
(एक सौ सैंतीस करोड़ नौ लाख अड़तीस हजार) रूपये

माँग संख्या-04 मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के संबंध में 175,00,00,000/-
(एक सौ पचहत्तर करोड़) रूपये

माँग संख्या-06 निर्वाचन विभाग के संबंध में 6,50,00,000/-
(छः करोड़ पचास लाख) रूपये

माँग संख्या-08 कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के संबंध में 50,02,000/-
(पचास लाख दो हजार) रूपये

माँग संख्या-09 सहकारिता विभाग के संबंध में 11,50,000/-
(ग्यारह लाख पचास हजार) रूपये

माँग संख्या-10 ऊर्जा विभाग के संबंध में 3682,21,31,000/-

(तीन हजार छः सौ बयासी करोड़ इक्कीस लाख इक्तीस हजार) रूपये

माँग संख्या–11 पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के संबंध में 127,23,00,000/– (एक सौ सत्ताईस करोड़ तेईस लाख) रूपये

माँग संख्या–12 वित्त विभाग के संबंध में 9354,61,00,000/–
(नौ हजार तीन सौ चौवन करोड़ इक्सठ लाख) रूपये

माँग संख्या–15 पेंशन के संबंध में 79,63,97,000/–
(उनासी करोड़ तिरेसठ लाख सत्तानवे हजार) रूपये

माँग संख्या–16 पंचायती राज विभाग के संबंध में 3613,01,69,000/–
(तीन हजार छः सौ तेरह करोड़ एक लाख उनहत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या–17 वाणिज्य–कर विभाग के संबंध में 1,000/–
(एक हजार) रूपये

माँग संख्या–18 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के संबंध में 1216,57,03,000/–
(एक हजार दो सौ सोलह करोड़ सत्तावन लाख तीन हजार) रूपये

माँग संख्या–19 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संबंध में 62,83,95,000/–
(बासठ करोड़ तिरासी लाख पंचानवे हजार) रूपये

माँग संख्या–20 स्वास्थ्य विभाग के संबंध में 2414,99,86,000/–
(दो हजार चार सौ चौदह करोड़ निन्यानवे लाख छियासी हजार) रूपये

माँग संख्या–22 गृह विभाग के संबंध में 640,50,09,000/–
(छः सौ चालीस करोड़ पचास लाख नौ हजार) रूपये

माँग संख्या–23 उद्योग विभाग के संबंध में 100,22,01,000/–
(एक सौ करोड़ बाईस लाख एक हजार) रूपये

माँग संख्या–26 श्रम संसाधन विभाग के संबंध में 53,70,000/–
(तिरपन लाख सत्तर हजार) रूपये

माँग संख्या–27 विधि विभाग के संबंध में 59,90,43,000/–
(उनसठ करोड़ नब्बे लाख तैंतालीस हजार) रूपये

माँग संख्या–32 विधान मंडल के संबंध में 1,05,00,000/–
(एक करोड़ पाच लाख) रूपये

माँग संख्या–33 सामान्य प्रशासन विभाग के संबंध में 500,18,00,000/–
(पांच सौ करोड़ अठ्ठारह लाख) रूपये

माँग संख्या–35 योजना एवं विकास विभाग के संबंध में 48,47,34,000/–
(अड़तालीस करोड़ सैंतालीस लाख चौंतीस हजार) रूपये

माँग संख्या–36 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के संबंध में 1,000/–
(एक हजार) रूपये

माँग संख्या–37 ग्रामीण कार्य विभाग के संबंध में 1400,00,01,000/–
(चौदह सौ करोड़ एक हजार) रूपये

माँग संख्या–38 मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के संबंध में 118,28,01,000/–
(एक सौ अठ्ठारह करोड़ अठ्ठाईस लाख एक हजार) रूपये

माँग संख्या–39 आपदा प्रबंधन विभाग के संबंध में 426,45,01,000/–
(चार सौ छब्बीस करोड़ पैंतालीस लाख एक हजार) रूपये

माँग संख्या–40 राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संबंध में 70,22,61,000/–
(सत्तर करोड़ बाईस लाख इकसठ हजार) रूपये

माँग संख्या–41 पथ निर्माण विभाग के संबंध में 1000,00,00,000/–
(एक हजार करोड़) रूपये

माँग संख्या–42 ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 1796,34,00,000/–
(एक हजार सात सौ छियान्वे करोड़ चौंतीस लाख) रूपये

माँग संख्या–43 विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संबंध में 5,18,00,000/–
(पाँच करोड़ अठ्ठारह लाख) रूपये

माँग संख्या–44 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के संबंध में 316,40,33,000/– (तीन सौ सोलह करोड़ चालीस लाख तैंतीस हजार) रूपये

माँग संख्या–45 गन्ना उद्योग विभाग के संबंध में 29,11,000/–
(उन्तीस लाख ग्यारह हजार) रूपये

माँग संख्या–46 पर्यटन विभाग के संबंध में 49,00,000/–
(उनचास लाख) रूपये

माँग संख्या–48 नगर विकास एवं आवास विभाग के संबंध में 250,29,51,000/–
(दो सौ पचास करोड़ उन्तीस लाख इक्यावन हजार) रूपये

माँग संख्या–49 जल संसाधन विभाग के संबंध में 218,13,50,000/–
(दो सौ अठ्ठारह करोड़ तेरह लाख पचास हजार) रूपये

माँग संख्या–50 लघु जल संसाधन विभाग के संबंध में 11,00,000/–
(ग्यारह लाख) रूपये

माँग संख्या–51 समाज कल्याण विभाग के संबंध में 3350,31,32,000/–
(तीन हजार तीन सौ पचास करोड़ इक्तीस लाख बत्तीस हजार) रूपये

से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभी माँगें स्वीकृत हुईं ।

माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य लिये जायेंगे ।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय)विधेयक

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022''

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग ।

श्री तारकिशोर प्रसाद,उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गयी ।

प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद,उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुर:स्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : यह पुर:स्थापित हुआ ।

विचार का प्रस्ताव, प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 पर विचार हो ।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022'' पर विचार हो ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खंडश: लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''खंड-1 इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''नाम इस विधेयक का अंग बने ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-30/पुलकित/29.06.2022

<u>स्वीकृति का प्रस्ताव</u>

अध्यक्ष : प्रभारी मंत्री ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2022-23 का प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी बिहार विधान मंडल में दिनांक 24 जून, 2022 को प्रस्तावित किया गया । प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में 43775,23,15,000 (तैंतालीस हजार सात सौ पचहत्तर करोड़ तेईस लाख पंद्रह हजार) रुपये की राशि प्रस्तावित की गयी है । प्रस्तावित राशि में वार्षिक स्कीम मद में 25765,97,89,000 (पच्चीस हजार सात सौ पैंसठ करोड़, सत्तानवे लाख, नवासी हजार) रुपये स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रवृत्त सहित 17954,74,28,000 (सत्रह हजार नौ सौ चौवन करोड़, चौहत्तर लाख, अठाइस हजार) रुपये एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद में 54,50,58,000 (चौवन करोड़ पचास लाख अठानवे हजार) रुपये प्रस्तावित है । कुल प्रस्तावित राशि भी बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत 1335,76,12,000 (एक

हजार तीन सौ पैंतीस करोड़, छिहत्तर लाख बारह हजार) रुपये की प्रतिपूर्ति शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, वार्षिक स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तथा राज्य स्कीम को शामिल किया जाता है । वार्षिक स्कीम मद में 25765,97,89,000 (पच्चीस हजार सात सौ पैंसठ करोड़ सत्तानवे लाख नवासी हजार) रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है । इस वार्षिक स्कीम मद में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में 1763,15,47,000 (एक हजार सात सौ तिरसठ करोड़ पन्द्रह लाख सैंतालीस हजार) रुपये, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश मद में 17577,17,51,000 (सत्रह हजार पांच सौ सत्तर करोड़ सत्रह लाख इक्याबन हजार) रुपये एवं राज्य स्कीम मद में 6425,64,91,000 (छह हजार चार सौ पच्चीस करोड़ चौसठ लाख इक्यानबे हजार) रुपये, कुल 25765,97,89,000 (पच्चीस हजार सात सौ पैंसठ करोड़ सत्तानवे लाख नवासी हजार) रुपये प्रस्तावित है । केन्द्र सरकार के पूर्ण सहयोग के कारण केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश मद में अतिरिक्त राशि का प्रस्ताव है । प्रस्तावित राशि में मुख्यत: केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान प्रारंभिक अंतर्गत 9440,00,00,000 (नौ हजार चार सौ चालीस करोड़) रुपये, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 1796,34,00,000 (एक हजार सात सौ छियानवे करोड़ चौंतीस लाख) रुपये, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य परिवार कार्यक्रम अंतर्गत 1584,88,00,000 (एक हजार पांच सौ चौरासी करोड़ अठासी लाख) रुपये, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1400,00,00,000 (एक हजार चार सौ करोड़) रुपये का प्रस्ताव शामिल है ।

अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केन्द्रांश मद में मुख्यत: ऊर्जा प्रक्षेत्र के, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत 489,93,00,000 (चार सौ नवासी करोड़ तिरानवे लाख) रुपये, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण एवं आत्मनिर्भर भारत योजना मद में 450,00,00,000 (चार सौ पचास करोड़) रुपये का प्रस्ताव शामिल है । अध्यक्ष महोदय, राज्य द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के साथ-साथ राज्य की स्कीम पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है । राज्य स्कीम मद में 6425,64,91,000 (छह हजार चार सौ पच्चीस करोड़ चौसठ लाख इक्यानबे हजार) रुपये का प्रस्ताव है । राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक प्रक्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार किये जा रहे हैं जिसके क्रियान्वयन के लिए औद्यागिक प्रोत्साहन निधि हेतु कुल 100,00,00,000 (एक सौ करोड़) रुपये का प्रस्ताव शामिल है । राज्य सरकार द्वारा पूंजीगत निर्माण कार्यों को प्राथमिकता देते हुए भू-अर्जन हेतु कुल 1892,00,00,000 (एक हजार

आठ सौ बानवे करोड़) रुपये का प्रस्ताव है । जिसमें सड़क प्रक्षेत्र में भू-अर्जन हेतु 900,00,00,000 (नौ सौ करोड़) रुपये, थाना ओ0पी0 के लिए भू-अर्जन हेतु 460,00,00,000 (चार सौ साठ करोड़) रुपये, पटना मेट्रो रेल परियोजना में भू-अर्जन हेतु 250,00,00,000 (दो सौ पचास करोड़) रुपये, बिहार भवन मुम्बई के लिए भू-अर्जन हेतु 175,00,00,000 (एक सौ पचहत्तर करोड़) रुपये, कुल प्रक्षेत्र में भू-अर्जन हेतु 100,00,00,000 (एक सौ करोड़) रुपये तथा सिंचाई सृजन परियोजनाओं कार्यों में भू-अर्जन हेतु 7,00,00,000 (सात करोड़) रुपये का प्रस्ताव शामिल है । इसके अतिरिक्त अन्य राज्य स्कीम यथा मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना हेतु 925,00,00,000 (नौ सौ पच्चीस करोड़) रुपये, मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडियेट प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 912,50,00,000 (नौ सौ बारह करोड़ पचास लाख) रुपये का प्रस्ताव शामिल है । अध्यक्ष महोदय, स्थापना, प्रतिबद्ध व्यय मद में मुख्य प्रस्ताव षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं के लिए 3613,02,00,000 (तीन हजार छह सौ तेरह करोड़ दो लाख) रुपये, ए0टी0 एण्ड सी0 लॉस के मद में वितरण कम्पनियों के घाटे की भरपाई हेतु 3183,00,000 (तीन हजार एक सौ तिरासी करोड़) रुपये, कोविड-19 उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 583,43,00,000 (पांच सौ तिरासी करोड़ तैंतालीस लाख) रुपये एवं बिहार जातीय आधारित गणना हेतु 500,00,00,000 (पांच सौ करोड़) रुपये का प्रस्ताव है । अध्यक्ष महोदय, बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 द्वारा कुल 43775,23,15,000 (तैंतालीस हजार सात सौ पचहत्तर करोड़ तेईस लाख पंद्रह हजार) रुपये की राशि समेकित निधि से विनियोजन किया जाना प्रस्तावित है । प्रथम अनुपूरक में राशि उपबंधित करने संबंधी प्रस्ताव एवं बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 का संक्षिप्त विवरण माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अतः सदन से अनुरोध है कि प्रथम अनुपूरक से संबंधित बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 में अपनी सहमति व्यक्त करते हुए इसे ध्वनिमत से पारित किया जायें ताकि राज्य का विकास निर्बाध गति से चलता रहे । जय हिन्द, जय बिहार ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 स्वीकृत हो ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2022 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 29 जून, 2022 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या- 64 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक वृहस्पतिवार, दिनांक 30 जून, 2022 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है ।

परिशिष्ट

शिक्षा विभाग

वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम तीन माह अन्तर्गत विभाग की उपलब्धि

प्राथमिक शिक्षा

- विभाग द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 90,762 विज्ञापित पदों के विरूद्ध 42,000 (बयालीस हजार) शिक्षकों की नियुक्ति की गई। शेष नियोजन इकाईयों द्वारा जुलाई, 2022 के प्रथम सप्ताह में काउंसेलिंग के आधार पर नियुक्ति हेतु समय निर्धारित किया गया है।
- राज्य के मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक के नवसृजित 8,386 (आठ हजार तीन सौ छियासी) पद के विरूद्ध अबतक 1,500 (एक हजार पांच सौ) अनुदेशक की नियुक्ति की गई है। शेष नियोजन इकाईयों द्वारा दिनांक–24.06.2022 को काउंसेलिंग करते हुए शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया गया है, जिसमें रिक्ति के अनुसार दिनांक–02.07.2022 से दिनांक–09.07.2022 की अवधि में नियुक्ति पत्र चयनित अभ्यर्थियों को दिया जायेगा। शेष सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थियों की प्रतीक्षक सूची (waiting list) प्रकाशित की जायेगी। उक्त प्रतीक्षक सूची से रिक्ति के आधार पर मेधा क्रम से नियुक्ति पत्र दिया जायेगा।
- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु राज्य सरकार के मद (GOB) से कुल ₹29,24,06,93,000/– (उनतीस अरब चौबीस करोड़ छः लाख तिरानवे हजार रूपये) एवं समग्र शिक्षा अभियान मद (SSA) से ₹37,94,90,77,100/– (सैतीस अरब चौरानवे करोड़ नब्बे लाख सतहत्तर हजार एक सौ रूपये) जिला को आवंटित करते हुए उपलब्ध करा दिया गया है।
- राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 छात्र/छात्राओं को मुख्यमंत्री पोशाक योजनान्तर्गत पोशाक हेतु नकद राशि उनके बैंक खाते में दिया जाता है। इसके अलावा सभी छात्र/छात्राओं को छात्रवृति के रूप में नकद राशि उनके बैंक खाता में दिया जाता है।

माध्यमिक शिक्षा

- विभाग द्वारा राज्य के सभी माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाने संबंधी निर्णय के आलोक में सत्र 2022–24 के लिए 4,361 उत्क्रमित एवं नवस्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में +2 (इण्टर) की पढ़ाई आरंभ करने हेतु कोड आवंटित किए जा चुके हैं।

- कक्षा 9 में प्रवेश के लिए 1 जुलाई से 15 जुलाई, 2022 तक प्रवेशोत्सव अभियान चलाया जायेगा, जिसमें कक्षा 8 उत्तीर्ण करने वाले सभी बच्चों जिनका नामांकन कक्षा 9 में नहीं हुआ हो, उनका नामांकन सुनिश्चित किया जायेगा।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षक नियुक्ति हेतु कार्यक्रम 30 जुलाई, 2022 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

राज्य के 50 अनुकरणीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान, पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की जा रही है।

- विभिन्न लाभुक आधारित योजनाओं के तहत डी0बी0टी0 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2021–22 में 4,92,88,318 (चार करोड़ बयानवे लाख अठासी हजार तीन सौ अठारह) लाभुकों के बीच ₹44,61,39,91,050/– (चौवालीस अरब इकसठ करोड़ उनचालीस लाख इकानवे हजार पचास रूपये) वितरित किया गया है।
- राज्य के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के वेतन भुगतान हेतु कुल ₹23,40,64,59,813/– (तेइस अरब चालीस करोड़ चौसठ लाख उनसठ हजार आठ सौ तेरह रूपये) जिला को आवंटित किया गया।
- उच्च माध्यमिक विद्यालयों में निर्धारित पारिश्रमिक पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2022–23 के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु ₹9,650 लाख जिलों को आवंटित किया गया।
- राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रबंध समिति का गठन 30 जून, 2022 तक किए जाने का निदेश दिया गया है।

उच्च शिक्षा

- विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया को और सुचारू एवं पारदर्शी बनाने के लिए निर्मित संबर्धित **वेतन निर्धारण पोर्टल** को चालू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन से लेकर वेतन निर्धारण तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।
- राज्य में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के विकास मद से पूर्व से स्वीकृत एवं नई योजनाओं हेतु लगभग 60 करोड़ की विकास योजनाएं स्वीकृत कर राशि विमुक्त की गई है।
- ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना में शिक्षकों के 51 पद एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के 22 पद सृजित किये गये हैं।
- सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर स्नातक एवं स्नातकोत्तर के साथ–साथ व्यावसायिक शिक्षा के परीक्षा के सत्रों को

नियमित करने हेतु परीक्षा कैलण्डर बनवा कर दिसम्ब 2022 तक सभी परीक्षा–फल का प्रकाशन करने हेतु प्राप्त किया गया है। वर्ष 2023 से परीक्षा–सत्र नियमित करने का प्रयास किया जा रहा है।

- बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के साथ बैठक कर विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के चल रहे नियोजन को वर्ष 2022 के अंत तक अधिकांश शिक्षकों का नियोजन पूरा करने हेतु निदेश दिया गया है।
- राज्य सरकार ने नीति बनाई है कि प्रत्येक जिला में कम–से–कम एक महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की सुविधा दी जायगी। इस क्रम में सुपौल एवं जमुई जिलों में हाल में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई की सुविधा प्रारंभ की गई है।
- विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति की अधियाचना विश्वविद्यालय से प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

मध्याह्न भोजन (पी०एम०पोषण) योजना

- मध्याह्न भोजन योजना के संचालन में किसी भी स्तर पर साझेदार एवं सहभागी होना एक स्वास्थ्य एवं शिक्षित राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करना है।
- मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत रसोईया–सह–सहायक को प्रतिमाह राशि 1,500/–रू0 की दर से 10 माह का पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसमें 150 रू0 की बढ़ोत्तरी करते हुए दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 1650 रू0 की दर से 10 माह का पारिश्रमिक के रूप में दिया जा रहा है।
- बिहार राज्य के 8,270 विद्यालयों में पोषण वाटिका का निर्माण कराया गया।
- कोविड–19 संक्रमण के फलस्वरूप DBT के माध्यम से विद्यालयों में नामांकित सभी बच्चों के बैंक खाते में राशि उपलब्ध कराया जा रहा है एवं सूखा राशन (चावल) वर्ग I-V तक के सभी बच्चों को 100 ग्राम प्रति छात्र/छात्रा एवं वर्ग I-VIII तक के सभी बच्चों को 150 ग्राम की दर से प्रतिदिन प्रति छात्र/छात्रा या उनके अभिभावक को उपलब्ध कराया गया है।
- दिनांक 28.02.2022 से भौतिक रूप से विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।
- मृत रसोईया–सह–सहायकों को 4,00,000/–रू0 (चार लाख रूपये) की अनुग्रह अनुदान राशि दिया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS Portal) SNA (Singal Nodal Account) के तहत योजना का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर तक किया जा रहा है।

जन शिक्षा

- महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना :– वित्तीय वर्ष 2022–23 में शिक्षा सेवकों द्वारा 3,51,704 महिलाओं को साक्षरता केन्द्र पर नामांकित कर साक्षरता प्रदान किया जा रहा है। साथ ही विद्यालय में 6,35,046 बच्चों को नामांकित करवाया गया तथा 5,26,431 बच्चों को कोचिंग प्रदान किया जा रहा है। वर्त्तमान में कुल–26,767 शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) बिहार में कार्यरत हैं, जिन्हें प्रतिमाह 11,000/– रुपये मानदेय का भुगतान उनके खाते में CFMS के माध्यम से किया जा रहा है।
- पढ़ना–लिखना अभियान (केन्द्र प्रायोजित योजना) :– इस अभियान के अन्तर्गत 4.20 लाख लक्ष्य के विरूद्व 3.30 लाख असाक्षर महिला एवं पुरूष को साक्षरता प्रदान किया गया।
- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम :– यह एक केन्द्रीय पंचवर्षीय योजना है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी असाक्षर महिला एवं पुरूष को बुनियादी साक्षरता प्रदान करने का लक्ष्य 9.40 लाख रखा गया है। केन्द्र से राशि प्राप्ति के पश्चात् कार्यक्रम प्रारंभ की जायेगी।